शर्मा हार्डওয়্যার
SHARMA HARDWARE
Sharma Gali, SJ Road
Athgaon, Guwahati-01
98648-02947

E-Paper : www.goodluckpublications.com, • www.vbslive.in
हिंदी दैनिक
गुवाहाटी, नई दिल्ली, शिमला और जम्मू से एकसाथ प्रकाशित

विकसित भारत समाचार

राष्ट्र निर्माण में प्रयत्नशील

वर्ष : 13 | अंक : 33 | गुवाहाटी | गुरुवार, 3 सितंबर, 2026 | मूल्य : 10 रुपए | पृष्ठ : 8 | VIKSIT BHARAT SAMACHAR | Regd. RNI No. ASSHIN/2014/56526

7,570 निजी घर तबाह, 30 अरब की सड़क संरचना ध्वस्त — पेज 2
सीएम हिमंत विश्व शर्मा का सपना हुआ साकार सिलचर नगर निगम चुनाव ... — पेज 3
ईडी के सबूत साझा करने तक मनी लांड्रिंग मामले में एफआईआर नहीं : अमन अरोड़ा — पेज 5
माया बाउचियर के शतक से इंग्लैंड ने रचा इतिहास, आयरलैंड के खिलाफ छह ... — पेज 7

असम पुलिस में 20 हजार और युवाओं की होगी भर्ती : सीएम

जीरो-वैकेंसी वाली फोर्स बनाने पर डॉ. शर्मा ने दिया जोर

गुवाहाटी। असम सरकार अगले पांच सालों में दो लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने के अपने बड़े वादे के तहत 15,000 से 20,000 और पुलिसकर्मियों की भर्ती करने का लक्ष्य बना रही है। मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने बुधवार को देरगांव में लचित बरफूकन पुलिस अकादमी (एलबीपीए) में पासिंग-आउट परेड को संबोधित करते हुए इस लक्ष्य की घोषणा की। शर्मा ने कहा कि अगले पांच सालों में दो लाख युवाओं की नई भर्ती सुनिश्चित करने के असम सरकार के फैसले के तहत, मुझे यकीन है कि हम तय समय-सीमा के भीतर 15,000 से 20,000 और पुलिसकर्मियों की भर्ती कर पाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य ने पिछले पांच सालों में एक निष्पक्ष और मेरिट-आधारित प्रक्रिया के जरिए लगभग 21,000 पुलिस अधिकारियों और कांस्टेबलों की भर्ती की है, जिससे असम पुलिस एक *युवा-नेतृत्व वाली फोर्स* बन गई है। उन्होंने कहा कि सरकार असम पुलिस को *जीरो-वैकेंसी* वाली फोर्स बनाने की दिशा में भी काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हम असम पुलिस को जीरो-वैकेंसी वाली फोर्स बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, ताकि भर्ती के लिए कोई भी पद खाली न रहे। अपराध नियंत्रण पर शर्मा ने दावा किया कि असम ने काफी तरक्की की है; अपराध दर 2021 में प्रति एक लाख आबादी पर 379 से घटकर जुलाई 2024 में प्रति एक लाख आबादी पर 116 हो गई है। उन्होंने बताया कि दर्ज मामलों की संख्या 1,33,239 से घटकर लगभग 25,000 रह गई है, जबकि चार्ज-शीट की दर बढ़कर 86.85 प्रतिशत और सजा दिलाने की दर (कनविक्शन रेट) लगभग 30 प्रतिशत हो गई है। राज्य में ड्रग्स-विरोधी अभियान का जिक्र करते हुए शर्मा ने कहा कि असम पुलिस ने पिछले पांच सालों में 3,254 करोड़ रुपए की कीमत के नशीले पदार्थ जब्त किए हैं और 26,537 लोगों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा कि ड्रग्स से जुड़े मामलों में सजा दिलाने की दर 57 प्रतिशत तक पहुंच गई है। शर्मा ने कहा कि असम की भौगोलिक स्थिति, जिसमें बांग्लादेश और म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं शामिल हैं, का मतलब है कि राज्य को सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना जारी रखना होगा। उन्होंने महिलाओं के खिलाफ अपराधों के प्रति *जीरो टॉलरेंस* की नीति अपनाने का भी आह्वान किया और पुलिस से बाल विवाह और बहुविवाह के खिलाफ कार्रवाई तेज करने को कहा। मुख्यमंत्री ने फोर्स से बराक वैली, गोलाघाट, शिवसागर, तिनसुकिया और डिब्रूगढ़ में ड्रग्स-विरोधी अभियानों को और तेज करने को भी कहा। पासिंग-आउट परेड 403 पुलिस कर्मियों की ट्रेनिंग पूरी होने का प्रतीक थी। इनमें 32 डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (डीएसपी) शामिल थे, जिन्होंने 52 हफ्ते की फाउंडेशनल -शेष पृष्ठ दो पर

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों के दो दिवसीय सम्मेलन का सीएम ने किया उद्घाटन

गोलाघाट (हि.स.)। असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने बुधवार को देरगांव स्थित लाचित बरफूकन पुलिस अकादमी में राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों के दो दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से बताया कि सम्मेलन के दौरान राज्य की कानून-व्यवस्था को और मजबूत करने पर विशेष जोर दिया जाएगा। बैठक में अपराध नियंत्रण, महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा, साइबर अपराध की रोकथाम, मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान तेज करने, आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल और पुलिस व्यवस्था को अधिक जनमुखी बनाने सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। -शेष पृष्ठ दो पर

door graph
Premium Quality Hinges
S.S. Traders
Suppliers in : All kinds of Door Fittings Modular Kitchen & Accessories, etc.
D. Neog Path, Near Dona Planet ABC, G.S. Road, Guwahati - 05
97079-99344

सुप्रभात

ज्ञानी और छल-कपट से रहित शुद्ध मन वाले व्यक्ति को ही मंत्री बनाएं।

- आचार्य चाणक्य

केंद्र सरकार बाढ़ प्रभावित इलाकों में घर, सड़क और पानी की सुविधा के लिए करेगी मदद : सोनोवाल

गुवाहाटी। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने कहा कि केंद्र सरकार तीन जिलों में विनाशकारी बाढ़ से प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए राज्य को हर संभव मदद देगी। सोनोवाल ने कहा कि संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों ने पुनर्वास प्रक्रिया पर काम करना शुरू कर दिया है। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सड़क बुनियादी ढांचे सहित ग्रामीण इलाकों का विकास शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रभावित क्षेत्र में पीएमजीएसवाई के तहत अतिरिक्त घर बनाने की संभावना पर भी विचार किया जा रहा है। इसी तरह, जल शक्ति मंत्रालय *जल जीवन मिशन* के माध्यम से प्रभावित क्षेत्रों में पीने का पानी उपलब्ध कराने की संभावना की जांच कर रहा है, और सड़क परिवहन मंत्रालय सड़कों के निर्माण और मरम्मत आदि की आवश्यकता पर ध्यान दे रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सभी संबंधित मंत्रालयों ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए जरूरी कदम उठाने शुरू कर -शेष पृष्ठ दो पर

काजीरंगा ईएसजेड विवाद पर सीएम ने कहा-

नए जोन को अंतिम रूप देने से पहले स्थानीय लोगों से सलाह करेगी सरकार

गुवाहाटी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने बुधवार को कहा कि काजीरंगा के आस-पास इको-सेंसिटिव जोन (ईएसजेड) बनाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करते समय असम सरकार स्थानीय समुदायों से सलाह-मशविरा करेगी। शर्मा ने कहा कि ईएसजेड को अंतिम रूप देते समय नेशनल पार्क के आस-पास रहने वाले लोगों की चिंताओं और दिक्कतों का ध्यान रखना होगा। देरगांव में एक कार्यक्रम के दौरान प्रेस से बात करते हुए शर्मा ने कहा कि हमें इको-सेंसिटिव जोन बनाना है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हमें इसकी इजाजत दी है। हम लोगों से बात करेंगे और अच्छे तरीके से इको-सेंसिटिव जोन बनाएंगे। लोगों को होने वाली दिक्कतों को दूर करना होगा। मैं मुख्यमंत्री हूं, लोगों ने मुझे वोट दिया है, इसलिए मुझे लोगों की बात सुननी होगी और उनके लिए काम करना होगा। उन्होंने कहा कि काजीरंगा की लंबे समय तक सुरक्षा पार्क के आस-पास रहने वाले समुदायों के सहयोग और समर्थन पर निर्भर करती है। उन्होंने -शेष पृष्ठ दो पर

न्यूज गैलरी

सिलचर नगर निगम चुनाव 3 और मतगणना 6 अक्तूबर को

सिलचर (हि.स.)। राज्य निर्वाचन आयोग ने सिलचर नगर निगम चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार, सिलचर नगर निगम के लिए मतदान 3 अक्तूबर, 2026 को होगा। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 11 सितंबर निर्धारित -शेष पृष्ठ दो पर

आंध्र प्रदेश में मलेरिया की दवा खाते ही 50 से अधिक बीमार, एक की मौत

अमरावती। आंध्र प्रदेश के पल्लावरम जिले से एक बेहद दुखद और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहां मलेरिया से लड़ने के लिए बांटी गई क्लोरोक्वीन की गोलियां खाने के बाद सात साल की एक मासूम बच्ची की मौत हो गई, जबकि 52 अन्य लोग बीमार पड़ गए हैं, जिनका इलाज अस्पताल और स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। इस दर्दनाक घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। -शेष पृष्ठ दो पर

भारत में ब्रिक्स सम्मेलन का मंच दिल्ली में जुटेंगे दुनियाभर के दिग्गज

संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस इस महीने के आखिर में नई दिल्ली में होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस साल अध्यक्ष होने के नाते, भारत 12-13 सितंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इस शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के नेताओं के साथ-साथ विशेष रूप से आमंत्रित अतिथि भी शामिल होंगे। गुटेरेस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने मंगलवार को कहा कि हमें अभी आधिकारिक तौर पर यह घोषणा करनी है कि महासचिव लगभग 10 दिनों में -शेष पृष्ठ दो पर

सभी राज्य जजों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष करें : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष करने पर विचार करने को कहा। कोर्ट ने कहा कि न्यायिक अधिकारी आम सरकारी कर्मचारियों की तुलना में अपेक्षाकृत देर से न्यायिक सेवा में आते हैं। ऐसे में उनकी सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने से राज्यों पर ऐसा अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा, जिसे आधार बनाकर प्रस्ताव का विरोध किया जाए। प्रधान न्यायाधीश (सीजेआइ) सूर्यकांत और जस्टिस जोयमाल्या बागची तथा वी. मोहना की पीठ ने न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने को लेकर हिचकिचा रहे राज्यों के एडवोकेट जनरल से कहा कि वे अपने मुख्यमंत्रियों को मनाने का प्रयास करें। कुछ राज्यों ने न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु अन्य सरकारी कर्मचारियों के समान 58 या 60 वर्ष रखने का सुझाव दिया था। पीठ ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया। -शेष पृष्ठ दो पर

रीवा में बड़ा सड़क हादसा, 12 की मौत, 20 से ज्यादा लोग घायल

रीवा। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 39 पर एक सड़क दुर्घटना हुई है। यह हादसा बदबार स्टैंड के पास हुआ है। सीधी की ओर से आ रही पवन एक्सप्रेस बस और रीवा की ओर से आ रहे बल्कर के बीच आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। इसमें करीब 12 लोगों के मौत की खबर सामने आ रही है। हालांकि अभी पुष्ट जानकारी सामने आना बाकि है। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस के परखच्चे उड़ गए। स्थानीय निवासियों ने तुरंत गुढ़ थाना पुलिस को घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और राहत दल मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों की मदद से बचाव कार्य शुरू किया गया। दुर्घटना में -शेष पृष्ठ दो पर

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास की नई इबारत लिख रहा छत्तीसगढ़ : उपराष्ट्रपति

रायपुर (हि.स.)। छत्तीसगढ़ नक्सलवाद, भय और अभाव के साये से निकलकर आज शांति, प्रगति और अवसरों के नए दौर में प्रवेश कर चुका है, जो क्षेत्र कभी हिंसा के लिए जाने जाते थे, वहां आज सड़कें, स्कूल, अस्पताल, कनेक्टिविटी और निवेश पहुंच रहे हैं। यह बात उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने बुधवार को यहां अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के तीसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कही। उपराष्ट्रपति ने एम्स रायपुर को राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के ऐतिहासिक परिवर्तन का एक प्रमुख प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि, उन्नत स्वास्थ्य देखभाल, चिकित्सा अनुसंधान और ट्रांसप्लांटेशन के क्षेत्र में संस्थान की उपलब्धियां सराहनीय हैं, जिनमें राज्य का पहला *स्वैप किडनी ट्रांसप्लांट* भी शामिल है। उन्होंने कहा कि हृदय प्रत्यारोपण कार्यक्रम की मंजूरी एक और महत्वपूर्ण सफलता है। -शेष पृष्ठ दो पर

नेपाल में ग्लेशियर टूटने के 38 मिनट बाद भेजा गया था अलर्ट

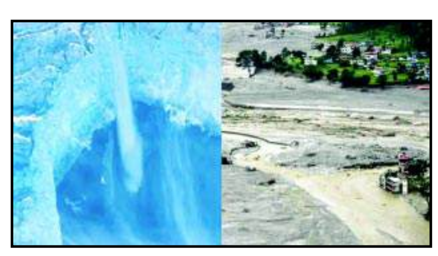

काठमांडू। नेपाल के पहाड़ी इलाकों में ग्लेशियर टूटने से आई विनाशकारी फ्लैश फ्लड ने भारी तबाही मचाई है। ताजा आंकड़ों के अनुसार, इस भयावह प्राकृतिक आपदा में अब तक 1,127 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 4,800 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों और कई क्षतिग्रस्त हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स की सुरंगों में फंसे लोगों को निकालने के लिए बड़े पैमाने पर खोज एवं बचाव अभियान चलाया जा रहा है। इसी बीच यह भी सामने आया है कि ग्लेशियर टूटने के 38 मिनट बाद अलर्ट भेजा गया था। इस पूरी त्रासदी के बाद नेपाल का आपातकालीन अलर्ट सिस्टम सवालों के घेरे में है। ग्लेशियर ढहने के पूरे 38 मिनट बाद जारी इस अलर्ट ने बालेन सरकार के आपदा प्रबंधन की पोल खोल दी। 26 अगस्त की सुबह 8:37 बजे जब नेपाल-तिब्बत सीमा के पास ग्लेशियर टूटा, तब सरकारी तंत्र भी बेखबर था। आपदा प्रबंधन विभाग को पहला आधिकारिक अलर्ट मिलने के बाद सुबह 9:15 बजे प्रभावित क्षेत्रों, रसुवा, नुवाकोट, धाडिंग और चितवन के लोगों के मोबाइल पर टेक्स्ट मैसेज भेजे गए। ग्लेशियर ढहने के पूरे 38 मिनट बाद जारी यह अलर्ट मैसेज भेजे गए। पहाड़ी -शेष पृष्ठ दो पर

CLASSIFIED

For all kinds of classified advertisements please contact

97070-14771
94350-14771

नेपाल में बाढ़ से हुई क्षति का प्रारंभिक आंकड़ा जारी

7,570 निजी घर तबाह, 30 अरब की सड़क संरचना ध्वस्त

काठमांडू (हि.स.)। नेपाल के भोटेकोशी और त्रिशूली नदी में आई विनाशकारी बाढ़ से नेपाल के पांच जिलों में 7,570 निजी घरों के क्षतिग्रस्त होने का प्रारंभिक अनुमान लगाया गया है। शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग द्वारा जुटाए गए विवरण के अनुसार रसुवा, नुवाकोट, धादिंग, गोरखा और चितवन में बड़ी संख्या में निजी घर बाढ़ की चपेट में आए हैं। विभाग के अनुसार 1,253 घरों का पूरी तरह नामोनिशान मिट गया है, जबकि 6,317 घर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं। इनमें से अधिकांश घरों की स्थिति ऐसी है कि उन्हें तत्काल मरम्मत कर रहने योग्य नहीं बनाया जा सकता और उनका पुनर्निर्माण करना पड़ेगा। विभाग के तरफ से जारी आंकड़ों में बताया गया है कि बाढ़ से पांच जिलों में 7,570 निजी घरों के क्षतिग्रस्त होने का प्रारंभिक विवरण प्राप्त हुआ है। विभाग की टीम ने प्रभावित क्षेत्रों में जाकर नुकसान का आकलन किया है। निजी घरों को ही करीब 17 अरब 31 करोड़ नेपाली रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। बाढ़ से सरकारी निकायों के 45 भवन भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। इन भवनों में करीब साढ़े चार अरब नेपाली रुपए के नुकसान का प्रारंभिक अनुमान है। विभाग के महानिदेशक रविंद्र बोहरा के अनुसार, रसुवा में कुल 1,779 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं और करीब 5 अरब 7 करोड़ 98 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। रसुवा जिले के गोसाईंकुंड में 1,043 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं जिनसे 2 अरब 49 करोड़ 86 लाख रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। ऐसे ही कालिका में 112 घर बर्बाद हो चुके हैं जिससे 18 करोड़ 48 लाख रुपए के नुकसान का अंदाजा लगाया गया है। रसुवा जिले के ही आमाछोदिङ्मो में 57 घर — 9 करोड़ 40 लाख रुपए और उत्तरगया में 567 घरो का नामोनिशान मिट गया है जिससे 2 अरब 30 करोड़ 23 लाख रुपए के नुकसान होने की जानकारी दी गई है। नुवाकोट में 3,977 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं और कुल नुकसान 9 अरब 22 करोड़ 62 लाख रुपए आंका गया है। इस जिले के बेलकोटगढ़ी में 212 घर तबाह हुए हैं जिससे 60 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। इसी तरह विदुर नगरपालिका में 3,026 घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। यहां 7 अरब 17 करोड़ 58 लाख रुपए के नुकसान होने की बात कही गई है। नुवाकोट जिले के किस्पाङ में 696 घर पानी में बह गए जिससे 1 अरब 30 करोड़ 24 लाख रुपए की क्षति हुई है। जिले के तार्केश्वर नगरपालिका में 43 घर टूट गए जिससे 14 करोड़ 79 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। धादिंग में कुल 1,451 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। यहां करीब 2 अरब 40 करोड़ 95 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। इस जिले के बेनीघाट रोराङ में 1,037 घर के टूटने से 1 अरब 72 करोड़ 64 लाख रुपए का उकसा बताया गया है जबकि गजुरी में 107 घर के टूटने से 17 करोड़ 65 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। ऐसे ही गल्छी में 79 घरों के टूटने पर 13 करोड़ 3 लाख रुपए और सिद्धलेक में 228 घर के नुकसान पर 37 करोड़ 62 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। गोरखा में 263 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं और 43 करोड़ 39 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। इनमें गण्डकी क्षेत्र में 248 और शहीद लखन में 15 घर शामिल हैं। वहीं, चितवन के इच्छाकामना में 100 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिससे करीब 16 करोड़ 50 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। बाढ़ ने नेपाल के सड़क बुनियादी ढांचे को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। सड़क विभाग के महानिदेशक डा विजय के अनुसार राष्ट्रीय सड़क ढांचे को करीब 30 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। 82 किलोमीटर लंबे गल्छी–स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढ़ी मार्ग का करीब 40 किलोमीटर हिस्सा पूरी तरह तबाह हो गया है, जिसे दोबारा बनाना पड़ेगा। इसके अलावा पृथ्वी राजमार्ग के कृष्णभीर खंड को भी नुकसान पहुंचा है। बाढ़ में 31 पुल बह गए, जबकि तीन अन्य पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं। सड़क विभाग के अनुसार इन सड़कों और पुलों के पुनर्निर्माण में करीब 50 अरब रुपए खर्च होने का अनुमान है। रसुवा और नुवाकोट में 53 सस्पेंशन ब्रिज भी बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। इनमें 33 पुल पूरी तरह बह गए, जबकि 20 पुलों की मरम्मत संभव बताई गई है। स्थानीय पूर्वाधार विकास विभाग के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार स्थानीय बुनियादी ढांचे को करीब 1 अरब 25 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है।

राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता का दावा कोर्ट में फेल, याचिका खारिज

नई दिल्ली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने राहुल की नागरिकता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। इस याचिका में उनकी भारतीय नागरिकता रद्द करने और रायबरेली से लोकसभा सदस्यता पर सवाल उठाया गया था। याचिकाकर्ताओं ने राहुल पर ब्रिटिश नागरिकता होने का आरोप लगाया था। इसके साथ ही ब्रिटेन में कंपनी बकोप्स लिमिटेड से जुड़े दस्तावेजों का हवाला दिया गया था। बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता अपने इस आरोप को साबित करने के लिए एक भी दस्तावेज पेश नहीं कर पाया कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक थे। कोर्ट ने कहा, दलीलों को देखते हुए याचिकाकर्ता को मौजूदा रिट याचिका वापस लेने की अनुमति दी जाती है। इस तरह मौजूदा रिट याचिका वापस ली गई मानकर खारिज की जाती है। कोर्ट ने पहले कहा था कि वह इस रिट याचिका पर सुनवाई करने को लेकर संशय में है क्योंकि राहुल की नागरिकता से जुड़ा मामला केंद्र सरकार के पास लंबित है। हालांकि, याचिकाकर्ता के जोर देने पर कोर्ट ने मामले की सुनवाई की और उसके द्वारा पेश किए गए दस्तावेजों की जांच की। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने 2003 में यूके स्थित कंपनी ख्व्ह्य बकोप्स लिमिटेड बनाई थी और खुद को डायरेक्टर, मुख्य शेयर–होल्डर और ब्रिटिश नागरिक बताया था। कोर्ट ने पाया कि भले ही याचिकाकर्ता की दलीलें और उनके दूरगामी परिणाम हो सकते थे लेकिन वह रिकॉर्ड पर ऐसा कोई दस्तावेज नहीं दिखा सका जो कंपनी के गठन, ब्रिटेन के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के रिकॉर्ड या किसी ऐसे घोषणा–पत्र से संबंधित हो जिससे यह साबित हो सके कि राहुल गांधी ने खुद को ब्रिटिश नागरिक घोषित किया था। बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता ने जिस एकमात्र दस्तावेज का सहारा लिया, वह कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी द्वारा जारी किया गया एक कथित कन्फर्मेशन लेटर है, जो *राउल विंची* की पढ़ाई को प्रमाणित करता है। इस कोर्ट के अनुसार यह दस्तावेज मौजूदा याचिका में लगाए गए किसी भी आरोप को किसी भी तरह से साबित नहीं करता है।

भूटान से आने वाले पानी से किसानों को मिलेगा सिंचाई का लाभ : पीयूष

गुवाहाटी (हिंस)। असम के मंत्री पीयूष हजारिका ने बुधवार को भारत–भूटान सीमा क्षेत्र बोगामाटी तथा तामुलपुर शहर के समीप बरलिया नदी पर स्थित नाला–सिंचाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। उन्होंने यह निरीक्षण बरनदी नदी की सिंचाई क्षमता की समीक्षा के उद्देश्य से किया। मंत्री हजारिका ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आने वाले दिनों में भूटान से असम में आने वाले पानी का उपयोग कर पूरे जिले के किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए बड़े पैमाने पर सिंचाई परियोजनाएं विकसित करने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य जल संसाधनों का बेहतर उपयोग कर कृषि क्षेत्र को मजबूत करना और अधिक से अधिक किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना है।

अन्ना हजारे की सेहत में सुधार

मुंबई (हि.स.)। वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता 89 वर्षीय अन्ना हजारे की तबीयत में सुधार हो रहा है। मुंबई स्थित बॉम्बे अस्पताल में भर्ती अन्ना हजारे डॉक्टरों की सलाह के अनुसार ठीक से खाना भी खा रहे हैं। अन्ना हजारे के सहयोगी दत्ता टावरी ने बुधवार को बताया कि डॉक्टरों ने अन्ना हजारे की जांच कर हालत में सुधार पाया है। हालांकि, पूरी तरह स्वस्थ होने तक उन्हें निगरानी में रखने के लिए अस्पताल में दो दिन और रखा जाएगा। अन्ना हजारे को सोमवार को दक्षिण मुंबई स्थित बॉम्बे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इससे पहले जांच के दौरान उनकी किडनी में संक्रमण (रीनल इंफेक्शन) की पुष्टि हुई थी। जिसके बाद उन्हें रालेगण सिद्धि से मुंबई लाया गया था। हजारे को पिछले सप्ताह अहिल्यानगर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहां उपचार के बाद उनकी स्थिति में सुधार हुआ लेकिन किडनी में संक्रमण सामने आने के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए मुंबई के बॉम्बे अस्पताल में स्थानांतरित किया गया।

जीडीपी के आंकड़ों में खेल कर रही सरकार : जयराम

नई दिल्ली (हि.स.)। कांग्रेस ने सरकार के 7.8 प्रतिशत जीडीपी वृद्धि दर के दावे पर सवाल उठाते हुए कहा कि पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग के आकलन के अनुसार वास्तविक जीडीपी वृद्धि करीब 2.6 प्रतिशत है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार आंकड़ों की बाजीगरी के जरिए अर्थव्यवस्था की तस्वीर चमकाने की कोशिश कर रही है, जबकि यह जमीनी हकीकत से अलग है। कांग्रेस महासचिव (संचार) एवं राज्यसभा सदस्य जयराम रमेश ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर कहा कि मोदी सरकार अपनी टीम और मीडिया के जरिए जितना फर्जी जीडीपी बढ़ोतरी का ढोल पीटेगी, उतना ही उसकी असलियत सामने आएगी। पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग ने इस दावे पर गंभीर सवाल उठाए हैं और उनका आकलन है कि वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7.8 प्रतिशत के बजाय करीब 2.6 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चाहती है कि देश की अर्थव्यवस्था वास्तव में मजबूत हो, लेकिन मजबूत अर्थव्यवस्था का रास्ता आंकड़ों को सजाने से नहीं, बल्कि वास्तविक स्थिति को स्वीकार करने से निकलता है। सरकार को पहले अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति स्वीकार करनी चाहिए और उसके बाद सुधारों की दिशा में कदम उठाने चाहिए। जयराम ने कहा कि सरकार को युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों और निजी निवेश को बढ़ावा देने तथा मांग और आमदनी बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही आर्थिक असमानता को कम करने और कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों को बढ़ावा देने के बजाय निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सरकार को समझना होगा कि जनसंपर्क के जरिए जीडीपी की तस्वीर चमकाई जा सकती है, लेकिन इससे अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होती। जिस जीडीपी वृद्धि दर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों से पटाखे फोड़ने और दीपावली मनाने की अपील कर रहे हैं, उसी पर उनके पूर्व वित्त सचिव गंभीर सवाल उठा रहे हैं।

शेख हसीना के तख्तापलट में बड़ी भूमिका निभाने वाले आसिफ के खिलाफ एक्शन की तैयारी

ढाका। शेख हसीना के तख्तापलट में अहम भूमिका निभाने वाले आसिफ महमूद भुइयां भ्रष्टाचार के मामले में फंस गए हैं। बांग्लादेश की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई ने आसिफ के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। जांच इकाई के एक अधिकारी ने बताया कि अंतरिम सरकार में आसिफ खेल मंत्री (सलाहकार) थे। इस दौरान ठेकों और नियुक्तियों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ। आसिफ के साथ चार और लोग भी इसमें शामिल थे। बांग्लादेश के अखबार प्रथम आलो के मुताबिक, आसिफ शेख हसीना के खिलाफ हुए जुलाई विद्रोह का प्रमुख चेहरा थे। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में जब अंतरिम सरकार बनी, तब आसिफ को खेल एवं युवा मामलों का मंत्री बनाया गया। आसिफ करीब 16 महीने तक सरकार में मंत्री रहे। 2024 के मध्य में बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन हुआ था। नाहिद इस्लाम और आसिफ महमूद इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे। जुलाई के आखिर में यह प्रदर्शन हिंसक हो गया। 5 अगस्त को शेख हसीना का तख्तापलट हो गया। शेख हसीना का कहना था कि इन लोगों को अमेरिका ने फंड किया था। शेख हसीना की सरकार जाने के बाद बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। नाहिद और आसिफ को सरकार में सलाहकार (मंत्री) का पद दिया गया। इस वक्त दोनों नेशनल सिटीजन पार्टी चलाते हैं। 28 साल के आसिफ महमूद का जन्म कोमिला जिले में हुआ था। ढाका यूनिवर्सिटी से पढ़ाई के बाद आसिफ छात्र राजनीति में आ गए। इसी दौरान छात्रों ने शेख हसीना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया।

सोनापुर हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को सात सात लाख रुपए की सहायता

गुवाहाटी (हिंस)। सोनापुर के खेत्री में हुए सड़क हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को राज्य सरकार की ओर से सात–सात लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। डिमोरिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉ. तपन दास ने राज्य सरकार की ओर से मृतकों के परिजनों को सहायता राशि के चेक सौंपे। मृतक इंसान अली, ज्योतिका रंग्हांग और तफीजुल अली के परिवारों को सात–सात लाख रुपए के चेक प्रदान किए गए।

অসম লোকসেৱা আয়োগ
ASSAM PUBLIC SERVICE COMMISSION
Jawaharnagar, Khanapara, Guwahati-781022.

eCFNo.830677/324 02.09.2026

NOTIFICATION

In continuation to earlier notification **no. 140PSC/DR-4/1/2024- 2025, Dated Guwahati, the 1st August, 2026,** this is for information to all concerned that the screening test for recruitment to the post of **Assistant Engineer (Civil/Mechanical/ Chemical) under Public Health Engineering Department, Assam. (Advt. No. 31/ 2025, Dated Guwahati the 9th September, 2025)** has been rescheduled by the Commission as per programme given below:

PROGRAMME OF SCREENING TEST

Name of Post	Date & Day	Time	Subjects
Assistant Engineer (Civil/Mechanical/ Chemical) under Public Health Engineering Department, Assam	29-09-2026 (Sunday)	10:00 AM to 12:00 Noon	General Studies (Paper-I)
		1:30 PM to 3:30 PM	Engineering (Civil / Mechanical / Chemical) (Paper -II)

No intimation letter to the candidates shall be sent separately by post. The candidates concerned are directed to refer to the list uploaded to the Commission's Official website **(www.apsc.nic.in)** on 28-07-2026. The updated e-Admission Certificate shall be uploaded on **17-09-2026** in the aforementioned website. Candidates shall have to download their own e-Admission Certificate from the aforesaid website.

The Commission would like to clarify that the Commission reserves the right **to cancel the candidature of any candidate on verification of their application form** at any time or stage even after the Screening Test, if it is found that they do not fulfill any of the eligibility criteria/conditions as per terms of the **aforementioned advertisement.**

PwBD candidates willing to apply for scribe for the said Screening Test may inform in writing with supporting documents to the Commission or send mail to apsc-asm@nic.in on or before 02-09-2026.

Secretary,
Assam Public Service Commission
Jawaharnagar, Khanapara, Guwahati - 22

-- DIPR /D/VBS-57/3-Sep-26

पृष्ठ एक का शेष

असम पुलिस में 20 हजार...

ट्रेनिंग पूरी की; इसमें एलबीपीए में दो हफ्ते का ओरिएंटेशन और मेघालय में नॉर्थ ईस्टर्न पुलिस एकेडमी में दो महीने की ट्रेनिंग शामिल थी। उनकी ट्रेनिंग में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, पॉस्को एक्ट, आर्म्स एक्ट और एनडीपीएस एक्ट जैसे कानून, साथ ही साइबर क्राइम, फोरेंसिक साइंस और बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मॉड्यूल शामिल थे। ट्रेनीज ने हथियार संभालने और सुरक्षा, घुड़सवारी, तैराकी, आईईडी मैनेजमेंट और भीड़ को नियंत्रित करने जैसी आउटडोर एक्सरसाइज भी कीं। शर्मा ने पुलिस महानिदेशक से एलबीपीए में ट्रेनिंग के स्टैंडर्ड को और बेहतर बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि एकेडमी को स्पेशल कमांडो ट्रेनिंग के अलावा भारतीय सशस्त्र बलों और अग्निवीर प्रोग्राम जैसी ट्रेनिंग भी देनी चाहिए। इस बीच, मुख्यमंत्री बुधवार और गुरुवार को सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (एसएसपी) की दो दिन की कांफ्रेंस के लिए देरगांव में रहेंगे। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार के सत्ता में आने के बाद यह अपनी तरह की पहली कांफ्रेंस होगी। शर्मा ने कहा कि बुधवार और गुरुवार को एसएसपी कांफ्रेंस होगी। इन दो दिनों में, मैं उनसे कानून–व्यवस्था, नई भर्तियों, ड्रग्स, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों और अन्य मुद्दों पर चर्चा करूंगा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों ...

मुख्यमंत्री ने कहा कि असम के प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करना राज्य सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। पुलिस बल को अधिक सक्षम, आधुनिक और जवाबदेह बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं तथा आने वाले दिनों में इन प्रयासों को और मजबूत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि म्यांमार और बांग्लादेश की सीमा से असम की भौगोलिक निकटता के कारण राज्य विशेष रूप से मादक पदार्थों की तस्करी के लिहाज से संवेदनशील है। इसलिए ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई को और अधिक मजबूत तथा तेज करना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मादक पदार्थों के खतरे को खत्म कर नई पीढ़ी के स्वस्थ भविष्य का निर्माण करना सरकार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।

केंद्र सरकार बाढ़ प्रभावित ...

दिए हैं। अपने मंत्रालय की नई परियोजनाओं के बारे में सोनोवाल ने कहा कि मैरीटाइम स्किल डेवलपमेंट सेंटर (समुद्री कौशल विकास केंद्र) स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उन्होंने कहा कि यह केंद्र हर साल 5,000 छात्रों को प्रशिक्षित करेगा। इस सवाल के जवाब में कि क्या इतने सारे लोगों के लिए पर्याप्त रोजगार के अवसर होंगे, सोनोवाल ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में रोजगार के पर्याप्त अवसर हैं। उन्होंने कहा कि फिलीपींस के बाद भारत में दुनिया में दूसरे सबसे अधिक नाविक (सीफेयरर) हैं। भारत के लिए इस मामले में नंबर एक बनने की काफी गुंजाइश है। मंत्री ने यह भी कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में 20 राष्ट्रीय जलमार्गों में नई जेट्टी (घाट) बनाने के अलावा, उनका मंत्रालय जल्द ही पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्र के बड़े जल निकायों में जेट्टी बनाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि पूर्वोत्तर में पहले केवल दो राष्ट्रीय जलमार्ग थे और अब इनकी संख्या बढ़कर 20 हो गई है।

नए जोन को अंतिम ...

कहा कि काजीरंगा की सुरक्षा इंस्टाग्राम पर नहीं हो सकती, गौरव गोगोई भी काजीरंगा की सुरक्षा नहीं कर सकते। काजीरंगा की सुरक्षा कौन करेगा? इसके पास रहने वाले लोग। इसलिए, लोगों को नाराज करके कुछ भी करना गलत है। हमें स्थानीय लोगों के साथ मिलकर काम करना है, और हमारी सरकार इसी तरह काम करती है। मुख्यमंत्री ने काजीरंगा के आस–पास ईएसजेड में प्रस्तावित बदलावों के खिलाफ हाल ही में हुए विरोध प्रदर्शनों को लेकर विपक्षी कांग्रेस पर भी निशाना साधा। शर्मा ने कहा कि हमने गैंडों के शिकार को रोका और काजीरंगा को ऐसी जगह में बदल दिया जिस पर हमें गर्व हो सकता है जब पर्यटक यहां आते हैं। वहां और भी कई काम किए जाएंगे। लेकिन जब कोई राजनीतिक पार्टी, जो जानती है कि उसके शासनकाल में गैंडों का शिकार खूब होता था, काजीरंगा के बारे में बात करती है, तो यह पूरी तरह से बेशर्मी दिखाता है। असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी (एपीसीसी) ने 29 अगस्त को काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व के आस–पास ईएसजेड को 10 किमी से घटाकर 1 किमी करने के राज्य सरकार के प्रस्तावित कदम के खिलाफ राज्य भर में विरोध प्रदर्शन किया था। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य के अन्य हिस्सों के अलावा शोणितपुर, शिवसागर, लखीमपुर, हैलाकांदी और करीमगंज सहित कई जिलों में पदयात्राएं निकालीं और प्रदर्शन किए। ये विरोध प्रदर्शन ईएसजेड के दायरे में संभावित कमी के बारे में शर्मा की पिछली टिप्पणियों के बाद हुए थे। हालांकि, मुख्यमंत्री ने 27 अगस्त को साफ किया कि 1–किमी ईएसजेड की उनकी बात खास तौर पर बोकाखाट के संदर्भ में थी। उन्होंने कहा था कि काजीरंगा इलाके के अलग–अलग हिस्सों में ईएसजेड के दायरे के लिए अलग–अलग तरीकों की जरूरत होगी, जो वन्यजीवों की आवाजाही और ब्रह्मपुत्र नदी की मौजूदगी जैसी बातों पर निर्भर करेगा।

भारत में ब्रिक्स सम्मेलन...

नई दिल्ली में होने वाली ब्रिक्स बैठक में भाग लेंगे। बता दें कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का विषय *लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण* है। भारत के 25 से अधिक शहरों में 350 से अधिक बैठकें और उच्च–स्तरीय बातचीत हुई हैं, ताकि ब्रिक्स की रणनीतिक साझेदारी को तीन मुख्य आधारों पर मजबूत किया जा सके। इनमें राजनीतिक और सुरक्षा, आर्थिक और वित्तीय तथा सांस्कृतिक और लोगों के बीच आदान–प्रदान शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इन कार्यक्रमों और बिजनेस–टू–बिजनेस तथा लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने वाली पहलों के माध्यम से, भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता ने व्यावहारिक और विकास–उन्मुख परिणामों के जरिए ब्रिक्स सहयोग को आगे बढ़ाने में योगदान दिया है।

सभी राज्य जजों ...

कोर्ट ने कहा कि न्यायिक सेवा में आने तक जज काफी उम्र पार कर चुके होते हैं। ऐसे में उन्हें 62 वर्ष तक सेवा का अवसर देने से राज्यों पर कोई असामान्य वित्तीय भार नहीं पड़ेगा। सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों ने न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने के प्रस्ताव को लागू करने में वित्तीय कठिनाइयों का हवाला दिया। नगालैंड ने कहा कि उसके यहां सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष है। ऐसे में न्यायिक अधिकारियों के लिए यह सीमा बढ़ाने से प्रशासनिक और वित्तीय दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। हालांकि, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना ने जिला अदालतों के न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने के प्रस्ताव पर सहमति जताई। पीठ ने राज्यों की अलग–अलग राय पर गौर करते हुए सभी से इस मुद्दे पर सकारात्मक रुख अपनाने को कहा। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 17 सितंबर की तारीख तय की है।

रीवा में बड़ा सड़क...

लगभग 20 लोग घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल एम्बुलेंस और अन्य वाहनों से संजय गांधी अस्पताल रीवा भर्ती कराया गया। घटनास्थल पर राहत एवं बचाव कार्य पूरी तत्परता से जारी है। पुलिस और प्रशासन की टीमें सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। घायलों को तुरंत चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। प्रशासन द्वारा स्थिति को नियंत्रित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस भीषण दुर्घटना से पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है। राष्ट्रीय राजमार्ग 39 पर यातायात भी प्रभावित हुआ है। प्रशासन ने घायलों के समुचित इलाज के निर्देश दिए हैं। मृतकों के परिजनों को सूचना देने की प्रक्रिया चल रही है।

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों ...

समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति ने विभिन्न संकायों के मेधावी छात्र–छात्राओं को उनकी उत्कृष्ट शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए स्वर्ण पदक और प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। मध्य भारत के इस प्रतिष्ठित संस्थान में आयोजित समारोह में स्नातक (यूजी), स्नातकोत्तर (पीजी), सुपर–स्पेशियलिटी, डॉक्टरेट और संबद्ध स्वास्थ्य विज्ञान पाठ्यक्रमों के कुल 689 विद्यार्थियों (376 छात्राएं और 313 छात्र) को डिग्रियां प्रदान की गईं। दीक्षांत समारोह के मुख्य आकर्षणों में *से नो टू ड्रग्स* (नशे को ना कहें) की शपथ भी शामिल रही, जिसके तहत उपस्थित सभी विद्यार्थियों को स्वयं नशीले पदार्थों के सेवन से दूर रहने और अपने साथियों व समाज में इसके दुष्प्रभावों व खतरों के प्रति व्यापक जागरूकता फैलाने का संकल्प दिलाया गया। समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि, यह दीक्षांत समारोह केवल उत्सव का क्षण नहीं है बल्कि जिम्मेदारी का भी अवसर है। उन्होंने कहा कि आज आपको आपकी डिग्रियां मिल रही हैं और कल आपको इससे कहीं अधिक मूल्यवान जिम्मेदारी सौंपी जाएगी– भारत की जनता का स्वास्थ्य, विश्वास और जीवन। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका, केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल उपस्थित रहे। वहीं, एम्स रायपुर की ओर से अध्यक्ष प्रो. (डॉ.) संजीव हांडा तथा कार्यकारी निदेशक सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल अशोक जिंदल भी मंच पर मौजूद रहे।

नेपाल में ग्लेशियर...

इलाकों में भीषण गति से बहने वाली फ्लैश फ्लड के सामने चेतावनी में हुई यह 38 मिनट की देरी निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए काल साबित हुई, जिससे उन्हें सुरक्षित ऊंचे स्थानों पर जाने का पर्याप्त समय नहीं मिल सका। नेपाल के खान एवं भूविज्ञान विभाग ने सुबह 8:37 बजे 4.4 तीव्रता का सिस्मिक डेटा रिकॉर्ड किया था, लेकिन इसे भूकंपीय झटका न मानकर सामान्य श्रेणी में रख दिया गया और अलर्ट जारी नहीं किया गया। वहीं, सुबह 8:50 बजे रसुवा में भोटेकोशी नदी का गेज तेज बहाव में बह गया। काठमांडू पोस्ट के अनुसार, राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए) के अधिकारियों का कहना है कि कई इलाकों में बाढ़ के शुरुआती झोंके से ही टेलीकॉम टावर नष्ट हो गए थे। हालांकि, 9:15 बजे भेजे गए टेक्स्ट अलर्ट के बाद कुछ लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया, लेकिन दूर–दराज के गांवों तक जानकारी पहुंचने से पहले ही जलप्रलय तबाही मचा चुका था। विशेषज्ञों का कहना है कि हिंदू कुश हिमालयी क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियर दोगुनी तेजी से पिघल रहे हैं। इसके बावजूद, नेपाल का चेतावनी तंत्र अब भी केवल सामान्य जलस्तर मापने वाले गेज पर टिका है, जो ऐसी भीषण आपदाओं को भांपने में असमर्थ है। फिलहाल इस भीषण बाढ़ के बाद लापता लोगों का बचाव और खोज अभियान जारी है। राहतकर्मी और सुरक्षा बल बाढ़ प्रभावित इलाकों तथा नदी के निचले हिस्सों में लगातार तलाश कर रहे हैं।

सिलचर नगर निगम ...

की गई है। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनावी तस्वीर और स्पष्ट होने की उम्मीद है। मतों की गिनती 6 अक्तूबर को होगी और इसी दिन चुनाव परिणाम घोषित किए जाने की संभावना है। चुनाव की तारीख घोषित होने के साथ ही सिलचर में राजनीतिक गतिविधियां तेज होने की उम्मीद है। विभिन्न राजनीतिक दलों और संभावित उम्मीदवारों ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। आने वाले दिनों में उम्मीदवारों के चयन, नामांकन दाखिल करने और चुनाव प्रचार से जुड़ी गतिविधियों में तेजी आने की संभावना है।

आंध्र प्रदेश में मलेरिया की ...

अधिकारियों के मुताबिक, तेलंगाना की अंतर–राज्यीय सीमा से लगे पलावाड़म जिले के गोलागुप्पा गांव में मलेरिया से बचाव के लिए 71 लोगों को एंटी–मलेरिया गोलियां दी गई थीं। मिली जानकारी के अनुसार दवा खाने के कुछ देर बाद ही कई लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी। हालात को गंभीर देखते हुए प्रशासन ने तुरंत ऐक्शन लिया और 29 मरीजों को तेलंगाना के एक अस्पताल में, जबकि 24 मरीजों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। इस हादसे में दूसरी कक्षा में पढ़ने वाली 7 साल की बच्ची माडिवी जमुना की इलाज के दौरान मौत हो गई। डॉक्टरों के मुताबिक, बाकी अन्य मरीजों की हालत फिलहाल स्थिर बनी हुई है। घटना की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों से पूरी रिपोर्ट मांगी है और इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही, पीड़ितों को बेहतर से बेहतर इलाज मुहैया कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जिला कलेक्टर दिनेश कुमार ने लोगों से अपील की है कि वे घबराएं नहीं और स्थिति नियंत्रण में है। मरीजों की देखरेख के लिए प्रशासन ने तुरंत कदम उठाए हैं। काकीनाडा सरकारी जनरल अस्पताल से 9 सदस्यों की एक विशेष मेडिकल टीम गांव पहुंच चुकी है। विजयवाड़ा, राजमहेंद्रवरम और काकीनाडा से तीन और विशेष टीमें जल्द ही पहुंचने वाली हैं। गांव में ही एक मेडिकल कैंप लगाकर विशेष डॉक्टरों की तैनाती की गई है, जो लगातार मरीजों की सेहत पर नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल बच्ची की मौत के असल कारणों की आधिकारिक जांच की जा रही है, और स्वास्थ्य विभाग यह पता लगाने में जुटा है कि आखिर दवा खाने के बाद लोगों की तबीयत इतनी कैसे बिगड़ गई।

60 लाख की फिरौती के लिए 9 साल की बच्ची का अपहरण मामले में दो गिरफ्तार

जोरहाट (हिंस)। असम के मरियानी में नौ वर्षीय बच्ची के कथित अपहरण का मामला सामने आया है। आरोप है कि बच्ची के रिश्तेदारों ने उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने के बाद परिवार से 60 लाख रुपए की फिरौती मांगी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बच्ची को डेरगांव के इस्लाम नगर से सुरक्षित बरामद कर लिया है। पुलिस के मुताबिक, बच्ची के मामा सागर घोष और उनकी पत्नी मनीषा घोष मरियानी के लोकनाथ भवन स्थित कमरा नंबर 109 में करीब तीन दिनों से ठहरे हुए थे। मंगलवार दोपहर दोनों कथित तौर पर बच्ची के रिश्तेदार के घर पहुंचे और उसे बहाने से अपने साथ ले गए। कई घंटे तक बच्ची के घर नहीं लौटने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। पुलिस के अनुसार, शाम करीब पांच बजे कथित अपहरणकर्ताओं ने परिवार से 60 लाख की फिरौती मांगी और पुलिस को सूचना देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। आरोप है कि रात आठ बजे तक रकम नहीं देने पर बच्ची को जान से मारने की धमकी भी दी गई। मामले की जानकारी मिलने के बाद मरियानी पुलिस ने बच्ची की तलाश के लिए अभियान शुरू किया। पुलिस को मिली सूचना के आधार पर डेरगांव के इस्लाम नगर में छापेमारी की गई, जहां से बच्ची को रात करीब दो बजे सुरक्षित बरामद कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि बच्ची सुरक्षित है और उसे उसके परिवार को सौंप दिया गया है। पुलिस ने मामले में अब तक दो लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें डेरगांव के कोयलाखाटा निवासी सागर घोष उर्फ *टार्जन* और इस्लाम नगर निवासी वसीम रहमान उर्फ *कनाकाई* शामिल हैं। वहीं, मनीषा घोष, डेरगांव के इस्लाम नगर निवासी राहुल अली और फुकन नगर निवासी एक व्यक्ति, जिसकी पहचान फिलहाल *मोन* के नाम से बताई गई है, फरार हैं। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए तलाशी अभियान चला रही है। पुलिस ने कथित तौर पर अपहरण में इस्तेमाल किए गए एक वाहन (एएस05बी9917) और लाल रंग के स्कूटर (एएस05डब्ल्यू4263) को भी जब्त किया है।

सीएम हिमंत विश्व शर्मा का सपना हुआ साकार सिलचर नगर निगम चुनाव का रास्ता साफ

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने सिलचर नगर निगम चुनाव की तारीख की घोषणा का किया स्वागत

गुवाहाटी (हिंस)। असम राज्य चुनाव आयोग द्वारा सिलचर नगर निगम के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित चुनाव की तारीख की घोषणा का भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के असम प्रदेश अध्यक्ष व लोकसभा सांसद दिलीप सैकिया ने गर्मजोशी से स्वागत किया है। पार्टी के मीडिया पैनलिस्ट त्रिदीप मोरन द्वारा बुधवार को जारी एक बयान में सैकिया ने कहा कि सिलचर नगरपालिका को नगर निगम में अपग्रेड करना भाजपा के प्रमुख चुनावी वादों में से एक था। इस वादे को पूरा करके, मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने बराक घाटी के लोगों के लंबे समय से संजोए सपने को साकार किया है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री का हार्दिक धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने कहा कि 3 अक्तूबर को होने वाले सिलचर नगर निगम के 42 वार्डों के चुनाव शहर के लोकतांत्रिक और नागरिक प्रशासनिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होंगे। नगर निगम के गठन से सिलचर के लोगों को

आधुनिक शहरी सुविधाओं तक पहुंच मिलेगी और लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शहर के समग्र विकास में तेजी आएगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि नवगठित नगर निगम नागरिक सेवाओं, स्वच्छता, सड़कों और कनेक्टिविटी, जल निकासी और सीवरेज, जलापूर्ति, स्ट्रीट लाइटिंग और अन्य बुनियादी ढांचे में सुधार को और गति देगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि एक ऐसा नया माहौल बनेगा जिसमें नगर निगम का स्थानीय प्रशासन, राज्य सरकार की विकास-उन्मुख पहलों के साथ मिलकर काम करते हुए, नागरिकों की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को पूरा करने में सक्षम होगा। सैकिया ने कहा कि विकास, सुशासन और जन-कल्याण मिलकर एक आधुनिक, स्वच्छ और आत्मनिर्भर सिलचर के निर्माण का आधार बनते हैं। यह चुनाव केवल नगरपालिका प्रतिनिधियों को चुनने की औपचारिक प्रक्रिया नहीं है; यह सिलचर की भविष्य की शहरी योजना, नागरिक सुविधाओं और समग्र विकास को आकार देने का एक ऐतिहासिक अवसर है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने सिलचर के लोगों से विकास और जन-कल्याण के हित में इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उत्साहपूर्वक और सक्रिय रूप से भाग लेने की अपील की।

नगांव की जनसांख्यिकी हमारे पक्ष में नहीं : मंत्री जयंत मल्ल बरुवा

गुवाहाटी (हिंस)। असम के वित्त मंत्री जयंत मल्ल बरुवा ने बुधवार को कहा कि नगांव लोकसभा क्षेत्र की जनसांख्यिकी उनकी पार्टी के पक्ष में नहीं है। उन्होंने नगांव को एक कठिन लोकसभा क्षेत्र बताते हुए आगामी उपचुनाव में जीत की उम्मीद जताई। नगांव लोकसभा उपचुनाव को लेकर बरुवा ने कहा कि नगांव एक कठिन सीट है, लेकिन पार्टी को उम्मीद है कि वह अच्छा प्रदर्शन करेगी। इस बीच, राज्य में कुल 126 *अरुणोदय सारथी* नियुक्त किए गए हैं। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक अरुणोदय सारथी की नियुक्ति की गई है। वित्त मंत्री जयंत मल्ल बरुवा ने बुधवार को इन नवनियुक्त अरुणोदय सारथियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बरुवा ने कहा कि मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी अरुणोदय योजना के जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं को दूर करने और लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ सुचारु रूप से पहुंचाने के लिए यह कदम उठाया गया है। वित्त मंत्री जयंत मल्ल बरुवा ने यूएसटीएम द्वारा पहाड़ काटे जाने को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि यूएसटीएम के पहाड़ों की खुदाई वाले क्षेत्र से पानी का तेज बहाव नीचे आने के कारण जोराबाट में समुद्र जैसी स्थिति पैदा हो गई।

मणिपुर के राज्यपाल और मुख्यमंत्री से पूसीरे के महाप्रबंधक ने की भेंट वार्ता

रेल कनेक्टिविटी और अवसंरचना विकास से जुड़े मुद्दों पर हुई चर्चा

गुवाहाटी (हिंस)। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (पूसीरे) के महाप्रबंधक चेतन कुमार श्रीवास्तव ने 1 सितंबर को मणिपुर के लोक भवन में राज्यपाल अजय कुमार भल्ला से भेंट वार्ता की। इस बैठक के दौरान, राज्य में रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करने, यात्रियों की सुविधा और माल परिवहन को बेहतर बनाने, सुरक्षा अवसंरचना में वृद्धि और मणिपुर में रेल सेवाओं एवं बुनियादी ढ़ांचे को और बेहतर बनाने संबंधी विषयों पर बातचीत हुई। पूसीरे के सीपीआरओ कपिंजल किशोर शर्मा ने आज बताया है कि चेतन कुमार श्रीवास्तव ने मणिपुर के मुख्यमंत्री सचिवालय में मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह से भी मुलाकात की। इस बैठक में राज्य सरकार और पूसीरे के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थें। इस अवसर पर राज्य में रेल कनेक्टिविटी, अवसंरचनात्मक विकास और यात्री सेवाओं से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में जिरिबाम और खोंगसांग के बीच पैसेंजर ट्रेन सेवाओं के सुचारू और नियमित परिचालन को सुनिश्चित करने के उपायों पर बातचीत करते हुए इस क्षेत्र के लोगों को विश्वसनीय और सुविधाजनक रेल सेवाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया। मणिपुर और गुवाहाटी के बीच सीधी रेल कनेक्टिविटी शुरू करने की संभावना पर भी चर्चा हुई, जिससे राज्य के प्रमुख शहरी और व्यावसायिक केंद्रों के साथ कनेक्टिविटी और अधिक बेहतर होगी और यात्रियों को अधिक सुविधा मिलेगी। बैठक में वंगाइचुंगपाऊ और राष्ट्रीय राजमार्ग के बीच सड़क कनेक्टिविटी में सुधार की आवश्यकता के साथ-साथ सुरक्षित और अधिक कुशल रेलवे संचालन के लिए सुरक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की भी समीक्षा की गई। बैठक में खोंगसांग टर्मिनल पर माल परिवहन के कुशल संचालन और प्रबंधन के उपायों पर भी चर्चा की गई, ताकि राज्य में सामान की आवाजाही सुलभ हो सके और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क में सुधार हो। टर्मिनल पर आरओ-आरओ (रोल-ऑन/रोल-ऑफ) सेवाओं को शुरू करने पर भी विचार-विमर्श किया गया, ताकि कुशल रेल आधारित परिवहन प्रणाली के माध्यम से सामग्रियों और वाहनों के परिवहन को सुलभ बनाया जा सके।

शिक्षक ने पत्नी और दो बच्चों पर किया कुल्हाड़ी से हमला, पत्नी, बच्चे की मौत; बेटी गंभीर

धेमाजी (हिंस)। असम के धेमाजी जिले के जोनाई के तेलाम इलाके में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। आरोप है कि एक शिक्षक ने अपने परिवार के सदस्यों पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिसमें उसकी पत्नी और एक बच्चा व एक बच्ची की मौत हो गई। वहीं एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गयी। मृतकों की पहचान पांच वर्षीय बेटी रिजिका बेगम, आठ वर्षीय पुत्र साखिल अली और 33 वर्षीय पत्नी सिनुवारा बेगम के रूप में हुई है। हमले में एक अन्य बेटी 13 वर्षीय नेइना अख्तर गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे गंभीर हालत में अस्पताल भेजा गया है। आरोपित शिक्षक की पहचान फिरोज अली के रूप में हुई है। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है।

एसकेएसी की 32 सीटों के लिए अंतिम फोटो मतदाता सूची प्रकाशित

1,63,966 मतदाता पंजीकृत, 337 मतदान केंद्र सूचीबद्ध

गुवाहाटी (हिंस)। असम सरकार द्वारा सोनोवाल कछारी स्वायत्त परिषद (एसकेएसी) के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के बाद परिषद की सभी 32 सीटों के लिए अंतिम फोटो मतदाता सूची बुधवार को प्रकाशित कर दी गई। अंतिम मतदाता सूची परिसीमन से संबंधित 6 सितंबर, 2024, 27 सितंबर, 2024 और 27 दिसंबर, 2024 को जारी अधिसूचनाओं के आधार पर तैयार की गई है। सूची के अनुसार, एसकेएसी की 32 सीटों में कुल 1,63,966 मतदाता पंजीकृत हैं। इनमें 79,295 पुरुष, 84,667 महिला और चार *अन्य* श्रेणी के मतदाता शामिल हैं। अंतिम मतदाता सूची में कुल 337 मतदान केंद्र शामिल हैं। हालांकि, मतदान केंद्रों के युक्तिकरण की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है, इसलिए इनकी संख्या में बदलाव संभव है। फोटो रहित अंतिम मतदाता सूची संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के सर्किल ऑफिसर और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के कार्यालयों के अलावा नगरपालिकाओं, टाउन कमेटियों, सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों, पुलिस थानों, चाय बागानों और गांव पंचायत कार्यालयों में मतदाताओं के निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगी। सूची ओईआरएमएस की वेबसाइट और संबंधित जिला प्रशासन की वेबसाइटों पर भी उपलब्ध होगी। मतदाता भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अपने ईपीआईसी नंबर के माध्यम से अंतिम मतदाता सूची में अपना नाम सत्यापित कर सकते हैं। इसके अलावा, ओईआरएमएस वेबसाइट के सिटीजन कॉर्नर से संबंधित मतदान केंद्र की अंतिम मतदाता सूची डाउनलोड की जा सकती है। निर्वाचन भागीदारी बढ़ाने और पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल होने का अवसर देने के उद्देश्य से आयोग ने नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि तक एसकेएसी मतदाता सूची में नाम शामिल करने के दावों पर विचार करने का निर्णय लिया है। यह सुविधा उन लोगों के लिए उपलब्ध होगी, जो 1 अप्रैल, 2026 या 1 जुलाई, 2026 के संदर्भ में मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए पात्र हुए हैं, बशर्ते उनका नाम भारत निर्वाचन आयोग द्वारा वर्तमान संक्षिप्त पुनरीक्षण के तहत प्रकाशित पूरक मतदाता सूची में शामिल हो और उनके पास वैध ईपीआईसी हो। आयोग ने सभी पात्र नागरिकों से अंतिम मतदाता सूची में अपना नाम सत्यापित करने और निर्धारित अवधि के भीतर नामांकन सुविधा का लाभ उठाने की अपील की है।

मंत्री बिमल बोरा ने जालुकबारी स्थित भूपेन हजारिका समन्वय क्षेत्र का किया दौरा

गुवाहाटी (हिंस)। गुवाहाटी के जालुकबारी स्थित डॉ. भूपेन हजारिका समन्वय तीर्थ क्षेत्र कां बुधवार की शाम को असम सरकार के सांस्कृतिक विभाग के अधिकारियों के साथ मंत्री बिमल बोरा दौरा किया। साथ ही उन्होंने वहां एक उच्च-स्तरीय बैठक की। उल्लेखनीय हैं कि आगामी 8 सितंबर को भारत रत्न डॉ. भूपेन हजारिका की जयंती मनायी जाएगी। मंत्री बोरा नें जयंती के अवसर पर होने वाले कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की। सुधाकंठ डॉ. भूपेन हजारिका का जन्मदिन 8 सितंबर को विशेष रूप से उनके समन्वय तीर्थ स्थल पर सांस्कृतिक विभाग के तत्वावधान में मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम में असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा भी मुख्य रूप से उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम की तैयारियों और व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए ही मंत्री बिमल बोरा ने आज समन्वय तीर्थ स्थल का दौरा किया।

नगांव लोकसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा की सक्रियता तेज

नगांव (हिंस)। नगांव लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। जागीरोड स्थित आवर्त भवन में मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा की मौजूदगी में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है। बैठक में नगांव लोकसभा क्षेत्र के उपचुनाव को लेकर तैयारियों और पार्टी की रणनीति पर चर्चा की जा रही है। इस बैठक में भाजपा के कई स्थानीय नेता एवं विधायक मौजूद हैं। बैठक में चुनाव से संबंधित सभी पहलुओं पर विचार किए जाने की संभावना है।

तामुलपुर में 70 करोड़ रुपए की सिंचाई परियोजनाओं की घोषणा

तामुलपुर (हिंस)। असम के कृषि एवं सिंचाई विभाग के मंत्री पीयूष हजारिका ने बुधवार को तामुलपुर जिले में सिंचाई व्यवस्था का व्यापक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के साथ-साथ युवाओं को व्यावसायिक एवं उच्च गुणवत्ता वाली कृषि की ओर प्रोत्साहित करने पर जोर दिया। कैबिनेट मंत्री एवं स्थानीय विधायक विश्वजीत दैमारी के साथ मंत्री हजारिका ने सुवनखाटा स्थित मानस चौकी का दौरा कर भूटान की पहाड़ियों से बहकर आने वाली पगलादिया नदी के पानी के उपयोग से प्रस्तावित एक बड़े कैनाल सिंचाई परियोजना की संभावनाओं की समीक्षा की। उन्होंने करीब 70 करोड़ रुपए की लागत से नई सिंचाई परियोजना विकसित करने की घोषणा की। प्रस्तावित परियोजना से लगभग 1,800 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा मिलने की उम्मीद है। इसके तहत मिनी रिजर्वायर, एक्वाडक्ट के निर्माण तथा मौजूदा स्लुइस गेट की मरम्मत और सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा के राज्य की अधिकतम कृषि भूमि को सिंचाई के दायरे में लाने के दृष्टिकोण

के अनुरूप कार्य किया जा रहा है। तमुलपुर क्षेत्र में प्रस्तावित सभी सिंचाई योजनाएं पूरी होने के बाद करीब 8,000 हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचाई के दायरे में आ जाएगी। इससे किसानों को वर्ष में तीन फसलें लेने में मदद मिलेगी। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने दरंगा नदी पर स्थित हाथीडूबा सिंचाई ढांचे की भी समीक्षा की और संबंधित अभियंताओं को इसे शीघ्र कार्यशील बनाने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने कालानदी सिंचाई योजना का निरीक्षण कर इसके विस्तार का आश्वासन दिया। तामुलपुर शहर के समीप बरलिया नदी की नहर सिंचाई व्यवस्था तथा बगामाटी में बरनदी परियोजना का भी जायजा लिया। मंत्री हजारिका ने कहा कि पूरे तामुलपुर जिले की सिंचाई जरूरतों को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर परियोजना विकसित करने की संभावनाओं पर भी विचार किया जा रहा है। इसके लिए भूटान के अंदरूनी हिस्सों से जल लाने के विकल्पों का विभाग द्वारा अध्ययन किया जाएगा। इस दौरान मंत्री ने प्रगतिशील किसान दैमालु बसुमतारी के चेसापानी स्थित कृषि फार्म का भी दौरा किया। बसुमतारी पांच बीघा भूमि पर ड्रैगन फ्रूट और छह बीघा भूमि पर सुपारी की खेती कर वर्तमान में करीब 5 लाख रुपए वार्षिक आय अर्जित कर रहे हैं। अगले पांच वर्षों में 11 बीघा भूमि से वार्षिक आय को बढ़ाकर करीब 15 लाख रुपए करने के उनके लक्ष्य की मंत्री ने सराहना की। मंत्री हजारिका ने दैमालु बसुमतारी को युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत बताते हुए कहा कि युवाओं को केवल सरकारी या निजी नौकरी के पीछे न भागकर व्यावसायिक कृषि को भी रोजगार और आत्मनिर्भरता का मजबूत माध्यम बनाना चाहिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार इस क्षेत्र में हरसंभव विभागीय सहयोग उपलब्ध कराएगी। अपने दौरे के दौरान मंत्री पीयूष हजारिका ने सेसापानी स्थित बीटीसी विधानसभा के दिवंगत उपाध्यक्ष बिजित गौरा नार्जारी के आवास पर पहुंचकर शोक संतप्त परिवार से मुलाकात की और गहरी संवेदना व्यक्त की।

कोकराझाड़ में बीपीएफ-भाजपा की समन्वय बैठक आयोजित

कोकराझाड़ (विभास)। बोड़ोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल (बीटीसी) विधानसभा के सभागार में बोड़ोलैंड पीपुल्स फ्रंट और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं व कार्यकर्ताओं की एक महत्वपूर्ण समन्वय बैठक आयोजित की गई। सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई इस बैठक की अध्यक्षता बीटीसी के मुख्य कार्यकारी सदस्य (सीईएम) एवं बीपीएफ प्रमुख हग्रामा महिलारी ने की। बैठक में दोनों दलों के बीच आपसी तालमेल को मजबूत करने और क्षेत्रीय विकास से जुड़े अहम मुद्दों पर विस्तृत विचार-विमर्श हुआ। इस दौरान भाजपा के कोकराझाड़ जिला प्रभारी शंकर प्रसाद रॉय, भाजपा जिला अध्यक्ष गोसाई बसुमतारी, बीपीएफ महासचिव व विधायक मानेश्वर ब्रह्म विशेष रूप से उपस्थित रहे। इसके अलावा बैठक में विधायक शोभाराम बसुमतारी, रूपम चंद्र रॉय, रबीराम नार्जरी, सेउली महिलारी सहित दोनों दलों के कई वरिष्ठ नेता और प्रमुख कार्यकर्ता मौजूद थे। नेताओं ने क्षेत्र के राजनीतिक परिदृश्य, जनहित के कार्यों और भविष्य की रणनीतियों को लेकर अपनी बात रखी।

भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरे वनडे के लिए टिकटों की बिक्री 4 सितंबर से

गुवाहाटी। असम क्रिकेट एसोसिएशन (एसीए) को यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा वनडे मैच, जो 30 सितंबर 2026 को गुवाहाटी के एसीए स्टेडियम में खेला जाना है, उसके लिए टिकटों की बिक्री 4 सितंबर 2026 को सुबह 11 बजे से शुरू होगी। टिकट सिर्फ बूक मायशो (बीएमएस) पर उपलब्ध होंगे। सफल बुकिंग के बाद, दर्शकों को एक रू-टिकट मिलेगा, जिससे स्टेडियम में एंट्री की प्रक्रिया आसान और सुविधाजनक होगी। असम और उसके बाहर के क्रिकेट प्रेमियों की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए टिकट की कीमतें किफायती रखी गई हैं। स्टूडेंट्स के लिए 500 अन्य कैटेगरी के स्टैंड के लिए 1,500 से शुरू की गई है। क्रिकेट प्रशंसक बूक मायशो के जरिए अपने टिकट बुक कर सकते हैं और एसीए स्टेडियम में एक और यादगार इंटरनेशनल क्रिकेट मैच का हिस्सा बन सकते हैं। टीम इंडिया की गुवाहाटी वापसी के साथ, यह मैच एसीए स्टेडियम में इंटरनेशनल क्रिकेट का एक रोमांचक दिन और शानदार माहौल पेश करेगा।

जीवन प्रेरणा और सीएम फ्लाइट योजनाएं युवाओं में उत्कृष्टता एवं नवाचार को देंगी बढ़ावा : भाजपा

गुवाहाटी (हिंस)। असम प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता डॉ. देवजीत महंत ने कहा है कि मुख्यमंत्री जीवन प्रेरणा और मुख्यमंत्री विदेशी भाषा पहल फॉर ग्लोबल ह्यूमन टैलेंट (सीएम फ्लाइट) जैसी योजनाएं राज्य के युवाओं को रोजगार, प्रतियोगी परीक्षाओं और अंतर्राष्ट्रीय रोजगार के अवसरों के लिए तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता विभाग के तहत लागू मुख्यमंत्री जीवन प्रेरणा योजना के माध्यम से पात्र स्नातक युवाओं को एक वर्ष तक प्रतिमाह 2,500 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके तहत अधिकतम 30 हजार रुपए वार्षिक सहायता मिल सकती है। डॉ. महंत ने युवाओं से इस सहायता का उपयोग यूपीएससी, एपीएससी समेत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं और सरकारी नौकरियों की तैयारी के लिए करने की अपील की। उन्होंने बताया कि 26 फरवरी, 2026 को 2025 में स्नातक पूरा करने वाले 48,319 युवाओं को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से जीवन प्रेरणा योजना का लाभ दिया गया था। मुख्यमंत्री के दूसरे कार्यकाल में योजना को फिर से शुरू किया गया और 31 अगस्त, 2026 को 48,366 स्नातक युवाओं को इसका लाभ प्रदान किया गया। इस योजना के लिए सरकार ने 118.58 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। डॉ. महंत ने सीएम फ्लाइट योजना का भी उल्लेख करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य असम के युवाओं को विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण देकर अंतर्राष्ट्रीय रोजगार के अवसरों के लिए तैयार करना है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा की 22 से 24 जनवरी 2025 तक जापान यात्रा के दौरान जापानी उद्योग जगत के नेताओं और मंत्रियों के साथ हुई बैठकों के बाद जापान के साथ सहयोग की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इसके तहत असम सरकार और जापान की एशियन वन कंपनी लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन हुआ, जिसके माध्यम से असम के युवाओं को जापानी भाषा का प्रशिक्षण और जापान के साथ-साथ भारत एवं असम में कार्यरत जापानी कंपनियों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। सीएम फ्लाइट के तहत अगले तीन वर्षों में 50 हजार से अधिक युवाओं को जापानी भाषा एवं कौशल विकास का प्रशिक्षण देने का लक्ष्य है। वित्तीय बाधाओं के कारण कोई पात्र युवा योजना के लाभ से वंचित न रहे, इसके लिए सरकार प्रशिक्षण सहायता के रूप में प्रत्येक पात्र उम्मीदवार के लिए संबंधित प्रशिक्षण एवं कार्यान्वयन एजेंसियों को एक लाख रुपए प्रदान करेगी। इसके अलावा विदेश में स्थानांतरण और शुरुआती पुनर्वास खर्चों के लिए प्रत्येक उम्मीदवार को 50,000 रुपए पोस्ट-प्लेसमेंट सहायता के रूप में दिए जाएंगे।

बोड़ोलैंड सिल्क पार्क में *मेरा रेशम मेरा अभिमान 2.0* और राष्ट्रीय रेशम प्रौद्योगिकी हस्तांतरण अभियान आयोजित

कोकराझाड़ (विभास)। बोड़ोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के रेशम उत्पादन (सेरीकल्चर) विभाग की पहल और केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय के तहत आने वाले केंद्रीय रेशम बोर्ड के सहयोग से आदाबाड़ी स्थित बोड़ोलैंड सिल्क पार्क में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम *राष्ट्रीय मेगा रेशम प्रौद्योगिकी हस्तांतरण अभियान* के तहत *मेरा रेशम मेरा अभिमान 2.0* शीर्षक से सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र के रेशम पालकों और बुनकरों तक आधुनिक तकनीक पहुंचाना, उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ाना तथा उन्नत वैज्ञानिक तौर-तरीकों का आदान-प्रदान करना है। विशेषज्ञों ने किसानों को रेशम उद्योग को अधिक लाभदायक और टिकाऊ बनाने के लिए आधुनिक तकनीकों की विस्तृत जानकारी दी। आयोजकों ने भरोसा जताया कि यह पहल बीटीसी क्षेत्र में रेशम उद्योग के विस्तार और किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण में मील का पत्थर साबित होगी। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10 बजे केंद्रीय सिल्क बोर्ड के सदस्य सचिव, बीटीसी के मुख्य कार्यकारी सदस्य, कार्यकारी सदस्यों, विधायकों और सेरीकल्चर विभाग के निदेशक के बीच एक उच्चस्तरीय बैठक से हुई। इसके बाद दिन के 11 बजे मुख्य मंच पर दीप प्रज्वलन और केंद्रीय रेशम बोर्ड, बेंगलुरु के सदस्य सचिव के स्वागत व अतिथियों के अभिनंदन के साथ मुख्य सत्र का शुभारंभ हुआ। इस दौरान बीटीसी सेरीकल्चर विभाग की निदेशक भानुलता मोसाहारी और केंद्रीय रेशम बोर्ड, बेंगलुरु के संयुक्त सचिव (तकनीकी) डॉ. नरेश बाबू एन (आईएफएस) ने *मेरा रेशम मेरा अभिमान* और बीटीसी क्षेत्र पर इसके सकारात्मक प्रभावों पर विशेष व्याख्यान दिया। कार्यक्रम में बीटीसी के रेशम विभाग के कार्यकारी सदस्य (ईएम) कर्मेश्वर राय, विधायक शिउली महिलारी, विभाग के उच्चाधिकारी, वैज्ञानिक तथा बड़ी संख्या में स्थानीय रेशम पालक उपस्थित रहे।

संपादकीय

'अंतहीन' ही रहेगा युद्ध

प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से एक बार फिर आग्रह किया है कि 'अंतहीन युद्ध' से निकल कर 'युद्ध के अंत' की ओर बढ़ें। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने प्रधानमंत्री मोदी को पश्चिम एशिया में शांति के प्रयासों और संवाद के लिए मध्यस्थ भूमिका निभाने का अनुरोध किया है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में 'शंघाई सहयोग संगठन' (एससीओ) के देशों का शिखर सम्मेलन जारी रहा और युद्ध-समाप्ति की ऐसी आवाजें बुलंद होती रहीं, लेकिन उसके समानांतर अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर एक बार फिर हमला करवा दिया। होर्मुज जलडमरूमध्य के करीब लारक द्वीप पर हमला कर दो लॉन्चर्स को तबाह करने का दावा किया गया है। दो मौतों के अलावा नुकसान काफी हुआ है। यह द्वीप फारस और ओमान खाड़ी के बीच स्थित है और बेहद महत्वपूर्ण, संवेदनशील संकरा जलमार्ग है। दुनिया के करीब 20 फीसदी तेल और गैस इसी रास्ते से सप्लाई होते रहे हैं। यहां से जहाजों पर पैनी निगरानी भी रखी जा सकती है। अमरीका इसे भी बर्बाद करने पर आमादा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया की पोस्ट में लिखा है कि ईरान द्वारा बिछाई जा रही बारूदी सुरंगों को उड़ाने के लिए यह हमला किया गया। ट्रंप ने यह भी लिखा है कि हम ईरान को बुरी तरह मारेंगे। ईरान एक नाकाम देश है। उसके पास करेंसी भी नहीं बची है। महंगाई दर 300 फीसदी है और ईरान अपने सैनिकों और पुलिस को वेतन तक नहीं दे पा रहा है। अमरीका आज की रात (मंगलवार) ईरान पर विध्वंसक हमला करेगा। हमले से पहले ही ईरान ने पलटवार कर जॉर्डन और संयुक्त अरब अमीरात समेत कतर, कुवैत, बहरीन में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले कर अमरीका को बता दिया है कि ईरान की ताकत अब भी मौजूद है। राष्ट्रपति ट्रंप पहले दावा कर चुके हैं कि अमरीका ने होर्मुज क्षेत्र को बारूदी सुरंगों से मुक्त करा दिया है। फिर यह हमला क्यों किया गया? हमले के बावजूद होर्मुज में अब भी 100 से अधिक बारूदी सुरंगें बताई जाती हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने करीब एक माह की खामोशी और हमलों को रोकने के बाद तब हमले के आदेश दिए हैं, जब अमरीका के कई सैन्य कमांडरों ने युद्ध को बढ़ाने पर 'असहमति' जताई है। 'व्हाइट हाउस' के आधा दर्जन बड़े अधिकारियों ने इस्तीफे दे दिए हैं। प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट, अमरीकी सेना के सचिव डैन ड्रिस्कॉल समेत उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, निदेशक, वकील आदि अधिकारियों ने राष्ट्रपति का साथ छोड़ दिया है। 'ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ' के अध्यक्ष जनरल डैन केन भी कह चुके हैं कि मौजूदा परिस्थितियों में ईरान को हराना असंभव-सा है। फिर भी राष्ट्रपति ट्रंप, युद्ध के छह महीने बाद भी, युद्ध को 'अंतहीन' बनाने पर आमादा हैं। युद्ध में अमरीका के अब तक 3,57,677 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। उसके वहशीपन, तानाशाह प्रवृत्ति ने करदाताओं का इतना पैसा 'फूंक' दिया है। अमरीका के 18-19 लड़ाकू विमान तबाह हो चुके हैं। उसके 18 सैनिक मारे जा चुके हैं और 750 से अधिक घायल हुए हैं। ये आंकड़े पेंटागन के हैं और शीर्ष मीडिया एजेंसियां और अखबार छाप चुके हैं। ट्रंप की लोकप्रियता 'निम्नतम' स्तर पर है और जनता में भी रोष, विद्रोह है। ईरान युद्ध में अभी तक कुल 3600 के करीब मौतें हो चुकी हैं, जबकि इजरायल में करीब 60 और लेबनान में 3527 मौतें हुई हैं। युद्ध के दौरान होर्मुज में 70 से अधिक जहाजों पर हमले किए गए, जिनमें 19 नाविक मारे गए। इनमें भारतीय भी शामिल हैं। बताया जाता है कि अब भी 400 जहाज और करीब 6000 नाविक होर्मुज और आसपास के समंदर में फंसे हैं। ईरान में महंगाई दर करीब 128 फीसदी है, जो लगातार बढ़ रही है। उपभोक्ता वस्तुएं 88 फीसदी महंगी हो चुकी हैं। बेशक ईरान के हालात बहुत खराब हैं, लेकिन अमरीका उसे घुटनों पर आने को विवश नहीं कर पाया है। युद्ध सिर्फ यहीं नहीं है। रूस-यूक्रेन के बीच साढ़े चार साल से युद्ध जारी है। यह रूस बनाम पश्चिम की तमाम ताकतों के बीच है। बर्बादी, तबाही, मिट्टी-मलबा होने का कोई हिसाब नहीं।

किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में 'शंघाई सहयोग संगठन' (एससीओ) के देशों का शिखर सम्मेलन जारी रहा और युद्ध-समाप्ति की ऐसी आवाजें बुलंद होती रहीं, लेकिन उसके समानांतर अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर एक बार फिर हमला करवा दिया। होर्मुज जलडमरूमध्य के करीब लारक द्वीप पर हमला कर दो लॉन्चर्स को तबाह करने का दावा किया गया है। दो मौतों के अलावा नुकसान काफी हुआ है। यह द्वीप फारस और ओमान खाड़ी के बीच स्थित है और बेहद महत्वपूर्ण, संवेदनशील संकरा जलमार्ग है। दुनिया के करीब 20 फीसदी तेल और गैस इसी रास्ते से सप्लाई होते रहे हैं। यहां से जहाजों पर पैनी निगरानी भी रखी जा सकती है। अमरीका इसे भी बर्बाद करने पर आमादा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया की पोस्ट में लिखा है कि ईरान द्वारा बिछाई जा रही बारूदी सुरंगों को उड़ाने के लिए यह हमला किया गया। ट्रंप ने यह भी लिखा है कि हम ईरान को बुरी तरह मारेंगे। ईरान एक नाकाम देश है। उसके पास करेंसी भी नहीं बची है। महंगाई दर 300 फीसदी है और ईरान अपने सैनिकों और पुलिस को वेतन तक नहीं दे पा रहा है। अमरीका आज की रात (मंगलवार) ईरान पर विध्वंसक हमला करेगा। हमले से पहले ही ईरान ने पलटवार कर जॉर्डन और संयुक्त अरब अमीरात समेत कतर, कुवैत, बहरीन में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले कर अमरीका को बता दिया है कि ईरान की ताकत अब भी मौजूद है। राष्ट्रपति ट्रंप पहले दावा कर चुके हैं कि अमरीका ने होर्मुज क्षेत्र को बारूदी सुरंगों से मुक्त करा दिया है। फिर यह हमला क्यों किया गया? हमले के बावजूद होर्मुज में अब भी 100 से अधिक बारूदी सुरंगें बताई जाती हैं।

कुछ अलग

बड़े साहब जी के चरणार्थ

जैसे कि आपको पता ही है कि हम चार चपरासी पिछले बीस सालों से आपके दफ्तर के दरवाजे पर बैठ आपके लिए काम करवाने आने वालों से आपके कहेनुसार रेट वसूलते रहे हैं। हमसे रेट वसूलवाते पता नहीं आप जैसे कितने बड़े साहब आए और आकर चले गए। पर हम वहीं के वहीं रहे साहब जी! हे सबसे बड़े साहब जी! हमारे द्वारा वसूला रेट ऊपर तक जाता है, जैसा कि हमें बताया गया है। इसमें हमें कोई आपत्ति भी नहीं कि हमारे द्वारा जनता से वसूला रेट कहां जाता है? जहां जाता हो, वहां जाता रहे। अपना काम तो बस, काम करवाने आयों से आपके द्वारा तय रेट वसूलने के बाद ही उसे दफ्तर में प्रवेश करने की इजाजत देना है। और इस काम को पिछले बीस सालों से हम पूरी कत्र्तव्यनिष्ठा और ईमानदारी से निभाते भी आ रहे हैं। हमने बिन रेट लिए आपके दफ्तर में आज तक किसी को घुसने नहीं दिया। चाहे वह यमराज ही क्यों न हो। लेकिन हमारी इस ईमानदारी और कत्र्तव्यनिष्ठा के बाद भी हम वहीं के वहीं बैठें हैं।

हिमालय में खतरे का स्वरूप बदल रहा है और हमारी तैयारी अभी भी पुराने ढर्रे पर चल रही

नेपाल की बाढ़ से भारत को लेना होगा सबक

नेपाल चीन सीमा पर 26 अगस्त को आई विनाशकारी बाढ़ ने हिमालय को लेकर हमारी सोच पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मृतकों की संख्या 900 के पार पहुंच चुकी है और 4200 से अधिक लोग अब भी लापता हैं लेकिन यह त्रासदी केवल मौतों और तबाही का आंकड़ा नहीं है। इसका सबसे बड़ा संदेश यह है कि हिमालय में खतरे का स्वरूप बदल रहा है और हमारी तैयारी अभी भी पुराने ढर्रे पर चल रही है। सवाल यह नहीं है कि अगली आपदा कब आएगी, सवाल यह है कि क्या हम अगली आपदा से पहले कुछ सीख पाएंगे? हम आमतौर पर बाढ़ को भारी बारिश से जोड़कर देखते हैं। बारिश हुई, नदी का जलस्तर बढ़ा और बाढ़ आ गई लेकिन इस बार कहानी कुछ अलग थी। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के प्रारम्भिक आकलन के अनुसार शुरुआत में ग्लेशियर का बर्फ और चट्टानों का मलबा तेज ढलान पर तेजी से नीचे आया और रास्ते में पानी तथा दूसरी सामग्री को अपने साथ मिलाता हुआ आगे बढ़ा। आईसीआईएमओडी ने भी ऊंचाई वाले क्षेत्र में संभावित आइस-रॉक एवलॉन्च को घटना का संदिग्ध ट्रिगर माना है, यानी बाढ़ का असली खतरा उस जगह पैदा हुआ जहां नीचे नदी किनारे रहने वाले लोगों की नजर ही नहीं पहुंच सकती थी। यही हिमालयी आपदाओं की सबसे बड़ी चुनौती है। ऊंचाई पर ग्लेशियर या चट्टान टूटती है, नदी का रास्ता रुकता है, पानी जमा होता है और फिर प्राकृतिक अवरोध टूटने पर पानी, मिट्टी, पत्थर और पेड़ों का सैलाब नीचे की ओर दौड़ता है। एक घटना दूसरी घटना को जन्म देती है। इसे 'कैस्केडिंग डिजास्टर' कहा जाता है। नेपाल की इस त्रासदी ने दिखाया है कि कुछ ही समय में ऐसा खतरा कितनी बड़ी तबाही में बदल सकता है।

मृतकों की संख्या 900 के पार पहुंच चुकी है और 4200 से अधिक लोग अब भी लापता हैं लेकिन यह त्रासदी केवल मौतों और तबाही का आंकड़ा नहीं है। इसका सबसे बड़ा संदेश यह है कि हिमालय में खतरे का स्वरूप बदल रहा है और हमारी तैयारी अभी भी पुराने ढर्रे पर चल रही है। सवाल यह नहीं है कि अगली आपदा कब आएगी, सवाल यह है कि क्या हम अगली आपदा से पहले कुछ सीख पाएंगे? हम आमतौर पर बाढ़ को भारी बारिश से जोड़कर देखते हैं। बारिश हुई, नदी का जलस्तर बढ़ा और बाढ़ आ गई लेकिन इस बार कहानी कुछ अलग थी। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के प्रारम्भिक आकलन के अनुसार शुरुआत में ग्लेशियर का बर्फ और चट्टानों का मलबा तेज ढलान पर तेजी से नीचे आया और रास्ते में पानी तथा दूसरी सामग्री को अपने साथ मिलाता हुआ आगे बढ़ा।

चेतावनी है, लेकिन क्या सही खतरे की?

नेपाल में बाढ़ और मौसम की निगरानी के लिए नदी जलस्तर केंद्र, स्वचालित मौसम स्टेशन, मौसम रडार, हिमपात निगरानी, हिमनद और हिमनद झीलों की निगरानी तथा सामुदायिक चेतावनी व्यवस्था मौजूद है। आईसीआईएमओडी की फ्लैश फ्लड प्रणाली भी हजारों नदी खंडों में संभावित खतरे का अनुमान लगाती है। फिर भी इस बार चेतावनी व्यवस्था की सीमा सामने आ गई। आईसीआईएमओडी के मुताबिक त्रिशूली नदी के एक हिस्से में जलस्तर करीब 30 मिनट में नौ मीटर तक बढ़ गया। कई निगरानी केंद्र भी क्षतिग्रस्त हो गए। इसलिए अब सवाल यह नहीं होना चाहिए कि अर्ली वार्निंग सिस्टम है या नहीं। सवाल यह है कि क्या वह उस खतरे को पहचान सकता है जो नदी में पानी बढ़ने से पहले पहाड़ के भीतर पैदा हो चुका है? हमें नदी की निगरानी से आगे बढ़कर पूरे पर्वतीय तंत्र की निगरानी करनी होगी। कौन-सा ग्लेशियर बदल रहा है? कौन-सी हिमनद झील तेजी से बढ़ रही है? कहां ढलान अस्थिर है? कहां प्राकृतिक बांध बन रहा है? किन घाटियों में मलबे के साथ अचानक बाढ़ आने का खतरा है? इन सवालों के जवाब खोजने होंगे।

जरूरी है सही जगह निर्माण

लेकिन केवल तकनीक इस समस्या का समाधान नहीं है। चेतावनी मिल भी जाए तो सवाल रहेगा कि लोगों को ले जाएंगे कहां? किसी गांव के मोबाइल पर चेतावनी संदेश पहुंचना तभी उपयोगी है, जब वहां रहने वाले व्यक्ति को पहले से मालूम हो कि सुरक्षित स्थान कहां है, किस रास्ते से जाना है और कितनी देर में वहां पहुंचना है। हिमालय के पुराने समाजों ने अपने अनुभव से यह बात समझी थी। लोग अक्सर नदी के बिल्कुल किनारे नहीं, अपेक्षाकृत सुरक्षित और ऊंचे स्थानों पर घर बनाते थे। आधुनिक विकास के दौर में हमने इस स्थानीय समझ को काफी हद तक भुला दिया है। आज नदी किनारे होटल, मकान और होमस्टे बन रहे हैं। पहाड़ काटकर सड़कें बनाई जा रही हैं। सुरंगें खोदी जा रही हैं और जलविद्युत परियोजनाएं स्थापित हो रही हैं। विकास जरूरी है लेकिन हर जगह निर्माण करना विकास नहीं हो सकता। हमें यह तय करना होगा कि कौन-सी जमीन रहने योग्य है और कौन-सी नहीं। नदी के डूब क्षेत्र से बाहर बस्तियां बसाना और जोखिम वाले इलाकों में निर्माण सीमित करना जरूरी है।

एक परियोजना नहीं, पूरे पहाड़ का हिसाब

हिमालय को टुकड़ों में देखने की हमारी आदत भी खतरे को बढ़ा रही है। एक सड़क को अलग परियोजना माना जाता है, एक बांध को अलग, एक होटल को अलग और एक सुरंग को अलग लेकिन पहाड़ इन्हें अलग-अलग नहीं देखता। एक ही घाटी में सैकड़ों निर्माण हों तो उनका सामूहिक असर नदी के रास्ते, जल निकासी और ढलानों की स्थिरता पर पड़ सकता है। इसलिए अब हर बड़ी परियोजना के साथ उसके संचयी प्रभाव का आकलन जरूरी है। सवाल यह भी होना चाहिए कि यदि अत्यधिक बारिश हो, ग्लेशियर का बड़ा हिस्सा टूटे, भूस्खलन हो या मलबे का सैलाब आए तो पूरी घाटी पर क्या असर पड़ेगा? सिर्फ पिछले 50 या 100 वर्षों के मौसम के आंकड़ों से भविष्य की सुरक्षा तय करना भी पर्याप्त नहीं है। हिमालय स्थिर भूगोल नहीं है। बदलते तापमान, ग्लेशियरों में परिवर्तन और मौसम की चरम घटनाओं के बीच पुराने आंकड़े भविष्य का पूरा जोखिम नहीं बता सकते।

सुरंग और बांध भी जोखिम से बाहर नहीं

नेपाल की घटना के बाद भारत में हिमालयी राज्यों की सुरंगों और जलविद्युत परियोजनाओं की सुरक्षा पर भी ध्यान बढ़ना स्वाभाविक है। खासकर हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में जहां सड़क सुरंगों और जलविद्युत परियोजनाओं का विस्तार तेजी से हुआ है। सवाल यह नहीं कि सुरंगें बनाई जाएं या नहीं। सवाल यह है कि निर्माण से पहले भूगर्भीय स्थिति को कितनी गंभीरता से समझा गया। चट्टानों की स्थिरता, पानी का रिसाव, भूमिगत दबाव और निर्माण के दौरान होने वाले बदलावों की वास्तविक समय में निगरानी हो रही है या नहीं। हिमालय में सुरंग खोदना सामान्य निर्माण कार्य नहीं है। यहां हर मीटर खुदाई के साथ पहाड़ की आंतरिक संरचना बदलती है। इसलिए आधुनिक रॉक सपोर्ट, भूगर्भीय सर्वेक्षण और रियल-टाइम निगरानी को परियोजना की अनिवार्य शर्त बनाया जाना चाहिए। स्रोत में भी इसी तरह की सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी की जरूरत रेखांकित की गई है।

पर्यटन को भी बदलनी होगी अपनी रफ्तार

हिमालय में पर्यटन रोजगार और अर्थव्यवस्था का बड़ा आधार है, लेकिन क्या हर पहाड़ी शहर अनियंत्रित पर्यटक भीड़ का दबाव झेल सकता है? किसी शहर की सड़क, पानी, सीवरेज, कचरा प्रबंधन और आपातकालीन निकासी क्षमता सीमित है तो पर्यटकों की संख्या भी उसी के अनुरूप होनी चाहिए। संवेदनशील क्षेत्रों में नियंत्रित प्रवेश, डिजिटल परमिट और मौसम के अनुसार पर्यटकों की संख्या तय करने जैसे उपायों पर गंभीरता से विचार करना होगा। पर्यटन का मतलब केवल ज्यादा लोग और ज्यादा कमाई नहीं है। सुरक्षित पर्यटन ही टिकाऊ पर्यटन है।

भारत के लिए सबसे बड़ी चेतावनी

नेपाल की बाढ़ का एक और पहलू भारत के लिए रणनीतिक महत्व रखता है। हिमालय पर देशों की सीमाएं हैं, लेकिन नदियों की नहीं। तिब्बत में पैदा हुआ खतरा नेपाल तक पहुंच सकता है और वहां से भारत तथा आगे बांग्लादेश तक असर डाल सकता है।

देश दुनीया से

जब जलवायु घर छीन रही हो, कानून को छत बनना होगा

बाढ़ और कटाव से घर उजड़ते हैं, परिवारों का भविष्य भी बह जाता है; लेकिन कानून में उनके लिए कोई ठिकाना नहीं। भारत में जलवायु परिवर्तन अब भविष्य की चेतावनी नहीं, लाखों लोगों की वर्तमान त्रासदी है। 2024 में जलवायु संबंधी आपदाओं से 54 लाख आंतरिक विस्थापन दर्ज हुए—दक्षिण एशिया में सबसे अधिक। करीब दो-तिहाई बाढ़ से जुड़े थे। 2022 में यह आंकड़ा 25 लाख था। असम, सुंदरबन, ओडिशा और बिहार के नदी-तटीय इलाकों में परिवार हर साल घर, खेत और पहचान खो रहे हैं। फिर भी अब तक (2026) ऐसा कोई कानून नहीं, जो उन्हें 'जलवायु विस्थापित' मानकर अधिकार तय करे। आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 तत्काल राहत तक सीमित है; स्थायी पुनर्वास और मुआवजे का अधिकार कानून से बाहर है। नदी का पानी उतर जाए तो आदमी घर लौट सकता है, लेकिन कटाव जमीन निगल जाए तो लौटने को कुछ बचता नहीं। यही नदी-कटाव को बाढ़ से अधिक क्रूर बनाता है। ब्रह्मपुत्र 1950 के बाद से असम की 4.27 लाख हेक्टेयर जमीन निगल चुकी है। माजुली द्वीप 1970 के दशक में 1,250 वर्ग किलोमीटर था, जो अब 350-600 वर्ग किलोमीटर रह गया है। सरकारी आंकड़े 2014-24 के बीच 17,390 लोगों के विस्थापन की बात करते हैं, जबकि संसद में दिए जवाब 86 हजार से अधिक लोगों की भूमिहीनता बताते हैं। तटबंधों या सरकारी जमीन पर बसे परिवार 'अतिक्रमणकारी' कहलाते हैं। भूमि अधिग्रहण कानून 2013 में राज्य जमीन ले तो मुआवजा है; नदी ले जाए तो न अधिग्रहण माना जाता है, न मुआवजा। सबसे गहरी चोट तब लगती है, जब जमीन का अस्तित्व मिट गया हो और उसी का कागज मांगकर इंसान को राहत से बाहर कर दिया जाए। संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन, आजीविका और आश्रय का अधिकार देता है, लेकिन अदालतें भी इस संकट का व्यापक समाधान नहीं कर पाई हैं। गौहाटी उच्च न्यायालय ने कुछ मामलों में राहत दी है, पर व्यापक नीति नहीं बनी। असम की 2020 की पुनर्वास नीति 2023 में संशोधित/आंशिक रूप से वापस ली गई। पंद्रहवें वित्त आयोग ने कटाव प्रभावितों के लिए अलग फंड की सिफारिश की थी और 2024 में केंद्र ने कुछ दिशानिर्देश जारी किए, मगर जमीनी पहुंच सीमित है। दस्तावेजों की शर्त उस परिवार के सामने है, जिसकी जमीन और कागज दोनों नदी में समा चुके हैं। उजड़ना केवल गांव छोड़ना नहीं है; यह आदमी को उसकी पुरानी पहचान से भी बेदखल कर देता है। सुंदरबन में बढ़ती लवणता खेती और मछली पालन खत्म कर रही है। खेत और पानी जब रोजी छीन लेते हैं, तो परिवार शहरों की ओर जाता है। वहां झुग्गियों में नई जिंदगी शुरू होती है—मगर अधिकारों के बिना। कोई राष्ट्रीय रजिस्टर, स्पष्ट नोडल एजेंसी नहीं है। 2022 का निजी सदस्य विधेयक—क्लाइमेट माइग्रेंट्स (प्रोटेक्शन एंड रिहैबिलिटेशन) बिल—संसद में आगे नहीं बढ़ सका। इस बीच जलवायु विस्थापन अस्थायी घटना नहीं, स्थायी और संरचनात्मक संकट बनता जा रहा है। व्यवस्था फिर भी उसे 'आपदा' की छोटी अवधि में बांधकर देख रही है। दुनिया के दूसरे हिस्सों में कानून ने बदलती जलवायु की आहट सुन ली है, लेकिन भारत में उजड़े लोगों की आवाज व्यवस्था की दीवारों से टकराकर लौट आती है। बांग्लादेश और फिजी ने जलवायु विस्थापितों को कानूनी पहचान देने की दिशा में कदम उठाए हैं। ऑस्ट्रेलिया-तुवालु समझौता बताता है कि जलवायु आवागमन को कानूनी ढांचे में जगह दी जा सकती है। भारत में कार्बन सेस और पर्यावरणीय जुर्माने से समर्पित फंड बनाने के प्रस्ताव हैं, लेकिन राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव है। जब बांध या हाईवे परियोजना से विस्थापित व्यक्ति को मुआवजा और पुनर्वास मिलता है, तो प्रकृति से उजड़े परिवार को क्यों नहीं?

जमीन जाने का दर्द उसके कारण से कम नहीं होता। इस कानून-विहीनता का सबसे भारी बोझ उन्हीं पर पड़ता है, जो पहले ही गरीबी ढो रहे हैं। आदिवासी, दलित और गरीब किसान जलवायु विस्थापन के सबसे असुरक्षित शिकार हैं। उनके लिए जमीन केवल संपत्ति नहीं, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और पीढ़ियों की पहचान है। जमीन जाने के साथ बच्चों की पढ़ाई, रोजी और समुदाय से जुड़ाव टूटता है। उनकी आवाज संसद तक पहुंचना कठिन है। चुनावी घोषणापत्रों में जलवायु विस्थापन का उल्लेख नहीं के बराबर है और सरकारी सर्वेक्षणों में भी यह प्राथमिकता नहीं बन पाया। जब विस्थापितों को कानून कोई नाम नहीं देता, तो उनके अधिकारों की मांग भी अनसुनी रह जाती है। यह केवल प्रशासनिक कमी नहीं, संवैधानिक समानता का गंभीर प्रश्न है। अब राहत की घोषणा से आगे बढ़कर ऐसे कानून की जरूरत है, जो उजड़ने के बाद भी नागरिक को अकेला न छोड़े। समर्पित कानून जलवायु विस्थापितों को स्पष्ट पहचान दे, पंजीकरण करे, पुनर्वास को अधिकार बनाए, और स्थायी फंड सुनिश्चित करे। भूमि खोने वालों को दस्तावेजी अड़चनों से राहत मिले तथा आवास, आजीविका और सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था हो। अनुच्छेद 21 और राज्य के नीति-निर्देशक तत्व इसका संवैधानिक आधार दे सकते हैं। पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप अलग कोष बनाया जा सकता है। कार्बन सेस और पर्यावरणीय जुर्मानों से भी संसाधन जुटाए जा सकते हैं। सवाल यह नहीं कि उपाय संभव हैं या नहीं; सवाल है कि राजनीतिक इच्छा कब पैदा होगी।

आप का नजरीया

सियासी आपूर्ति का दरिया

हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मांग और आपूर्ति का चिट्ठा खोलते प्रश्न बताते हैं कि कुछ अनावश्यक ढांचा हमने अपना लिया है। विधायक रणधीर शर्मा के प्रश्न के उत्तर में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि डिनोटिफाई 1526 स्कूलों में 734 ऐसे स्कूल हैं, जहां एक भी छात्र नहीं था। अगर इसी तरह हर विभाग की कार्यक्षमता का हवाला सामने आए तो यकीनन कई सफेद हाथी सामने आएंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में चंबा मेडिकल कालेज का जिक्र स्वयं मुख्यमंत्री ने किया है जहां फैकल्टी पूरी तरह कायम रखने के लिए आज भी जद्दोजहद करनी पड़ती है। यानी मांग और आपूर्ति के जिस हिसाब से शिक्षण व मेडिकल संस्थान खुले हैं, उनकी उपयोगिता सिद्ध करने की बुनियाद पर संदेह है। क्या चंबा में मेडिकल कालेज की स्थापना से चिकित्सकीय सेवाएं मुकम्मल होंगी या आधा चंबा जिला आज भी कांगड़ा के टीएमसी में खुद को सुविधाजनक पाता है। हमने एम्स को अहम व सत्ता के प्रभाव में तोलते हुए जो स्थान चयनित किया, क्या वह उचित निर्णय था या साबित हो रहा है। राजनीति गवाह है कि किस तरह हमारी सरकारों ने केंद्रीय विश्वविद्यालय से धर्मशाला की जमीन खींच ली। यहां कार्यालयों का भवन और संस्थानों को इमारतों की तरह देखते हुए क्षेत्रीय असंतुलन की एक प्रतिस्पर्धा दशकों से जारी है। हमने शहरीकरण को इसकी मांग के आधार पर नहीं समझा, बल्कि राजनीतिक आधार पर नगर निगमों के गठन में समझा। प्रदेश की सबसे बड़ी औद्योगिक व शहरी आबादी बीबीएन में तकरीबन चार लाख है, तो क्या हम वहां की भौगोलिक, औद्योगिक, रिहायशी व नागरिक सुविधाओं की मांग को पूरा कर पाए। आश्चर्य यह कि जहां राजनीति का प्रभाव बढ़ गया, वहां शिक्षा-चिकित्सा, शहरी समाधान, बिजली व जलापूर्ति के प्रतिमान बढ़ गए। प्रदेश में परिवहन की मांग को जिस तरह निजी क्षेत्र ने समझा है, क्या उस स्तर का सोच सार्वजनिक क्षेत्र में पैदा हुआ। इतिहास गवाह है कि घाटे के बावजूद हर सरकार ने राजनीतिक बस डिपो बढ़ा दिए, जबकि मांग अलग जिरह करती रही। प्रदेश में कुछ ही सालों में निजी वोल्वो बसों का बेड़ा ढाई सौ के करीब पहुंच गया है, तो इस मांग को बाखूबी समझा गया। दूसरी ओर एचआरटीसी ने अगर 26 नई वोल्वो बसें जोड़ी भी, तो उनका तकाजा न बदला। हिमाचल में पर्यटन क्षेत्र को समझने में भी सरकारी पक्ष की कमजोरी प्रदर्शित होती है। अब फोरलेन परियोजनाओं ने जिस तरह हाईवे टूरिज्म को बूस्ट दिया है, क्या उस परिप्रेक्ष्य में योजनाएं बनी हैं। आखिर टूरिस्ट जिस मौज मस्ती से या के लिए हिमाचल आना चाहता है, क्या हमने उस तस्वीर की आपूर्ति की है। हमने मंदिरों की आय को मंदिरों या श्रद्धालुओं की मांग पर आधारित नहीं किया, बल्कि इन्हें भी अनावश्यक रोजगार का गुलाम बना दिया। सदन की बहस में मांग और आपूर्ति का हिसाब करते हर सत्र गुजर जाता है, लेकिन हमारी नीतियां, कार्यक्रम और खाके पूरे नहीं होते। आज भी विधायक अपने क्षेत्रों में पुलिस चौकी या थाने, फायर ब्रिगेड का दफ्तर, विभागीय दफ्तर, बस रूट, जलापूर्ति, विद्युत आपूर्ति या किसी नए स्कूल-कालेज, डिस्पेंसरी या पशु औषधालय की मांग करते हैं, तो इसकी आपूर्ति का न्यायोचित फैसला होना चाहिए। राजनीति में सत्ता पक्ष ही वजीफे का हकदार नहीं होना चाहिए। आश्चर्य है कि सरकारें बदलते ही नीतियां बदल जातीं, स्वीकृत योजनाओं-परियोजनाओं की गति थम जाती। बजट का आबंटन हास परिहास का विषय या सियासत का शिलालेख बन जाता है, जबकि भौगोलिक मांग किसी अधूरे भवन की छाती पर मूंग दलती दिखाई देती है। प्रदेश की जरूरतें सियासी कद को नहीं बढ़ातीं, बल्कि इनकी कुशल आपूर्ति के लिए सख्त, संतुलित और पारदर्शी नीतियां चाहिएं।

विधायक रणधीर शर्मा के प्रश्न के उत्तर में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि डिनोटिफाई 1526 स्कूलों में 734 ऐसे स्कूल हैं, जहां एक भी छात्र नहीं था। अगर इसी तरह हर विभाग की कार्यक्षमता का हवाला सामने आए तो यकीनन कई सफेद हाथी सामने आएंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में चंबा मेडिकल कालेज का जिक्र स्वयं मुख्यमंत्री ने किया है जहां फैकल्टी पूरी तरह कायम रखने के लिए आज भी जद्दोजहद करनी पड़ती है। यानी मांग और आपूर्ति के जिस हिसाब से शिक्षण व मेडिकल संस्थान खुले हैं, उनकी उपयोगिता सिद्ध करने की बुनियाद पर संदेह है। क्या चंबा में मेडिकल कालेज की स्थापना से चिकित्सकीय सेवाएं मुकम्मल होंगी या आधा चंबा जिला आज भी कांगड़ा के टीएमसी में खुद को सुविधाजनक पाता है। हमने एम्स को अहम व सत्ता के प्रभाव में तोलते हुए जो स्थान चयनित किया, क्या वह उचित निर्णय था या साबित हो रहा है। राजनीति गवाह है कि किस तरह हमारी सरकारों ने केंद्रीय विश्वविद्यालय से धर्मशाला की जमीन खींच ली। यहां कार्यालयों का भवन और संस्थानों को इमारतों की तरह देखते हुए क्षेत्रीय असंतुलन की एक प्रतिस्पर्धा दशकों से जारी है। हमने शहरीकरण को इसकी मांग के आधार पर नहीं समझा, बल्कि राजनीतिक आधार पर नगर निगमों के गठन में समझा। प्रदेश की सबसे बड़ी औद्योगिक व शहरी आबादी बीबीएन में तकरीबन चार लाख है, तो क्या हम वहां की भौगोलिक, औद्योगिक, रिहायशी व नागरिक सुविधाओं की मांग को पूरा कर पाए। आश्चर्य यह कि जहां राजनीति का प्रभाव बढ़ गया, वहां शिक्षा-चिकित्सा, शहरी समाधान, बिजली व जलापूर्ति के प्रतिमान बढ़ गए।

दृष्टि कोण

किसानों-पशुपालकों के समक्ष चुनौतियां

हमारे देश की 75 प्रतिशत से अधिक आबादी गांवों में रहती है। कृषि एवं पशुपालन मुख्य व्यवसाय होने के कारण उन्हें अपनी मेहनत के अनुसार आय नहीं हो रही है। केन्द्र या प्रदेश सरकार इस वर्ग के समस्याओं के प्रति संवेदनशील नहीं हैं। सिंचाई की पर्याप्त सुविधा न होने के कारण प्रकृति से सामंजस्य स्थापित करके रात दिन कड़ी मेहनत करके कृषक देश की खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है। किसानों एवं पशुपालकों के सामने अनेक चुनौतियां हैं। नतीजतन अब उपजाऊ भूमि बंजर होने लगी है तथा पशुपालकों के ज्यादातर पशु सडकों, गलियों और चैराहों में भटक रहे हैं। ग्रामीणों को लग रहा है कि अब खेतीबाड़ी करना और पशुपालन व्यवसाय घाटे का सौदा हो गया है। इसलिए अब ग्रामीण युवा रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन करने लगे हैं। इसलिए कृषि एवं पशुपालन का काम न के बराबर हो गया है। पहले शहरों के लिए गांव से अनाज और दूध वितरित होता था। अब स्थिति यह हो गई है कि शहरों से आटा, दाल, सब्जी और फल इत्यादि गांव के लिए वितरित हो रहे हैं। यह भी तर्कसंगत रहा कि खेतीबाड़ी एवं पशुपालन व्यवसाय से ग्रामीण स्तर की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती रही है, जबकि देश के विकास का रास्ता गांव से होकर गुजरता है। अर्थात ग्रामीण क्षेत्र जितने विकसित होंगे, देश की आर्थिक व्यवस्था उतनी ही मजबूत होगी। पशुपालन से कस्बों से लेकर बड़े शहरों तक दूध की आपूर्ति हो रही है। स्वस्थ समाज के लिए जितना अन्न आवश्यक है उतना ही दूध भी आवश्यक है। एक लोक कहावत 'गाय न बच्छी नींद पई अच्छी' प्रचलित है। यानी कृषि एवं पशुपालन ग्रामीण जीवन शैली का आधार है। यदि किसान के पास पशु नहीं होंगे तो कृषि कार्यों में उसकी सक्रियता नहीं रहेगी। उपरोक्त लोक कहावत का यह अर्थ है कि यदि किसान के पास गाय या बछड़ी अर्थात पशु नहीं होंगे तो वह कोई मेहनत नहीं करेगा। इसलिए उसकी नींद भी समय पर नहीं खुलेगी। उसे चिंता नहीं होगी कि उसने पशुओं के लिए घास-पानी की व्यवस्था करनी है। डिजिटल इंडिया के कार्यान्वयन के बाद केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार आए दिन किसानों के लिए नई-नई समस्याएं खड़ी कर रही है तथा थोड़े से अनुदान के लिए नियम इतने कड़े कर दिए हैं कि किसान को खेत में काम करने के बजाय औपचारिकताएं पूरी करने के लिए भागदौड़ करनी पड़ती है। इससे उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। फसल की बुआई के समय किसान का एक एक पल बहुमूल्य होता है। यह काम ज्यादातर बारिश पर ही निर्भर करता है। बारिश के पानी से खेत में नमी थोड़े ही समय के लिए रहती है। पर्याप्त मात्रा में नमी न होने से बीज में अंकुर नहीं फूटते। ऐसी स्थिति में किसान को अगली बारिश के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है। कई बार समय पर बारिश नहीं होती। इसलिए फसल पर शुरू से ही संकट मंडराने लगता है। केंद्र की मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की। इस योजना के अंतर्गत खाद, बीज, कीटनाशक दवाइयों के लिए किसानों को सालाना 6 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। यह राशि साल में तीन किस्तों में मिलती है। शुरू में उन लोगों को भी किसान निधि का लाभ मिल गया, जिनके पास एक बीघे से कम भूमि थी, लेकिन उन किसानों को यह राशि नहीं मिली जिनके पास पांच बीघे से अधिक जमीन थी। कुछ सुधार होने के बाद किसानों को आईडी बनाने के चक्कर में डाल दिया। इसके लिए किसान की भूमि ऑनलाइन होनी जरूरी है। कई जिलों में बनी नई तहसीलों और उप-तहसीलों में किसानों की जमीन ऑनलाइन नहीं हुई। यदि हुई है तो उसमें दिक्कत आ रही है।

आठ वार्डों में रहेगा दिलचस्प मुकाबला, महिला प्रत्याशी दे रही हैं पुरुष प्रत्याशियों को चुनौती

उदयपुर (हिंस)। उदयपुर में नगर निगम चुनाव में नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद वार्डवार चुनावी तस्वीर साफ होने लगी है। भाजपा और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबले के बीच आठ वार्ड ऐसे हैं, जहां महिला प्रत्याशी पुरुष उम्मीदवारों को चुनौती दे रही हैं। इन सीटों पर अब प्रत्याशियों की व्यक्तिगत पकड़, जनसंपर्क, स्थानीय मुद्दे और जातीय समीकरण चुनावी नतीजों की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। वार्ड नंबर 9 में भाजपा ने महिला प्रत्याशी मीना बंधु को उतारा है, उसके सामने कांग्रेस के हर्ष पंवार मैदान में हैं। इसी तरह, वार्ड नंबर 79 में भाजपा ने महिला प्रत्याशी संतोष मीणा को उतारा है, जबकि वहां कांग्रेस के बाबूलाल गमेती मैदान में हैं। वार्ड 24 में भाजपा के पारस सिंघवी को कांग्रेस की दीपिका कुमावत चुनौती दे रही हैं। वार्ड 25 में भाजपा के लोकेश साहू और कांग्रेस की नेहा कुमावत आमने-सामने हैं। वार्ड 28 में भाजपा के विजय आहूजा का मुकाबला कांग्रेस की महिमा चुग से है।

ईडी के सबूत साझा करने तक मनी लांड्रिंग मामले में एफआईआर नहीं : अमन अरोड़ा

चंडीगढ़ (हिंस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से पंजाब पुलिस को *कैश फॉर ट्रांसफर और लैंड फ्रॉड* मामले में कथित मनी लॉड्रिंग को लेकर एफआईआर दर्ज करने के लिए, भेजे गए पत्रों के बीच आम आदमी पार्टी (आआपा) पंजाब के अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने बुधवार को कहा कि जब तक ईडी पंजाब पुलिस के साथ पुख्ता और स्पष्ट सबूत साझा नहीं करती, तब तक एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती। 31 अगस्त को ईडी की ओर से पंजाब पुलिस को भेजे गए तीसरे पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए अरोड़ा ने आरोप लगाया कि पूरा मामला केंद्र की भाजपा सरकार की ओर से शुरू किया गया राजनीतिक बदनाम करने का अभियान है। उन्होंने केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया। अरोड़ा ने कहा कि ईडी की ओर से भेजी गई जानकारी स्पष्ट और पढ़ने योग्य नहीं है। उन्होंने कहा कि कभी ईडी उनका नाम लेती है, कभी कैबिनेट सहयोगी लाल चंद कटारुचक का और संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार भी किया जा चुका है, लेकिन उनके अनुसार इन मामलों में अब तक कोई ठोस आधार सामने नहीं आया है। ईडी ने पंजाब सरकार के 28 अगस्त के पत्र के जवाब में भेजे गए पत्र में पहले साझा की गई मनी लांड्रिंग संबंधी जानकारी के आधार पर तत्काल एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। एजेंसी ने कहा है कि उसके पहले पत्र को भेजे हुए 30 दिन बीत चुके हैं और देरी से सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका पैदा हो सकती है। ईडी ने पंजाब पुलिस के उस अनुरोध को भी खारिज कर दिया है, जिसमें एफआईआर दर्ज करने से पहले अतिरिक्त प्रारंभिक जांच रिपोर्ट मांगी गई थी। ईडी और पंजाब पुलिस के बीच यह पत्राचार इस साल मई की शुरुआत में निखिल गोहल से जुड़े परिसरों पर हुई ईडी की तलाशी के बाद सामने आया। ईडी का दावा है कि तलाशी के दौरान कथित *कैश फॉर ट्रांसफर और लैंड फ्रॉड* नेटवर्क से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए थे। अरोड़ा ने कहा कि पंजाब सरकार पहले ही अपना रुख स्पष्ट कर चुकी है कि ईडी द्वारा स्पष्ट और पढ़ने योग्य सबूत उपलब्ध कराने के बाद ही एफआईआर दर्ज की जाएगी। उन्होंने दावा किया कि पुलिस को भेजे गए दस्तावेजों की प्रतियां और ट्रैपशॉट स्पष्ट नहीं हैं। अपने खिलाफ ईडी की जांच को लेकर अरोड़ा ने कहा कि एजेंसी ने उनके मित्र गौरव धीर को निशाना बनाकर उन तक पहुंचने की कोशिश की। उन्होंने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि धीर के अल्टस प्रोजेक्ट से संबंधित छह सीएलयू वर्ष 2011 से 2022 के बीच मंजूर किए गए थे, जब राज्य में शिअद-भाजपा और कांग्रेस की सरकारें थीं। उन्होंने दावा किया कि प्रोजेक्ट के लेआउट प्लान में भी दो बदलाव पिछली सरकारों के कार्यकाल में, जबकि तीन बदलाव आप सरकार के दौरान हुए। अरोड़ा के अनुसार, ये बदलाव कानूनी प्रक्रिया के तहत किए जा सकते हैं। ईडी के उस आरोप को भी अरोड़ा ने निराधार बताया, जिसमें कथित तौर पर डेवलपर द्वारा जमीन गमाडा को वापस बेचने को गौरव धीर को लाभ पहुंचाने से जोड़ा गया है। अरोड़ा ने कहा कि इस मामले का आधार बने दो एफआईआर को अदालत पहले ही रद्द कर चुकी है। फिलहाल ईडी और पंजाब पुलिस के बीच इस मामले को लेकर पत्राचार जारी है। एफआईआर दर्ज करने को लेकर दोनों पक्षों के बीच मतभेद बने हुए हैं।

बिजली निजीकरण की तैयारी कर रही भाजपा सरकार : आदित्य सुरजेवाला

कैथल (हिंस)। कांग्रेस विधायक आदित्य सुरजेवाला ने हरियाणा विधानसभा के अंतिम दिन बिजली के प्रस्तावित निजीकरण को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। शून्य काल में उन्होंने गुड़गांव और नूंह में समानांतर बिजली लाइसेंस देने की प्रक्रिया का विरोध करते हुए इसे बिजली विभाग के निजीकरण की दिशा में उठाया गया कदम बताया। सुरजेवाला ने कहा कि जिस कंपनी को बिजली वितरण का काम देने की तैयारी है, वह करीब एक साल पुरानी है और उसके पास इस क्षेत्र में कोई अनुभव नहीं है। इसके बावजूद उसे 4717 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट सौंपने की तैयारी सवाल खड़े करती है। उन्होंने कंपनी की महज एक करोड़ रुपए की पूंजी का हवाला देते हुए सरकार से जवाब मांगा। विधायक ने आरोप लगाया कि प्रस्तावित व्यवस्था का फायदा मुख्य रूप से बड़े मॉल, उद्योगों और सोसाइटियों को मिलेगा, जबकि गांवों, ट्यूबवेलों और छोटी दुकानों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि गुड़गांव दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम के राजस्व में करीब 40 प्रतिशत योगदान देता है। ऐसे में राजस्व का बड़ा हिस्सा निजी हाथों में जाने से किसानों, ग्रामीण क्षेत्रों और बिजली उपभोक्ताओं पर असर पड़ सकता है। सुरजेवाला ने आशंका जताई कि निजीकरण से सरकारी कर्मचारियों की नौकरियों और किसानों को मिलने वाली बिजली सुविधाओं पर भी संकट आ सकता है। उन्होंने सरकार से गुड़गांव-नूंह में प्रस्तावित समानांतर बिजली लाइसेंस की प्रक्रिया तत्काल रद्द करने की मांग की। उनकी अचानक मौत से स्कूल के शिक्षक और कर्मचारी सदमे में हैं। जिस समय वह बच्चों के बीच अपनी नियमित जिम्मेदारी निभा रहे थे, उसी दौरान उनकी तबीयत बिगड़ने की घटना ने सभी को झकझोर दिया। हरजीत ग्रेवाल अपने पीछे पत्नी और दो बच्चों को छोड़ गए हैं। उनकी पत्नी गृहिणी हैं। उनका बेटा खेती का काम संभालता है, जबकि बेटी कनाडा में पढ़ाई कर रही है। उनके दो बड़े भाई भी हैं। हेड टीचर की मौत की सूचना मिलते ही परिवार के सदस्य डीएमसी अस्पताल पहुंचे। अचानक और असमय हुई मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। स्कूल के शिक्षकों और कर्मचारियों ने भी उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है।

हाथरस में किसानों का धरना जारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत के आगमन की तैयारी

हाथरस (हिंस)। उत्तर प्रदेश के जनपद हाथरस में सादाबाद तहसील प्रांगण में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर किसानों का धरना लगभग 24 दिनों से जारी है। किसानों का कहना है कि लंबे समय से वे अपनी समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं लेकिन अभी तक उनकी मांगों पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई है। बुधवार को धरना स्थल पर किसानों ने स्वयं साफ-सफाई अभियान चलाया। भारतीय किसान यूनियन राकेश टिकैत के मण्डल उपाध्यक्ष चौधरी चंद्रेश ने बताया कि गुरुवार को किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत तहसील परिसर में पहुंचने वाले हैं। उनके आगमन को लेकर धरना स्थल और आसपास के परिसर की साफ-सफाई की गई है। ताकि कार्यक्रम व्यवस्थित तरीके से आयोजित हो सके। किसानों ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत के सामने वे अपनी सभी प्रमुख समस्याओं और मांगों को रखेंगे। साथ ही, किसानों को उम्मीद है कि उनके राष्ट्रीय नेता सरकार के समक्ष किसानों की समस्याओं को मजबूती से उठाएंगे और मांगों के समाधान के लिए सरकार पर दबाव बनाएंगे। धरने पर बैठे किसानों ने कहा कि वे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज उठा रहे हैं। जब तक उनकी समस्याओं का उचित समाधान नहीं होता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। अब किसानों की निगाहें राकेश टिकैत के आगमन और उनके संबोधन पर टिकी हैं।

टिकट नहीं मिलने पर केंद्रीय मंत्री से मिलकर रोने लगा कार्यकर्ता

जोधपुर (हिंस)। नगर निकाय चुनाव में टिकट नहीं मिलने से परेशान एक कार्यकर्ता बुधवार को जोधपुर एयरपोर्ट पर केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मिलकर रोने लगा। शेखावत ने उन्हें गले लगाया और चुप करवाया। कहा कि अपन को मस्त रहना है। हम सभी को मिलकर संगठन के लिए काम करना है। दरअसल, धन्नाराम चौधरी पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं। संगठन में भी लंबे समय से सक्रिय हैं। इस बार उन्होंने वार्ड नंबर 10 से टिकट मांगा था। लेकिन किन्हीं वजह से उन्हें टिकट नहीं मिला। आज जब केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर पहुंचे तो धन्नाराम भी एयरपोर्ट पहुंच गया। वहां शेखावत को देखते ही धनाराम की आंखों में आंसू आ गए। इस पर उन्होंने धनाराम को गले लगा लिया और उनको ढांढस बंधाते हुए कहा कि सब मिलकर पार्टी को जिंदाबाद बनाएंगे।

टार्गेटेड फाइल सिस्टम के खिलाफ वकीलों को मिला समर्थन

जोधपुर (हिंस)। राजस्थान की न्यायिक व्यवस्था में पेंडिंग और सूचीबद्ध मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए अपनाई जा रही *टार्गेटेड/लिस्टेड फाइल सिस्टम* व्यवस्था को लेकर अधिवक्ताओं का विरोध अब व्यापक रूप लेता जा रहा है। जोधपुर और जयपुर के बाद अब प्रदेश के कई जिलों की बार एसोसिएशन ने न्यायिक कार्यों से दूरी बनाते हुए हड़ताल का ऐलान कर दिया है। जोधपुर की राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन और राजस्थान हाईकोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन की ओर से कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को भेजे गए संयुक्त अभ्यावेदन में लिस्टेड/टार्गेटेड मामलों के शीघ्र निस्तारण के दबाव के कारण न्यायिक अधिकारियों और अधिवक्ताओं की न्यायिक कार्यप्रणाली एवं पारित न्यायिक आदेशों की गुणवत्ता पर पड़ रहे संभावित प्रभाव पर गंभीर चिंता जताई गई है। बार एसोसिएशन द्वारा भेजे गए प्रतिवेदन में तर्क दिया गया है कि किसी मामले का केवल लंबे समय से लंबित होना उसके तत्काल निस्तारण का पर्याप्त आधार नहीं हो सकता। प्रत्येक मामले में तथ्यों, साक्ष्यों, दस्तावेजों, लागू कानून और न्यायिक पहलुओं पर पर्याप्त विचार आवश्यक है। बार एसोसिएशनों ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि अलग-अलग मामलों की प्रकृति और जटिलता अलग होती है। ऐसे में केवल निर्धारित संख्या में मामलों के निस्तारण को न्यायिक कार्य की सफलता का आधार बनाना उचित नहीं है। बार ने जटिल, साक्ष्य-प्रधान और विस्तृत बहस वाले मामलों को केवल लक्ष्य पूरा करने के लिए जल्द निपटाने से न्याय की गुणवत्ता प्रभावित होने की आशंका जताई है। बार एसोसिएशन के अनुसार टार्गेटेड मामलों की वजह से एक ही दिन में अलग-अलग न्यायालयों में बड़ी संख्या में मामलों की सुनवाई के लिए उपस्थित होना पड़ता है। इससे अधिवक्ताओं को प्रत्येक मामले के तथ्यों, दस्तावेजों और कानूनी पहलुओं की पर्याप्त तैयारी तथा प्रभावी बहस के लिए समय नहीं मिल पाता। अभ्यावेदन में यह भी कहा गया है कि लगातार बढ़ते कार्य-दबाव का असर अधिवक्ताओं के वर्क-लाइफ बैलेंस और पेशेवर जीवन पर पड़ रहा है। जोधपुर की दोनों प्रमुख हाईकोर्ट बार एसोसिएशनों ने मुख्य रूप से टार्गेटेड/लिस्टेड मामलों के शीघ्र निस्तारण से संबंधित जारी दिशा-निर्देशों एवं आदेशों पर पुनर्विचार करने, मामलों की संख्या तय करने के बजाय प्रत्येक न्यायालय की वास्तविक कार्यक्षमता और मामलों की प्रकृति को ध्यान में रखने और जटिल, साक्ष्य-प्रधान और विस्तृत बहस वाले मामलों को केवल लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से जल्द निपटाने के लिए बाध्य नहीं करने की मांग की है। इसके साथ ही बार ने अधिवक्ताओं को प्रभावी पैरवी और पर्याप्त तैयारी का अवसर उपलब्ध कराने की मांग करते हुए व्यावहारिक एवं संतुलित व्यवस्था बनाने का अनुरोध किया गया है। जोधपुर बार एसोसिएशन के हड़ताल पर जाने के बाद अब लगातार प्रदेशभर के बार एसोसिएशन भी इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। जोधपुर के बाद बाड़मेर बार एसोसिएशन के निर्णय के अनुसार अधिवक्ताओं ने न्यायिक संस्था की स्वतंत्रता, गरिमा और जनविश्वास की रक्षा के मुद्दे पर विचार-विमर्श के बाद 6 सितंबर तक न्यायिक कार्य से स्वैच्छिक रूप से दूर रहने का निर्णय लिया। वहीं डीआरटी बार एसोसिएशन जयपुर ने डेब्ट्स रिकवरी ट्रिब्यूनल, जयपुर के रजिस्ट्रार को पत्र भेजकर बताया कि जयपुर एवं राजस्थान की अन्य बार एसोसिएशनों के आह्वान के समर्थन में 5 सितंबर तक न्यायिक कार्य से अनुपस्थित रहने का सर्वसम्मत निर्णय लिया है। बुधवार को जालोर जिला बार के अधिवक्ताओं ने भी न्यायिक कार्य का बहिष्कार करते हुए न्यायिक कार्य नहीं किया।

राममंदिर के पहले सीईओ बने पूर्व एयर मार्शल जीतेंद्र मिश्रा, गोविंद देव गिरि महासचिव

अयोध्या (हिंस)। पूर्व एयर मार्शल जीतेंद्र मिश्रा श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) बनाए गए हैं। गोविंद देव गिरि को महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी गयी है। वह अभी कोषाध्यक्ष थे। इसके अलावा ट्रस्ट में एक महिला समेत तीन नए सदस्यों को भी शामिल किया गया है। ट्रस्ट की बुधवार को यहां हुई बैठक के बाद इसकी घोषणा की गयी। तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने एक बयान में बताया कि मिश्रा ने ऑपरेशन सिंदूर में पश्चिमी वायु कमान का नेतृत्व किया था। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के रहने वाले मिश्रा वायुसेना में अपनी 39 साल की सेवा के बाद 30 अप्रैल 2026 को सेवानिवृत्त हुए थे। ट्रस्ट में तीन नए सदस्य भी बनाए गए हैं। इनमें अयोध्या छावनी के निवासी एडवोकेट मदन मोहन पांडेय, दिल्ली के महेश भागचंदका और शिकोहाबाद की रहने वाली डॉ. निर्मला यादव शामिल हैं। निर्मला यादव ट्रस्ट की पहली महिला ट्रस्टी होंगी। भागचंदका को गोविंद देव गिरि के स्थान पर कोषाध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया है। ट्रस्ट के तीन नए सदस्यों में से 74 वर्षीय मदन मोहन पांडेय राम जन्मभूमि के स्वामित्व विवाद मामले में रामलला की ओर से कानूनी पैरवी करने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में राम जन्मभूमि से जुड़े पक्ष की दलीलों में उनकी अहम भूमिका रही। पांडेय उत्तर प्रदेश के छह वर्षों तक अतिरिक्त महाधिवक्ता भी रह चुके हैं। दूसरे सदस्य 68 वर्षीय महेश भागचंदका दिल्ली के कारोबारी हैं। वर्ष 2020 में राम मंदिर के भूमि पूजन और 22 जनवरी 2024 के प्राण-प्रतिष्ठा समारोह में वह यजमान भी रहे थे। स्नातक तक शिक्षा प्राप्त भागचंदका *हिंदुत्व के पुरोधा* पुस्तक के लेखक हैं। वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम की कार्यकारिणी के सदस्य भागचंदका राम वनगमन यात्रा से जुड़े 292 पवित्र तीर्थस्थलों में श्रीराम स्तम्भ की स्थापना कार्य से भी जुड़े रहे हैं। ट्रस्ट की तीसरी सदस्य 66 वर्षीय डॉ. निर्मला यादव शिकोहाबाद की रहने वाली हैं। वह ट्रस्ट की पहली महिला सदस्य हैं। हिंदी और संस्कृत में परास्नातक डॉ. यादव 19 वर्ष तक महाविद्यालय की प्राचार्य रही हैं। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने के बाद दो जुलाई को ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया था। उनके इस्तीफे के बाद रिटायर्ड आईएफएस कृष्ण मोहन को कार्यवाहक महासचिव बनाया गया था। ट्रस्ट ने पिछले दो माह की चुनौतीपूर्ण अवधि में महासचिव पद का कार्यभार सफलतापूर्वक निर्वहन करने के लिए कृष्ण मोहन की सराहना करते हुए उनके प्रति आभार प्रकट किया। ट्रस्ट के मुताबिक बैठक में चढ़ावे की नकद राशि की गणना की प्रक्रिया में मानवीय हस्तक्षेप कम करने के निमित किए जा रहे प्रयासों पर चर्चा हुई। दो बैंकों और आईआईटी से इस संबंध में कुछ प्रस्ताव मिले हैं जिनका मूल्यांकन कर शीघ्र ही तकनीकी सहायता से इस दिशा में प्रगति हो सकेगी। ट्रस्ट ने चयन समिति के सदस्यों- न्यायमूर्ति (सेवानिवृत) प्रमोद कोहली, लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत) विष्णुकांत चतुर्वेदी, सुरेश हावड़े और समिति के सचिव समीर पंडा के प्रति अल्पकाल में साढ़े पांच हजार आवेदनों की जांच और सैकड़ों आवेदकों का साक्षात्कार कर इस कार्य को सम्पन्न करने के लिए आभार व्यक्त किया। ट्रस्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2025-26 में कुल आय 237 करोड़ और व्यय 91 करोड़ रुपए रहा। इनके अतिरिक्त निर्माण आदि कार्यों पर 425 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय हुआ। वर्ष के अंत 31 मार्च 2026 को ट्रस्ट के पास कुल उपलब्ध राशि 1882 करोड़ रुपए थी।

नाबालिग अवस्था में भारत में दाखिल पाकिस्तानी नागरिक को कानूनी प्रक्रिया के बाद पाकिस्तान भेजा गया

फरीदकोट (हिंस)। बिना वैध पासपोर्ट के जून 2024 में फरीदकोट-फिरोजपुर सीमा क्षेत्र से भारत में प्रवेश करने वाले एक पाकिस्तानी नागरिक को बुधवार को आवश्यक कानूनी प्रक्रिया और औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पाकिस्तान वापस भेज दिया गया। भारत में प्रवेश के समय वह नाबालिग था। उसकी स्वदेश वापसी की प्रक्रिया में जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी (डीएलएसए), फरीदकोट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों के तहत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जानकारी के अनुसार, पाकिस्तानी युवक ने जून 2024 में फिरोजपुर सीमा के रास्ते भारतीय क्षेत्र में प्रवेश किया था। इसके बाद उसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, फिरोजपुर के समक्ष पेश किया गया। करीब एक वर्ष बाद 2025 में उसके मामले में फैसला हुआ। हिरासत के दौरान युवक की उम्र 18 वर्ष हो गई, जिसके बाद उसे फरीदकोट स्थित ऑब्जर्वेशन होम के अलग सुरक्षित परिसर में रखा गया। कानूनी सजा पूरी होने और अन्य आवश्यक औपचारिकताएं पूरी किए जाने के बाद विदेश मंत्रालय से स्वदेश वापसी की मंजूरी मिली। इसके बाद डीएलएसए फरीदकोट के चेयरमैन एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय अग्निहोत्री ने युवक की पाकिस्तान वापसी की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। डीएलएसए की सचिव एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) गुरप्रीत कौर की निगरानी में स्वदेश वापसी की पूरी कार्रवाई संपन्न कराई गई। फरीदकोट ऑब्जर्वेशन होम के अधीक्षक और कर्मचारियों ने युवक को सुरक्षा एवं आवश्यक प्रक्रिया के तहत अटारी सीमा तक पहुंचाया। वहां उसे पाकिस्तानी रेंजर्स के हवाले कर दिया गया। स्वदेश रवाना होने से पहले सीजेएम गुरप्रीत कौर ने युवक को मिठाई, फल और कपड़े भी दिए। उन्होंने उसके बेहतर भविष्य की कामना करते हुए उसे भविष्य में किसी भी गैरकानूनी गतिविधि से दूर रहने की सलाह दी। उन्होंने युवक को बिना वैध यात्रा दस्तावेजों के किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार नहीं करने की हिदायत भी दी और कानूनी एवं सुरक्षित तरीके से यात्रा करने के महत्व के बारे में समझाया। फरीदकोट क्षेत्र में यह इस तरह का पहला मामला नहीं है।

ओटीए गयाजी में 5 सितंबर को 29वीं पासिंग आउट परेड, 253 ऑफिसर कैडेट्स होंगे सेना में शामिल

गयाजी (हिंस)। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी (ओटीए), गयाजी 5 सितंबर 2026 को अपनी 29वीं पासिंग आउट परेड आयोजित करने जा रही है। इस अवसर पर शॉर्ट सर्विस कमीशन, टेक्निकल एंट्री (पुरुष)-65वें कोर्स के 218/219 ऑफिसर कैडेट्स और शॉर्ट सर्विस कमीशन, टेक्निकल एंट्री (महिला)-36वें कोर्स की 35 ऑफिसर कैडेट्स अपनी कठिन सैन्य प्रशिक्षण यात्रा पूरी कर पासिंग आउट परेड में हिस्सा लेंगी। समारोह के साथ ही ये प्रशिक्षु देश की सेवा के लिए सैन्य अधिकारी के रूप में नई जिम्मेदारी संभालने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। दो दिवसीय समारोह को यादगार बनाने के लिए ओटीए गयाजी की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इनमें गौरव पदक सम्मान समारोह, पासिंग आउट परेड, पिपिंग सेरेमनी और शपथ ग्रहण समारोह प्रमुख हैं। गौरव पदक सम्मान समारोह के दौरान सिम्फनी बैंड, मल्लखंब, कलारीपयट्टू और गतका जैसे पारंपरिक एवं रोमांचक प्रदर्शन भी आकर्षण का केंद्र होंगे। इन समारोहों में नागरिक गणमान्य व्यक्तियों के अलावा ऑफिसर कैडेट्स के परिजन और अन्य विशिष्ट अतिथि शामिल होंगे। विभिन्न प्रतिष्ठित स्कूलों के विद्यार्थी, नेशनल कैडेट कोर (एनसीसी) की टुकड़ियां और विभिन्न *सेंटर ऑफ एक्सीलेंस* के छात्र भी समारोह में मौजूद रहेंगे। इनकी भागीदारी का उद्देश्य युवाओं में देशभक्ति और राष्ट्रसेवा की भावना को मजबूत करना तथा उन्हें भारतीय सशस्त्र बलों में करियर बनाने के लिए प्रेरित करना है। समर टर्म-2026 के पासिंग आउट समारोहों के क्रम में ओटीए गयाजी के विजय ऑडिटोरियम में कमांडेंट अवार्ड्स सेरेमनी आयोजित की गई। कार्यक्रम में ओटीए गयाजी के कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल संदीप सिंह, अति विशिष्ट सेवा मेडल (एवीएसएम), ने भाग लिया। इस दौरान लेफ्टिनेंट जनरल संदीप सिंह ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले ऑफिसर कैडेट्स को पुरस्कार प्रदान किए। खेल, ड्रिल, घुड़सवारी, शारीरिक प्रशिक्षण, आउटडोर कैंप, सर्विस और अकादमिक विषयों के साथ-साथ हथियार प्रशिक्षण में बेहतर प्रदर्शन करने वाले कैडेट्स को सम्मानित किया गया।

संतान की दीर्घायु के लिए माताओं ने रखा ललही छठ व्रत, तालाब-कुंडों पर उमड़ी भीड़

समूह में एकत्रित होकर महिलाओं ने की हलषष्ठी माता व भगवान बलराम की पूजा, सुनी कथा

वाराणसी (हिंस)। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि पर बुधवार को उत्तर प्रदेश की धार्मिक नगरी वाराणसी में ललही छठ का पर्व आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया गया। संतान की दीर्घायु, सुख-समृद्धि और मंगलकामना के लिए महिलाओं ने निर्जला व्रत रखा। शहर के ईश्वरगंगी तालाब, लक्ष्मीकुंड, लोलार्क कुंड समेत नगर और ग्रामीण क्षेत्रों के तालाबों, पोखरों व कुओं के किनारे व्रती महिलाओं की भीड़ जुटी। महिलाओं ने समूह में पूजा-अर्चना कर हलषष्ठी माता और भगवान बलराम की कथा सुनी। सुबह से ही व्रती महिलाओं ने घरों में पूजा की तैयारी शुरू कर दी थी। महिलाओं ने भैंस के गोबर से पूजा स्थल की दीवार पर हलछठ माता का चित्र बनाया और विधि-विधान से पूजन किया। इसके बाद भगवान गणेश और माता गौरी की भी पूजा की गई। पूजा में नारियल, मिष्ठान, फल-फूल, मेवा, महुआ, कमेर, तिल, गुम का पत्ता, तिन्नी का चावल और दही समेत विभिन्न पूजन सामग्री अर्पित की गई। कई स्थानों पर महिलाओं ने समूह में कुश को जमीन में स्थापित कर उसकी पूजा की। पूजा के बाद कुश और महुआ के पत्तों का पूजन कर उन पर महुआ, तिन्नी का चावल, गुड़ और दही का प्रसाद रखा गया। व्रती महिलाओं ने प्रसाद का वितरण कर अपनी संतानों के दीर्घ जीवन और सुख-समृद्धि की कामना की। वाराणसी के ईश्वरगंगी मोहल्ले की ईश्वरी सिंह, गीता सिंह, अनुपमा तिवारी, ज्योत्सना चौबे और माया यादव ने बताया कि ललही छठ का व्रत पुत्र की दीर्घायु और परिवार की सुख-समृद्धि के लिए रखा जाता है। परिवार में इस पर्व को परंपरागत तरीके से पूरे श्रद्धाभाव के साथ मनाया जाता है। तालाब या कुंड के किनारे हलषष्ठी माता और भगवान बलराम की पूजा करने की परंपरा है। सनातन परंपरा में ललही छठ को भगवान श्रीकृष्ण के बड़े भाई बलराम के जन्म से जोड़कर देखा जाता है। मान्यता है कि भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को बलराम का जन्म हुआ था। इसी कारण इस दिन माताएं व्रत रखकर हलषष्ठी माता की पूजा करती हैं और कथा सुनती हैं। कथा के अनुसार, कंस को जब यह पता चला कि वासुदेव और देवकी की संतान उसके विनाश का कारण बनेगी तो उसने दोनों को कारागार में बंद कर दिया। कंस ने उनकी छह संतानों का वध कर दिया। सातवीं संतान के समय देवकी की रक्षा के लिए नारद मुनि ने उन्हें हलषष्ठी माता का व्रत करने की सलाह दी। देवकी के व्रत के प्रभाव से भगवान की योगमाया ने देवकी के गर्भ में पल रहे सातवें शिशु को रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। बाद में रोहिणी के गर्भ से बलराम का जन्म हुआ, जबकि देवकी के आठवें पुत्र के रूप में भगवान श्रीकृष्ण का जन्म हुआ। मान्यता है कि हलषष्ठी माता के व्रत के प्रभाव से दोनों पुत्रों की रक्षा हुई। ललही छठ से जुड़ी एक अन्य लोककथा में ग्वालिन का प्रसंग आता है। कथा के अनुसार, एक ग्वालिन दूध-दही बेचकर जीवन यापन करती थी। एक बार गर्भवती होने के बावजूद वह दूध बेचने निकली। रास्ते में प्रसव पीड़ा होने पर उसने पेड़ के नीचे पुत्र को जन्म दिया और उसे वहीं सुलाकर दूध बेचने चली गई। उस दिन हरछठ का व्रत था और लोगों को भैंस का दूध चाहिए था। ग्वालिन ने गाय का दूध भैंस का दूध बताकर बेच दिया। इससे हलषष्ठी माता नाराज हो गईं और उसके पुत्र की मृत्यु हो गई। लौटकर ग्वालिन ने पुत्र को मृत पाया तो वह विलाप करने लगी।

वित्त मंत्री सीतारमण ने की विश्व बैंक प्रमुख अजय बंगा से मुलाकात, सहयोग बढ़ाने पर चर्चा

वाशिंगटन

केंद्रीय वित्त एवं कार्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा से मुलाकात कर भारत तथा इस अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था के बीच सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की।

वित्त मंत्रालय ने एक्स पोस्ट में बताया कि सीतारमण ने एशविले में जी20 सदस्य देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर (एफएमसीबीजी) की बैठक से इतर विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा मुलाकात की। वित्त मंत्री ने भारत के साथ वर्ल्ड बैंक ग्रुप के लगातार जुड़ाव की सराहना की और 1.5 अरब डालर की डेवलपमेंट पालिसी फाइनेंसिंग (डीपीएफ) की तेज़ी से प्रोसेसिंग को सराहा।

इस मुलाकात के दौरान सीतारमण ने सिडबी के जरिए एमएसएमई को आईएफसी से मिले सहयोग की भी तारीफ़ की। इस प्रक्रिया को रिकार्ड समय में पूरा किया गया और इसका एमएसएमई सेक्टर पर सकारात्मक असर पड़ा है। दोनों नेताओं ने भारत-वर्ल्ड बैंक समूह की साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। इसमें भारत में एमआईजीए की बड़ी भूमिका पर विचार करना भी शामिल था, ताकि गारंटी के व्यवस्थित इस्तेमाल और प्राइवेट कैपिटल को ज्यादा जुटाकर कार्पोरेट, इंफ्रास्ट्रक्चर और म्युनिसिपल बान्ड मार्केट को गहरा किया जा सके।

वित्त मंत्रालय ने बताया कि बातचीत में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्रेडिट बढ़ाने के वास्ते सेक्टर-आधारित, प्रोग्राम-आधारित अप्रोच पर भी चर्चा हुई। बंगा ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में आए बड़े बदलाव की सराहना की और भारत के विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए वर्ल्ड बैंक ग्रुप के साधनों का और फ़ायदा उठाने के मौकों पर ध्यान दिया। इसमें एमआईजीए की भागीदारी और विदेशों में निवेश करने वाली भारतीय कंपनियों के लिए पालिटिकल रिस्क इंश्योरेंस शामिल है।

वित्त मंत्री सीतारमण ने भारत में ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर नालेज हब बनाने के लिए वर्ल्ड बैंक ग्रुप के साथ भारत के जुड़ाव पर भी जोर दिया। इसमें खेती जैसे क्षेत्रों में टेक्नोलाजी का फायदा उठाने के मौकों पर विचार करना शामिल है। उन्होंने इसके लान्च की दिशा में जल्द प्रगति की उम्मीद जताई।

इसके अलावा सीतारमण ने नए भारत-वर्ल्ड बैंक ग्रुप कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत विश्व-स्तरीय टूरिज्म डेस्टिनेशन विकसित करने पर भी चर्चा की। इसके लिए आईबीआरडी की पालिसी और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, आईएफसी के निवेश और एमआईजीए की गारंटी को मिलाकर एक समन्वित अप्रोच अपनाने की बात हुई।

मंत्रालय के मुताबिक दोनों नेताओं ने साझेदारी को पारंपरिक कर्जदाता-उधारकर्ता रिश्ते से आगे बढ़ाकर ग्लोबल नालेज, इनोवेशन और प्राइवेट कैपिटल जुटाने के एक रणनीतिक प्लेटफार्म के रूप में विकसित करने पर भी चर्चा की। इसमें भारत के बड़े पैमाने और लागू करने की क्षमता को वर्ल्ड बैंक समूह की ग्लोबल विशेषज्ञता और फाइनेंसिंग साधनों के साथ जोड़ा जाएगा।

न्यूज ब्रीफ

जोमैटो ने एनालाग डेयरी उत्पादों की बिक्री पर लगाई रोक

मुंबई। फूड डिलीवरी प्लेटफार्म जोमैटो ने एनालाग डेयरी उत्पादों से बनी डिश की बिक्री पर रोक लगा दी है। खाद्य नियामक एफएसएसएआई की कई रेस्टोरेंट के खिलाफ हालिया कार्रवाई के बाद जोमैटो ने जीरो-टालरेंस पालिसी अपनाकर प्लेटफार्म पर लिस्टेड उन सभी खाद्य पदार्थों को हटा लिया है जिन्हें पार्टनर्स ने एनालाग डेयरी आधारित बताया था। कंपनी ने स्पष्ट किया कि इस कदम का मुख्य उद्देश्य ग्राहकों के लिए पारदर्शिता सुनिश्चित करना और परोसे जा रहे भोजन की गुणवत्ता बेहतर करना है। जोमैटो ने चेतावनी भी दी है कि जो रेस्टोरेंट पार्टनर्स नई शर्तों को पूरा नहीं करते, उन्हें प्लेटफार्म से हटाया जा सकता है। नई पालिसी के तहत, रेस्टोरेंट पार्टनर्स को अब प्राकृतिक डेयरी उत्पादों का ही उपयोग करना होगा। जो रेस्टोरेंट तुरंत ऐसा नहीं कर सकते, उन्हें निर्देश दिया गया है कि वे एनालाग डेयरी वाले आइटम को अपने मैन्यू से हटा दें। इसके अतिरिक्त, रेस्टोरेंट से आपूर्तिकर्ताओं द्वारा दिए गए प्रोडक्ट लेबल और सामग्री की जानकारी की गंभीरता से जांच करने को कहा गया है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जोमैटो पर लिस्टेड प्रोडक्ट्स की जानकारी पूरी तरह सही और वास्तविक सामग्री के अनुरूप हो। जोमैटो के सीईओ आदित्य मंगला ने कहा, हमारा मुख्य मकसद अधिक से अधिक लोगों तक बेहतर खाना पहुंचाना है।

उदारीकरण की दहलीज पर मुंबई, बदलाव का शुरुआती दौर, उदारीकरण और यूएलसी ने बदल दी मुंबई की तस्वीर, कैसे बंदरगाह शहर बना वित्तीय राजधानी

नई दिल्ली। वर्ष 1991 में देश में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत ने मुंबई जैसे महानगरों के लिए परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया। कभी बंदरगाह आधारित अर्थव्यवस्था और कपड़ा मिलों का गढ़ रहा यह शहर, सुधारों की बयार में एक नए वित्तीय केंद्र और कभी न सोने वाले शहर के रूप में उभरा। इस बदलाव की कहानी केवल आर्थिक नीतियों तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसमें भूमि उपयोग कानूनों में संशोधन और शहरी जमीन सीमा अधिनियम (यूएलसी) का उन्मूलन जैसे अहम कारक भी शामिल थे। उदारीकरण से पहले ही मुंबई बदलाव के मुहाने पर खड़ा था। यह शहर अपनी बंदरगाह आधारित अर्थव्यवस्था और विनिर्माण केंद्र के लिए जाना जाता था, लेकिन सेवा क्षेत्र की ओर कदम बढ़ा रहा था। तब यह काफी हद तक सरकारी नियम-कायदे की जद में था। 1991 के आर्थिक सुधारों ने इस बदलाव की गति को असाधारण रूप से तेज कर दिया।

किआ सोरेंटो की नई एसयूवी 4 सितंबर को होगी लान्च

नई दिल्ली। भारतीय बाजार में किआ सोरेंटो की नई प्रमुख एसयूवी के रूप में 4 सितंबर को लान्च होने जा रही है। मजबूत हाइब्रिड संस्करण में 1.6 लीटर इंजन दिया जाएगा, जो 238 हार्सपावर की ताकत और 380 न्यूटन मीटर का अधिकतम टार्क पैदा करेगा। यह एसयूवी मजबूत हाइब्रिड और डीजल, दोनों इंजन विकल्पों के साथ उतारी जाएगी। वहीं, 2.0 लीटर डीजल इंजन 202 हार्सपावर की ताकत और 441 न्यूटन मीटर का टार्क देगा, जिससे यह परफार्मेंस के मामले में भी काफी दमदार होगी। सोरेंटो के बाहरी डिजाइन में किआ की सिग्नेचर टाइगर नोज ग्रिल प्रमुखता से दिखेगी। इसके साथ बड़े और सीधे आकार के एलईडी हेडलैंप दिए गए हैं, जिनमें वाई-आकार की एलईडी डे-टाइम रनिंग लाइट्स मिलती हैं। आगे की तरफ एलईडी फाग लैंप और बंपर के किनारों पर वर्टिकल एयरो वेंट भी दिए गए हैं, जो इसकी स्पोर्टी अपील को बढ़ाते हैं। कंपनी ने अभी मिश्रधातु पहियों का आकार आधिकारिक तौर पर नहीं बताया है, लेकिन इसमें 19 इंच के आकर्षक पहिए मिलने की संभावना है। पीछे की तरफ चौकोर आकार के टेल-लैंप, उल्टे एल-आकार की एलईडी लाइट सिग्नेचर, एक बड़ा रूफ स्पायलर और दो रंगों वाला बंपर डिजाइन इसे आधुनिक और प्रीमियम लुक देता है। केबिन के अंदर भी सोरेंटो को एक आधुनिक और शानदार रूप दिया गया है। सामने की तरफ एक जुड़ा हुआ डिस्प्ले पैनल दिया गया है, जिसमें मनोरंजन प्रणाली और चालक सूचना प्रणाली के लिए दो बड़ी स्क्रीन शामिल हैं।

भारत में सेमीकंडक्टर क्रांति को मिलेगा बल, सरकार ने अधिसूचित की सेमीकान 2.0 योजना

सिलिकान फैब को 40 और अन्य सेमीकंडक्टर को 35 फीसदी पूंजीगत व्यय पर मिलेगी वित्तीय सहायता

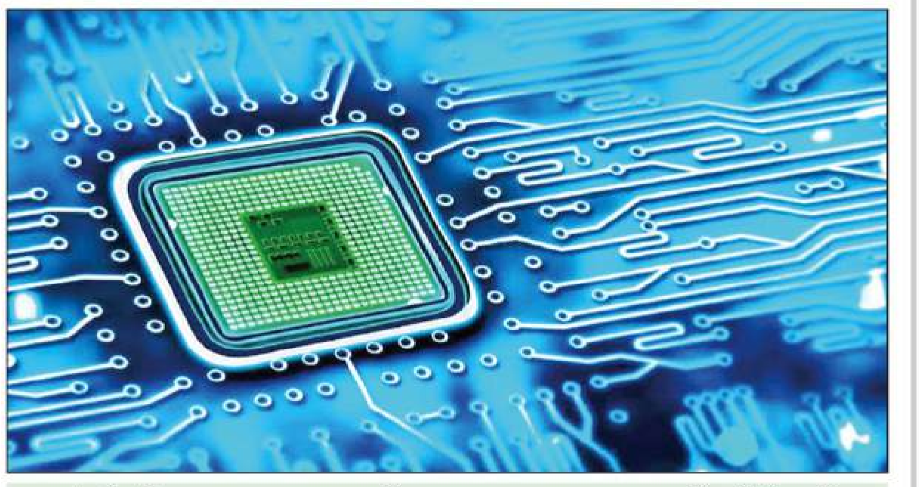

नई दिल्ली

भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर हब बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी सेमीकान 2.0 योजना को अधिसूचित कर दिया है। यह योजना देश में चिप डिजाइन, सेमीकंडक्टर निर्माण, उपकरण और सामग्री विकास, उन्नत पैकेजिंग, शोध एवं विकास (आरऐंडडी) और प्रतिभा विकास से जुड़ी परियोजनाओं को व्यापक पात्रता मानदंड और वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।

केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इस साल जुलाई में 1,27,500 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ स्वीकृत की गई यह योजना छह प्रमुख स्तंभों और 10 श्रेणियों पर आधारित है। नए दिशानिर्देशों के तहत सिलिकान वेफर फैब (निर्माण संयंत्र) को उनके पात्र पूंजीगत व्यय के 40 प्रतिशत तक की वित्तीय सहायता मिलेगी।

इस सहायता के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु, एक 300-मिमी सिलिकान फैब में प्रति माह कम से कम 40,000 वेफर स्टार्ट्स की स्थापित क्षमता होनी चाहिए। साथ ही, न्यूनतम 20,000 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश आवश्यक होगा और आवेदन से पहले के तीन वित्त वर्षों में से कम से कम एक में 7,500 करोड़ रुपये का न्यूनतम राजस्व दर्ज करना होगा। कंपाउंड सेमीकंडक्टर, फोटोनिक्स, सेंसर और डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर फैब संयंत्रों के लिए, वित्तीय सहायता पात्र पूंजीगत व्यय के 35 प्रतिशत पर निर्धारित की गई है। इन संयंत्रों के लिए न्यूनतम पूंजी निवेश की सीमा 500 करोड़ रुपये है। दिशानिर्देशों में सेंसर/एमईएमएस फैब के लिए न्यूनतम 200 मिमी, कंपाउंड और डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर फैब के लिए 150 मिमी और फोटोनिक्स अनुप्रयोगों के लिए 100 मिमी वेफर आकार तय किए गए हैं। उद्योग विशेषज्ञों ने सरकार के इस कदम का गर्मजोशी से स्वागत किया है।

हुंडई की 2030 तक भारत में 26 नए माडल लान्च करने की तैयारी

नई दिल्ली। जापानीज कार निर्माता हुंडई कंपनी 2030 तक भारत में 26 नए माडल लान्च करने की तैयारी में है, जिसमें नई क्रेटा भी शामिल होगी। हुंडई अपनी सबसे लोकप्रिय एसयूवी क्रेटा के नेक्स्ट-जेनरेशन माडल पर काम कर रही है, जो अगले साल यानी 2027 में भारतीय बाजार में दस्तक दे सकती है। इस अपडेटेड माडल में डिजाइन, इंटीरियर और इंजन विकल्पों में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, जिससे यह मौजूदा माडल से काफी अलग और आधुनिक प्रतीत होगी। स्पाई शाट्स के अनुसार, नई क्रेटा में नए फ्रंट और रियर बंपर, नए डिजाइन के अलाय व्हील, बदले हुए हेडलैंप और टेल-लैंप जैसे बाहरी बदलाव होंगे। इसके अलावा, नए ओआरवीएमएस और क्वार्टर पैनल में भी संशोधन अपेक्षित हैं। केबिन के भीतर भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, जिसमें नया डैशबोर्ड, नई फ्रंट सीट्स, नया अपहोल्स्ट्री डिजाइन और एक कर्व्ड स्क्रीन सेटअप प्रमुख होंगे। उम्मीद है कि इसमें फ्रंट पैसेंजर सीट पर बास मोड और हुंडई का नया प्लोस टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम भी मिलेगा, जो भारत में इस साफ्टवेयर की शुरुआत करेगा और बेहतर कनेक्टिविटी व यूजर इंटरफेस प्रदान करेगा। इंजन स्पेसिफिकेशन्स की जानकारी अभी कंपनी ने साझा नहीं की है, लेकिन मौजूदा इंजन विकल्पों के साथ पहली बार हाइब्रिड पावरट्रेन को भी शामिल किए जाने की संभावना है। इससे एसयूवी को बेहतर माइलेज और शहर में कम ईंधन खपत का लाभ मिलेगा। यह निसान टेक्टान और टाटा सिएरा जैसी आगामी कारों को चुनौती देगी।

मारुति सुजुकी का 77,500 करोड़ रुपये का मेगा निवेश

मुंबई

मारुति सुजुकी इंडिया ने अगले पांच वर्षों में (वित्त वर्ष 2027 से 2031 तक) अपने कारोबार विस्तार और उत्पादन क्षमता में वृद्धि के लिए 77,500 करोड़ रुपये के बड़े पूंजीगत खर्च की योजना तैयार की है। यह राशि पहले घोषित योजना से करीब 29 से 30 फीसदी अधिक है, जो भारतीय वाहन बाजार में कंपनी के मजबूत विश्वास को दिखाता है।

इस विशाल निवेश का उपयोग उत्पादन क्षमता विस्तार, नए वाहनों के विकास, शोध एवं विकास (आरएंडटी), संयंत्रों के रखरखाव और देश भर में बिक्री नेटवर्क को मजबूत करने जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में होगा। कंपनी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हिसाशी ताकेउची ने बताया कि वित्त वर्ष 2027 में ही करीब 14,000 करोड़ रुपये का पूंजीगत खर्च किया जाएगा, जो बीते वित्त वर्ष से करीब 40 फीसदी अधिक है।

7 नई एसयूवी के साथ उत्पादन क्षमता बढ़ाने पर जोर

वर्तमान में, हरियाणा के खरखौदा और गुजरात के हंसलपुर में विस्तार के बाद मारुति सुजुकी की सालाना उत्पादन क्षमता करीब 29 लाख वाहन हो गई है। कंपनी का लक्ष्य गुजरात के साणंद में एक नया संयंत्र स्थापित कर चरणबद्ध तरीके से क्षमता को 40 लाख वाहनों तक पहुंचाना है। कंपनी का ध्यान तेजी से बढ़ते एसयूवी (स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल) बाजार पर भी केंद्रित है। अगले पांच वर्षों में सात नए एसयूवी माडल पेश करने की योजना है, जिसके माध्यम से कंपनी सेगमेंट में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती है। नए संयंत्रों में उत्पादन व्यवस्था को अधिक लचीला बनाया जाएगा, जिससे एक ही लाइन पर इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड, सीएनजी और पेट्रोल-डीजल इंजन वाले वाहन तैयार किए जा सकें। इस निवेश का एक हिस्सा कार्बन उत्सर्जन कम करने, लाजिस्टिक्स, विपणन, बिक्री ढांचे और शोध एवं विकास पर भी खर्च होगा। हालांकि, कच्चे माल और वाहन कलपुर्जों की बढ़ती लागत तथा पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष जैसे कारक कंपनी के लिए लागत दबाव बढ़ा रहे हैं। इसके बावजूद, यह बड़ा निवेश भारतीय वाहन बाजार में लंबी अवधि की मांग और सतत वृद्धि को लेकर मारुति सुजुकी के दृढ़ संकल्प और भरोसे को रेखांकित करता है।

एथर एनर्जी जल्द लांच करेगी अपना नया इलेक्ट्रिक स्कूटर कोनार्क

नई दिल्ली। आगामी 29 अगस्त को एथर एनर्जी कंपनी बेंगलुरु में अपना नया इलेक्ट्रिक स्कूटर कोनार्क लान्च करने जा रही है। कोनार्क को एथर के बिल्कुल नए ईएल प्लेटफार्म पर तैयार किया गया है, जो इस प्लेटफार्म पर निर्मित होने वाला पहला माडल है। यह वाहन कंपनी के पोर्टफोलियो में एक महत्वपूर्ण विस्तार होगा, जिसका उद्देश्य व्यापक ग्राहक वर्ग तक अपनी पहुंच बनाना है। कंपनी ने इसके उत्पादन के लिए छत्रपति संभाजीनगर में एक नई निर्माण इकाई भी स्थापित की है। एथर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने इस उपलब्धि को हीरो मोटोकार्प के अध्यक्ष पवन मुंजाल के साथ साझा किया, जिन्होंने 2016 में शुरुआती चरण में ही इसमें निवेश किया था। कोनार्क धातु यानी मेटल बाडी के साथ बाजार में आएगा, जिसकी बनावट मजबूत और दैनिक उपयोग के लिए अनुकूल होगी। इसका डिजाइन पारिवारिक जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिसमें हैंडलबार पर मुख्य लाइट, एक लंबी व सपाट सीट और सामान रखने के लिए समतल फुटबोर्ड जैसी सुविधाएं हैं। इसमें दो से पांच किलोवाट-घंटा क्षमता तक के बैटरी विकल्प मिल सकते हैं, जो एक बार चार्ज होने पर 100 से 150 किलोमीटर तक की दूरी तय करने में सक्षम होगा। लागत नियंत्रण और मजबूती के लिए इसमें एलएफपी बैटरी तकनीक का उपयोग होने की संभावना है।

सर्राफा बाजार में गिरावट जारी, सोना और चांदी की घटी कीमत

नई दिल्ली

सर्राफा बाजार में शुरुआती कारोबार के दौरान जबरदस्त गिरावट का रुख बना हुआ नजर आ रहा है। चेन्नई के अलावा देश के ज्यादातर हिस्सों में सोना 2,090 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 2,680 रुपये प्रति 10 ग्राम तक सस्ती हो गई है। वहीं चेन्नई में सोने की कीमत 1,950 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 2,130 रुपये प्रति 10 ग्राम तक गिर गई है। चांदी भी ज्यादातर सर्राफा बाजार में 5,000 रुपये प्रति किलोग्राम तक सस्ता हो गया है।

भाव में बदलाव होने की वजह से देश के ज्यादातर सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना 1,54,080 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 1,54,630 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह 22 कैरेट सोना 1,41,240 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 1,41,740 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच बिक रहा है। चांदी के भाव में भी गिरावट आने के कारण ये चमकीली धातु दिल्ली सर्राफा बाजार में शुरुआती कारोबार में 2,49,900 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर बिक रही है।

दिल्ली में 24 कैरेट सोना 1,54,230 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 1,41,390 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 24 कैरेट सोना 1,54,080 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,41,240 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। इसी तरह अहमदाबाद में 24 कैरेट सोने की रिटेल कीमत 1,54,130 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत 1,41,290 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है।

इन प्रमुख शहरों के अलावा चेन्नई में 24 कैरेट सोना 1,54,630 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर और 22 कैरेट सोना 1,41,740 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर बिक रहा है। इसी तरह कोलकाता में 24 कैरेट सोना 1,54,080 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,41,240 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। भोपाल में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,54,130 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है, जबकि 22 कैरेट सोना 1,41,290 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है।

जयपुर में 24 कैरेट सोना 1,54,230 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,41,390 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। पटना में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,54,130 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है, जबकि 22 कैरेट सोना 1,41,290 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। लखनऊ के सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना 1,54,230 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर और 22 कैरेट सोना 1,41,390 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है।

ग्लोबल मार्केट से कमजोरी के संकेत, एशिया में भी बिकवाली का दबाव

नई दिल्ली

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में आई तेजी, अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में बढ़ोतरी और पश्चिम एशिया में लगातार बढ़ते तनाव की वजह से दुनिया भर के ज्यादातर शेयर बाजार में न्यूनतम जोखिम पर काम करने का माहौल बना हुआ है। पूरी दुनिया में ज्यादातर निवेशक सतर्क मुद्रा में कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। इसकी वजह से ग्लोबल मार्केट से कमजोरी के संकेत मिल रहे हैं।

वैश्विक दबाव की वजह से अमेरिकी बाजार पिछले सत्र के दौरान गिरावट के साथ बंद हुए। डाउ जान्स फ्यूचर्स भी मामूली कमजोरी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। यूरोपीय बाजार में भी पिछले सत्र के दौरान लगातार बिकवाली का दबाव बना रहा। इसी तरह एशियाई बाजार में भी चौतरफा बिकवाली होती हुई नजर आ रही है।

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और उसकी वजह से अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहे निगेटिव इफेक्ट की वजह से अमेरिकी बाजार में पिछले सत्र के दौरान निवेदक जोखिम लेने से बचते हुए नजर आए। निवेशकों की सतर्कता की वजह से वाल स्ट्रीट के सूचकांक गिरावट के साथ लाल निशान में बंद हुए। एस एंड पी 500 इंडेक्स 0.71 प्रतिशत टूट कर 7,631.47 अंक के स्तर पर बंद हुआ। इसी तरह नैस्डेक ने 271.11 अंक यानी 1.03 प्रतिशत लुढ़क कर 26,099.77 अंक के स्तर पर पिछले सत्र के कारोबार का अंत किया। वहीं डाउ जान्स फ्यूचर्स फिलहाल 0.01 प्रतिशत की सांकेतिक कमजोरी के साथ 52,762.66 अंक के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है।

यूरोपीय बाजार में भी पिछले सत्र के दौरान लगातार दबाव बना रहा। एफटीएसई इंडेक्स 0.32 प्रतिशत की गिरावट के साथ 10,789.28 अंक के स्तर पर बंद हुआ। इसी तरह सीएसी इंडेक्स ने 0.39 प्रतिशत फिसल कर 8,301.85 अंक के स्तर पर पिछले सत्र के कारोबार का अंत किया। इसके अलावा डीएएक्स इंडेक्स 288 अंक यानी 1.11 प्रतिशत टूट कर 25,970.11 अंक के स्तर पर बंद हुआ। एशियाई बाजार में भी लगातार बिकवाली हो रही है। एशिया के सभी नौ बाजार के सूचकांक दबाव में कारोबार कर रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी 117 अंक यानी 0.49 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 23,934 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह जकार्ता कंपोजिट इंडेक्स 0.15 प्रतिशत लुढ़क कर 6,589.98 अंक के स्तर पर पहुंचा हुआ है। कोस्पी इंडेक्स में जबरदस्त गिरावट आई है। यह सूचकांक फिलहाल 256.23 अंक यानी 3.75 प्रतिशत टूट कर 6,579.57 के स्तर पर आ गया है। इसी तरह निक्केई इंडेक्स भी जबरदस्त कमजोरी का शिकार हो गया है। फिलहाल यह सूचकांक 1,962.34 अंक यानी 2.96 प्रतिशत फिसल कर 64,253 अंक के स्तर पर पहुंचा हुआ है। इसके अलावा ताइवान वेटेड इंडेक्स 716.29 अंक यानी 1.53 प्रतिशत की गिरावट के साथ 46,232.43 अंक के स्तर पर आ गया है।

वहीं हैंग सेंग इंडेक्स 276.73 अंक यानी 1.10 प्रतिशत लुढ़क कर 25,053 अंक के स्तर पर पहुंचा हुआ है। इसके अतिरिक्त शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.82 प्रतिशत टूट कर 3,947.26 अंक के स्तर पर, सेट कंपोजिट इंडेक्स 0.78 प्रतिशत फिसल कर 1,576.23 अंक के स्तर पर और स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.02 प्रतिशत की मामूली गिरावट के साथ 5,709.051 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहे हैं।

अनाहत-रमित लंदन स्क्वाश क्लासिक के प्री-क्वार्टर फाइनल में :11 मिनट में जीतीं अनाहत; वीर चोतरानी को स्विट्ज़रलैंड के खिलाड़ी ने हराया

लंदन

लंदन में खेले जा रहे लंदन स्क्वाश क्लासिक में भारत की अनाहत सिंह और रमित टंडन प्री-क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। वर्ल्ड नंबर-20 अनाहत ने मिस्र की 30वें नंबर की मरियम मेटवाली को सिर्फ 11 मिनट में 11-3, 11-2 से हराया।

वहीं, 42वें नंबर के रमित ने कतर के 61वें नंबर के अब्दुल्ला अल-तमीमी को 20 मिनट में 11-6, 11-7 से मात दी। हालांकि, 38वें नंबर के वीर चोतरानी को स्विट्जरलैंड के यैनिक विल्हेमी के खिलाफ 9-11, 9-11 से हार मिली।

अनाहत ने 11 मिनट में जीता मुकाबला

अनाहत ने मरियम मेटवाली के खिलाफ शुरुआत से ही दबाव बनाए रखा। उन्होंने पहला गेम 11-3 से जीता और दूसरे गेम में सिर्फ दो अंक गंवाते हुए 11-2 से मुकाबला अपने नाम कर लिया। मैच खत्म करने में उन्हें केवल 11 मिनट लगे। अब प्री-क्वार्टर फाइनल में अनाहत का सामना बेल्जियम की दुनिया की 11वें नंबर की खिलाड़ी नेले गिलिस से होगा। यह मुकाबला गुरुवार को खेला जाएगा।

अनाहत ने हाल ही में जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब जीतकर इतिहास रचा था। वह यह खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनी थीं।

रमित ने 20 मिनट में अल-तमीमी को हराया

पुरुष एकल में रमित टंडन ने अब्दुल्ला अल-तमीमी को 11-6, 11-7 से हराया। 20 मिनट चले मुकाबले में रमित ने दोनों गेम अपने नाम किए और अगले दौर में जगह बनाई।

प्री-क्वार्टर फाइनल में रमित का सामना टूर्नामेंट के आठवें वरीयता प्राप्त मोहम्मद एलशोरबागी से होगा। मिस्र में जन्मे एलशोरबागी अब इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व करते हैं।

वीर चोतरानी दो गेम में हारे

भारत के वीर चोतरानी को पहले दौर में दुनिया के 34वें नंबर के खिलाड़ी यैनिक विल्हेमी ने 11-9, 11-9 से हराया। दोनों गेम में मुकाबला करीबी रहा, लेकिन स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी ने दोनों गेम में 11 अंक पूरे कर मैच जीत लिया। अनाहत और वीर दोनों आगामी एशियन गेम्स के लिए भारत के स्क्वैश दल का हिस्सा हैं। एशियन गेम्स जापान के आइची-नागोया में होंगे।

न्यूज़ ब्रीफ

चाइना मास्टर्स: विक्टर लाई से सीधे गेम में हारकर लक्ष्य सेन हुए बाहर

नई दिल्ली। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन का चाइना मास्टर्स में अभियान समाप्त हो गया। राउंड आफ 32 के मुकाबले में लक्ष्य को कनाडा के विक्टर लाई के खिलाफ सीधे गेम में 14-21, 7-21 से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ विक्टर

लाई के खिलाफ लक्ष्य सेन का इस साल का रिकार्ड और खराब हो गया है। दोनों के बीच 2026 में खेले गए चार मुकाबलों में लाई ने तीन बार जीत दर्ज की है। उन्होंने थामस कप और जुलाई में चाइना ओपन के राउंड आफ 16 में भी लक्ष्य को हराया था। हालांकि, दोनों के बीच इस साल पहली भिड़ंत में लक्ष्य ने जीत दर्ज की थी। मार्च में आल इंग्लैंड ओपन के सेमीफाइनल में लक्ष्य ने लाई को तीन गेम तक चले मुकाबले में 21-16, 18-21, 21-15 से हराया था। लक्ष्य सेन के लिए यह लगातार दूसरा निराशाजनक टूर्नामेंट रहा। नई दिल्ली में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में उन्हें दूसरे दौर में अमेरिका के गैरेट टैन के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। चाइना मास्टर्स में उन्हें शुरुआत में फ्रांस के एलेक्स लानियर के खिलाफ खेलना था, लेकिन दिल्ली में खिताब जीतने के बाद लानियर के हटने से लक्ष्य का सामना एक बार फिर लाई से हुआ। श्रीकांत की शानदार जीत दिन के पहले मुकाबले में किदांबी श्रीकांत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ची यू-रेन को 21-16, 21-15 से हराकर राउंड आफ 16 में जगह बनाई। श्रीकांत ने पहले गेम में दबदबा बनाया और दूसरे गेम में भी संयम बरतते हुए मुकाबला अपने नाम किया। यू-रेन ने 2023 में सैयद मोदी इंटरनेशनल में अपना पहला बीडब्ल्यूएफ खिताब जीता था और उसी टूर्नामेंट में उन्होंने श्रीकांत को पहले दौर में हराया था। इस बार श्रीकांत ने हिसाब बराबर कर लिया।

डोपिंग में फंसे ईरानी पैरा एथलीट जावनमर्दी, आईपीसी ने लगाया तीन साल का प्रतिबंध

बान (जर्मनी)। अंतरराष्ट्रीय पैरालंपिक समिति (आईपीसी) ने ईरान के पैरा एथलीट सैयद अलीअसगर जावनमर्दी पर डोपिंग मामले में तीन साल का प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही नई दिल्ली में आयोजित 2025 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुष शाट पुट एफ35 स्पर्धा में जीता उनका स्वर्ण पदक भी रद्द कर दिया गया है। जावनमर्दी के दो मूत्र नमूनों में प्रतिबंधित पदार्थ आक्सांड्रोलोन पाया गया था। पहला नमूना 22 सितंबर 2025 को ईरान की राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (ईरान नाडो) ने प्रतियोगिता से बाहर लिया था, जबकि दूसरा नमूना 24 सितंबर को नई दिल्ली में विश्व चैंपियनशिप के दौरान आईपीसी ने लिया था। दोनों नमूनों में मिले परिणामों को एक ही डोपिंग रोधी नियम उल्लंघन (एडीआरवी) माना गया। आक्सांड्रोलोन विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (वाडा) की 2025 प्रतिबंधित सूची में एनाबालिक एंड्रोजेनिक स्टेरायड की श्रेणी में शामिल है। आईपीसी ने 28 अक्टूबर 2025 को मामले का अंतिम फैसला आने तक जावनमर्दी को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया था।

मेसी की कमाई के सामने दूर-दूर तक नहीं टिकते क्रिकेटर

बार्सिलोना। अर्जेंटीना के महान फुटबालर लियोनल मेसी ने अचानक ही खेल से संन्यास लेकर सभी को हैरान कर दिया है। मेसी ने मैदान में जिस तेजी से गोल किये हैं। उसी तेजी से अपने दो दशक के करियर में कमाई भी की है। वह विश्व के सबसे धनी खिलाड़ियों में से एक है। फुटबाल दुनिया के

सबसे लोकप्रिय और देखे जाने वाले खेलों में से एक है, और इसमें शीर्ष खिलाड़ियों को भारी भरकम राशि मिलती है और ये क्रिकेटरों को मिलने वाले रकम से कई गुना अधिक है या यूं कहें तो स्टार क्रिकेटर जितनी रकम अपने करियर में कमा पाते है उतनी तो दिग्गज फुटबालर एक साल में ही कमा लेते हैं। ऐसे में मेसी जैसे दिग्गज खिलाड़ी की उनकी कमाई और संपत्ति कितनी होगी इसके अनुमान लगाये जा सकते है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मेसी की अनुमानित नेटवर्थ वर्तमान में लगभग 1.1 अरब डालर है। भारतीय मुद्रा में यह आंकड़ा 10,450 करोड़ रुपये के करीब बैठता है। यह राशि उनके पिछले दो दशकों के शानदार करियर और खेल जगत में उनके अद्वितीय प्रभाव को दिखाती है। केवल उनकी कुल संपत्ति ही नहीं, बल्कि उनकी सालाना कमाई भी जानकार आप हैरान हो जाएंगे। फोर्ब्स की 2026 की सूची के अनुसार, मेसी विश्व के तीसरे सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीट थे, जिनकी सालाना आय 140 मिलियन डालर बताई गई थी।

माया बाउचियर के शतक से इंग्लैंड ने रचा इतिहास, आयरलैंड के खिलाफ छह विकेट से दर्ज की जीत

लीसेस्टर

सलामी बल्लेबाज माया बाउचियर के शानदार शतक की बदौलत इंग्लैंड ने आयरलैंड के खिलाफ एकदिवसीय क्रिकेट में अपना सबसे बड़ा सफल रन चेज पूरा किया। इंग्लैंड ने 282 रन के लक्ष्य को महज 38.1 ओवर में चार विकेट खोकर 283 रन बनाकर हासिल कर लिया और छह विकेट से मुकाबला अपने नाम किया। आयरलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 5 विकेट पर 281 रन बनाए थे। जवाब में बाउचियर ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 95 गेंदों पर 104 रन की शानदार पारी खेली। उनकी पारी में 11 चौके शामिल रहे। बाउचियर ने सोफिया डंकली के साथ दूसरे विकेट के लिए 118 गेंदों में 143 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी की। डंकली ने 61 गेंदों पर 73 रन बनाए। दोनों ने इंग्लैंड को शुरुआत से ही मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया।

डंकली ने 40 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, जबकि बाउचियर ने 53 गेंदों में पचास रन पूरे किए। दोनों की तेज बल्लेबाजी से इंग्लैंड ने 10 ओवर में बिना विकेट खोए 72 रन बना लिए थे।

आयरलैंड की कारा मरे ने 20वें ओवर में डंकली को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ा। इसके बाद उन्होंने अगले ओवर में जोडी ग्रेकाक को भी पवेलियन भेजा। हालांकि, बाउचियर और एलिस कैप्सी ने 50 रन की साझेदारी कर इंग्लैंड की जीत की राह आसान कर दी।

बाउचियर ने 31वें ओवर में 91 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया, लेकिन अगले ही ओवर में मरे ने उन्हें आउट कर दिया। इसके बाद फ्रेया केम्प ने 22 गेंदों पर 36 रन की तेज पारी खेलकर आयरलैंड की उम्मीदें पूरी तरह खत्म कर दीं। कैप्सी ने नाबाद 41 रन बनाए और चौका लगाकर इंग्लैंड को रिकार्ड लक्ष्य तक पहुंचा दिया।

आयरलैंड की मजबूत शुरुआत

इससे पहले आयरलैंड ने गैबी लुईस और एमी हंटर की शानदार बल्लेबाजी के दम पर मजबूत स्कोर खड़ा किया। दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 152 गेंदों में 136 रन की साझेदारी की। लुईस ने 69 और हंटर ने 62 रन बनाए।

30वें ओवर के बाद आयरलैंड ने 7.1 ओवर के भीतर तीन विकेट गंवा दिए थे और उसका स्कोर 250 रन के आसपास पहुंचने पर भी संशय था। लेकिन लिया पाल और रेबेका स्टोकल ने 71 गेंदों में 84 रन की साझेदारी कर पारी को संभाला। स्टोकल 54 रन बनाकर नाबाद रहीं।

आयरलैंड ने अंतिम 10 ओवर में 77 रन जोड़कर इंग्लैंड के सामने 282 रन का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखा, लेकिन बाउचियर की तूफानी पारी के सामने यह स्कोर भी छोटा साबित हुआ।

संक्षिप्त स्कोर:

आयरलैंड: 281/5 (50 ओवर) — गैबी लुईस 69, एमी हंटर 62, रेबेका स्टोकल नाबाद 54; चार्ली डीन 2/44, इस्सी वोंग 2/57।

इंग्लैंड: 283/4 (38.1 ओवर) — माया बाउचियर 104, सोफिया डंकली 73, एलिस कैप्सी नाबाद 41; कारा मरे 3/58।

परिणाम: इंग्लैंड छह विकेट से विजयी।

यूएस ओपन: राइबाकिना, गाफ, कीज और एंड्रीवा की दमदार जीत, दूसरे दौर में पहुंचीं

न्यूयार्क

विश्व की नंबर दो खिलाड़ी एलेना राइबाकिना, पूर्व चैंपियन कोको गाफ, मैडिसन कीज और फ्रेंच ओपन चैंपियन मिर्रा एंड्रीवा ने शानदार जीत दर्ज करते हुए यूएस ओपन के दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया।

तीसरी ग्रैंड स्लैम ट्राफी और विश्व नंबर एक रैंकिंग पर नजरें लगाए राइबाकिना ने अमेरिका की थिया फ्राडिन को 6-3, 6-2 से हराया। कजाकिस्तान की राइबाकिना ने मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया और दोनों ब्रेक प्वाइंट बचाए।

राइबाकिना के लिए यह जीत खास रही, क्योंकि इसी महीने सिनसिनाटी में क्वार्टर फाइनल मुकाबले से उन्हें बाएं पैर की चोट के कारण हटना पड़ा था। चोट के बाद वापसी करते हुए उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया और अपनी फिटनेस को लेकर उठ रही चिंताओं को भी दूर किया। राइबाकिना, कोको गाफ और जेसिका पेगुला उन तीन खिलाड़ियों में शामिल हैं, जो न्यूयार्क में आर्यना सबालेंका से विश्व नंबर एक की रैंकिंग छीन सकती हैं। गाफ को इसके लिए अपना दूसरा यूएस ओपन खिताब जीतना होगा, जबकि राइबाकिना सेमीफाइनल में पहुंचकर भी शीर्ष रैंकिंग हासिल कर सकती हैं।

गाफ ने सर्विस से किया प्रभावित

2023 की यूएस ओपन चैंपियन कोको गाफ ने तुर्किये की दुनिया की 53वें नंबर की जेनेप सोनमेज को 6-3, 6-4 से हराया। गाफ ने अपनी बेहतर हुई सर्विस का शानदार इस्तेमाल किया और शुरुआती सेट में दबदबा बनाया।

एंड्रीवा ने भी आसान जीत दर्ज की

फ्रेंच ओपन चैंपियन और पांचवीं वरीयता प्राप्त मिर्रा एंड्रीवा ने इंडोनेशिया की 36वें नंबर की जेनिस तिएन को 6-2, 6-2 से हराकर दूसरे दौर में जगह बनाई।

कीज भी दूसरे दौर में

मैडिसन कीज ने रूसी किशोरी अलीना कोर्नेएवा को 7-5, 6-4 से हराया। कीज ने मुकाबले में 21 विनर्स लगाए और अब दूसरे दौर में चेक गणराज्य की लूसी हव्लिचकोवा या हंगरी की अन्ना बोंदार से भिड़ेंगी।

घरेलू क्रिकेट में बेहतर प्रदर्शन कर टीम में वापसी करना चाहते हैं ऋतुराज

कोयंबटूर। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान और युवा बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ का कहना है कि उनका ध्यान केवल रन बनाने पर है। वह जानते हैं कि घरेलू टूर्नामेंटों में बेहतर प्रदर्शन के आधार पर ही वह भारतीय टीम में वापसी करने में सफल होंगे। इसी कारण उनका ध्यान अपनी लय बनाये रखने पर रहेगा। गायकवाड़ ने कहा, मुझे वापसी का पूरा भरोसा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुझे धैर्य बनाए रखते हुए आने वाले मुकाबलों में जमकर रन बनाने होंगे। इस सलामी बल्लेबाज ने कहा, मैं पिछले कुछ साल से लगातार रन बना रहा हूं और मुझे ये सिलसिला आगे भी बनाये रखते हुए अवसर का इंतजार करना है। गायकवाड़ के इस बयान से साफ है कि वह घरेलू क्रिकेट में वापसी का कोई अवसर नही छोड़ेगें। इस बल्लेबाज ने कहा कि मैच के दिन टीम का हिस्सा न होने पर भी राष्ट्रीय टीम के लिए उनका समर्थन हमेशा बना रहता है। इस क्रिकेटर ने कहा कि आप अपने देश का समर्थन ही करना चाहेंगे। अब घरेलू सत्र नजदीक आने के साथ, गायकवाड़ का ध्यान तेजी से खेल की ओर केंद्रित हो रहा है। उन्होंने संकेत दिया कि व्यस्त कार्यक्रम और तैयारी के कारण वह भारतीय के हर मैच पर बारीकी से नजर नहीं रख पाते हैं।

यूएस ओपन: 40वें जन्मदिन पर मोनफिल्स ने दर्ज की शानदार जीत, कोबोली और फ्रिट्ज भी दूसरे दौर में

न्यूयार्क

फ्रांस के अनुभवी टेनिस खिलाड़ी गेल मोनफिल्स ने अपने 40वें जन्मदिन पर शानदार वापसी करते हुए यूएस ओपन के दूसरे दौर में जगह बना ली। बारिश से बाधित मुकाबलों और रोमांचक मुकाबलों से भरे दिन में मोनफिल्स के अलावा फ्लावियो कोबोली और टेलर फ्रिट्ज ने भी अपने-अपने मुकाबले जीतकर अगले दौर में प्रवेश किया।

मोनफिल्स ने एडोल्फो डेनियल वालेहो को 2-6, 6-1, 6-2, 6-0 से हराया। इस जीत के साथ उनका विदाई ग्रैंड स्लैम अभियान जारी है। शुरुआत में पिछड़ने के बाद मोनफिल्स ने शानदार वापसी की और लुई आर्मस्ट्रांग स्टेडियम में मौजूद दर्शकों से जमकर तालियां बटोरीं।

मोनफिल्स फ्लशिंग मीडोज में मुख्य ड्रा का एकल मुकाबला जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी भी बन गए हैं। उन्होंने 1992 में अपने 40वें जन्मदिन पर जीत दर्ज करने वाले जिमी कानर्स की उपलब्धि की बराबरी की। कोर्ट पर केक तो नहीं आया, लेकिन मैच के बाद दर्शकों ने मोनफिल्स के लिए जन्मदिन का गीत गाया। मैच के बाद मोनफिल्स ने कहा, अपने 40वें जन्मदिन पर खेलना मेरे लिए बेहद खास था। आप सभी ने इसे अविश्वसनीय बना दिया। माहौल शानदार था और मैंने भी अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश की।

दो सेट से पिछड़ने के बाद कोबोली की शानदार वापसी

पांचवीं वरीयता प्राप्त इटली के फ्लावियो कोबोली ने अर्जेंटीना के फ्रांसिस्को कोमेसेना के खिलाफ दो सेट से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी की। कोबोली ने चार घंटे 13 मिनट चले मैराथन मुकाबले में 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, 6-4 से जीत दर्ज की।

यह पहली बार था जब कोबोली ने अपने करियर में दो सेट से पिछड़ने के बाद मुकाबला जीता। निर्णायक सेट में उन्होंने शुरुआती ब्रेक गंवाने के बाद

वापसी की, फिर 5-4 की बढ़त हासिल कर मैच अपने नाम कर लिया। उन्होंने शानदार फोरहैंड वाली के साथ मुकाबला समाप्त किया। कोबोली ने कहा, ग्रैंड स्लैम में मुकाबला कभी खत्म नहीं होता। आपको आखिरी अंक तक संघर्ष करना पड़ता है।

फ्रिट्ज ने दमदार सर्विस से आसान की राह

अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज ने हमवतन डार्विन ब्लांच को 6-3, 6-2, 6-4 से हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। 2024 में उपविजेता रहे फ्रिट्ज ने 18 वर्षीय वाइल्ड कार्ड खिलाड़ी के खिलाफ 14 ऐस लगाए। फ्रिट्ज अब दूसरे दौर में इटली के मत्तिया बेलुच्ची का सामना करेंगे। उन्होंने मैच एक ऐसी सर्विस के साथ समाप्त किया, जिसे ब्लांच वापस नहीं कर सके।

पुजारा ने अपनी पसंदीदा टीम में इन तीन दिग्गजों को शामिल नहीं किया

मुम्बई

पूर्व टेस्ट क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा ने अपनी पसंदीदा अंतिम ग्यारह टीम घोषित की है। पुजारा ने इस टीम में उन्हीं खिलाड़ियों को शामिल किया है। जिनके साथ उन्होंने अपने करियर में खेला था। पुजारा ने साल 2010 से 2023 तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 103 टेस्ट मैचों में 7195 रन बनाए। उन्होंने हालांकि पांच एकदिवसीय मैच भी खेले पर वह इस प्रारुप में आगे नहीं खेल पाये। पुजारा ने अपने दौर की टीम के , पांच वर्तमान खिलाड़ियों और छह पूर्व दिग्गजों को अपनी पसंदीदा टीम में शामिल किया है पर हैरानी की बात ये है कि उनकी इस टीम में तीन दिग्गज खिलाड़ियों महेन्द्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा और अजिंक्य रहाणे के नाम नहीं हैं।

इस टीम में पुजारा ने केवल उन्हीं खिलाड़ियों को रखा है जिनके साथ उन्होंने अपने 13 साल के करियर में खेला था। सलामी बल्लेबाज के तौर पर उन्होंने राहुल द्रविड़ और वीरेंद्र सहवाग को

रखा है। द्रविड़ ने साल 1996 से 2012 तक भारत के लिए 13265 टेस्ट रन बनाए, और आक्रामक बल्लेबाज वीरेन्द्र सहवाग के साथ उन्होंने साल 2001 से 2013 तक 103 टेस्ट में 8503 रन बनाये। पुजारा ने अपनी इस टीम में खुद को अपनी पसंदीदा तीसरे नंबर पर रखा है। मध्यक्रम में उन्होंने महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को चौथे और विराट कोहली को पांचवें नंबर पर रखा है। वहीं छठे नंबर पर पुजारा ने वीवीएस लक्ष्मण को चुना, जो अजिंक्य रहाणे की जगह लेते दिख रहे हैं। यह फैसला थोड़ा आश्चर्यजनक है क्योंकि पुजारा ने अपने टेस्ट करियर में काफी समय तक रहाणे के साथ खेला। वहीं विकेटकीपर के रूप में पुजारा ने महेंद्र सिंह धोनी के बजाय युवा ऋषभ पंत को तरजीह दी है, जिसकी वजह आस्ट्रेलिया में इस बल्लेबाज के साथ उनकी कुछ यादगार साझेदारियां बताई जाती हैं। गेंदबाजी में उन्होंने दो स्पिनरों रवींद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन को शामिल किया है। तेज गेंदबाज के तौर पर उन्होंने जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी को रखा है। पुजारा ने ईशांत शर्मा को 12वें खिलाड़ी के रूप में रखा और कहा कि परिस्थितियों को देखते हुए वे तीन तेज गेंदबाजों के साथ भी जा सकते हैं। उन्होंने यह भी जोड़ा कि यदि तेज गेंदबाजी आलराउंडर की जरूरत पड़ी तो हार्दिक पांड्या उनकी सूची में शामिल हो सकते हैं। इस चयन से यह स्पष्ट है कि पुजारा ने उन खिलाड़ियों को प्राथमिकता दी है जिनके साथ उन्होंने मैदान पर और बाहर गहरा संबंध साझा किया और जिनके खेल से वह व्यक्तिगत रूप से प्रभावित रहे।

पुजारा की अंतिम ग्यारह : राहुल द्रविड़, वीरेंद्र सहवाग, चेतेश्वर पुजारा, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, वीवीएस लक्ष्मण, ऋषभ पंत, रवींद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी।

मोशन सिकनेस से छुटकारा पाने के घरेलू उपाय

मोशन सिकनेस कोई बीमारी नहीं है बल्कि शरीर के संतुलन को महसूस करने से जुड़ी समस्या है। वह स्थिति है जब हमारे दिमाग को भीतरी कान, आंख और त्वचा से अलग-अलग सिग्नल मिलते हैं यह सेंट्रल नर्वस सिस्टम को दुविधा में डाल देता है, जिससे सिर चकराने लगता है और उबकाई आती है, यानी मोशन सिकनेस हावी हो जाती है। मसलन, कार में ट्रैवलिंग के वक्त आपके कान रफ्तार का संदेश दें और आंखें किताब पढ़ने का। हालांकि कुछ घरेलू उपाय की मदद से इसे ठीक किया जा सकता है।

किसे होता है?

हम में से तकरीबन हर कोई जीवन में कभी न कभी मोशन सिकनेस को महसूस करता ही है। यह समस्या छोटे-बच्चों या बढ़ती उम्र के लोगों को ज्यादा होती है। हालांकि भीतरी कान की संवेदना कई मामलों में अनुवांशिक होती है, इसलिए कुछ परिवारों को मोशन सिकनेस ज्यादा परेशान करता है।

मोशन सिकनेस की पहचान

मोशन सिकनेस होने पर उबकाई आ सकती है या फिर अपच, ज्याद पसीना आना, असहज महसूस होना, चेहरा पीला पड़ना और सिर चकराना आदि हो सकते हैं। यह समस्या सफर की शुरुआत से लेकर कुछ घंटों तक रहती है। कुछ मामलों में यह 2 से 4 दिन तक भी रह सकती है।

क्या है इसका इलाज

आमतौर पर मोशन सिकनेस के लिए एंटी हिस्टामाइन दवाइयां दी जाती हैं, जिससे भीतरी कान की संवेदना कम हो जाती है। यह दवाइयां तभी काम करती हैं, जब इसे मोशन सिकनेस शुरू होने से पहले यानी सफर से पहले ले लिया जाए।

अदरक

कहीं सफर करने से पहले एक कप अदरक की चाय पीने से मोशन सिकनेस के कारण आने वाली उल्टी नहीं होती हैं। साथ ही मतली होने पर भी एक कप अदरक चाय से आराम मिलता है।

सेब साइडर सिरका

सेब साइडर सिरका शरीर पर एक क्षारीय और पीएच संतुलन प्रभाव डालता है। मोशन सिकनेस होने पर एक कप गुनगुने पानी में एत चम्मच सेब साइडर सिरका और एक चम्मच शहद मिलाकर पीने से, मोशन सिकनेस ठीक हो जाती है।

पेपरमिंट

पेपरमिंट मोशन सिकनेस की समस्या से तुरंत निजात दिलाता है। पुदीना में मौजूद मेन्थॉल पेट की मांसपेशियों को शांत करता है और मतली को कम करने तथा मोशन सिकनेस की समस्या को दूर करने में मदद करता है।

नींबू

ताजे नींबू या ताजे नीबू के रस में साइट्रिक एसिड होता है, जो यात्रा के दौरान होने वाली उल्टी, मोशन शिकनेस और नाजुक पेट को ठीक कर सकता है। यहां तक की नींबू का खशबू भी दिमाग की मदद से इस समस्या में राहत दिला सकती है।

ग्रीन एप्पल

ग्रीन एप्पल (हरे सेब) में मौजूद पेक्टिन पेट में मौजूद एसिड को बेअसर करने में मदद करता है और इसके कारण हो रही मोशन सिकनेस की समस्या से राहत दिलाता है। इसके अलावा हरे सेब में पाई जाने वाली प्राकृतिक शर्करा पेट को ठईक रखने में मदद करती है।

सौल्ट क्रैकर्स

क्रैकर्स आसानी से पचने वाला नाश्ता होते हैं और पेट के लिए भी बहुत ही अच्छे होते हैं। नमकीन और सुगंधित और बिना मीठे वाले ये क्रैकर्स अतिरिक्त एसिड को सोख लेते हैं और मोशन सिकनेस को रोकने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं।

समझें चूड़ियों के संकेत, वो शुभ हैं तो अशुभ भी

भारत में महिलाओं द्वारा चूड़ियां पहनने की परंपरा काफी पुरानी है। आज के समय में भी इनका बहुत ज्यादा महत्व है और एक महिला के जन्म से लेकर मृत्यु तक इनकी भूमिका रहती है। कुछ धर्मों में तो बच्ची के पैदा होने के साथ ही उसे शगुन के तौर पर चांदी के कंगन पहना दिए जाते हैं। चूड़ियां कई प्रकार की होती हैं और हर एक का एक अपना महत्व है। सबसे पहले चूड़ियों का संदर्भ शादीशुदा स्त्रियों से जोड़कर देखा जाता है। एक विवाहित स्त्री के लिए चूड़ियां केवल श्रृंगार की वस्तु या फिर आभूषण नही हैं, बल्कि इसके पीछे कई सारे कारण हैं। शादी के बाद स्त्रियों को सोने से बने कंगनों से अधिक कांच की चू?ियां पहनने के लिए कहा जाता है। इसके पीछे मान्यता है कि कांच की चूड़ियां पहनने से पति और बेटे का स्वास्थ्य बेहतर रहता है। अगर हम इसके वैज्ञानिक कारणों के बारे में जाने तो चूड़ियां पहनने से महिला के आसपास के वातावरण और स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। चूड़ियां वातावरण में से नकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर खींचती हैं इसके साथ ही यह स्त्री के विभिन्न शारीरिक अंगों पर एक अलग सा दबाव बनती है जिससे उनका स्वास्थ्य बेहतर रहता है।

रहे सावधान ये नकारात्मक भी साबित हो सकती है

आपने चूड़ियों के फायदों के बारे में तो जान लिया लेकिन इसके वितरीत प्रभाव के बारे में जानना भी जरूरी है। ऐसा तब होता है जब चूड़ियां टूटती हैं या फिर उनमें दरार आ जाती है। ऐसी मान्यता है कि चूड़ियों का टूटना उस स्त्री या उससे जुड़े लोगों के लिए एक अशुभ संकेत लेकर आता है। चूड़ियों के टूटने के साथ उनमें दरार आ जाना ही अशुभ माना जाता है। ऐसा होने पर स्त्री को चूड़ियां उतार देने की सलाह दी जाती है क्यों कि ऐसा माना जाता है कि दरार आने पर भी अगर चूड़ियों को उतारा न जाए तो महिला के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

चार्जिंग के समय हो जाता है फोन गरम तो बड़े काम के हैं ये टिप्स

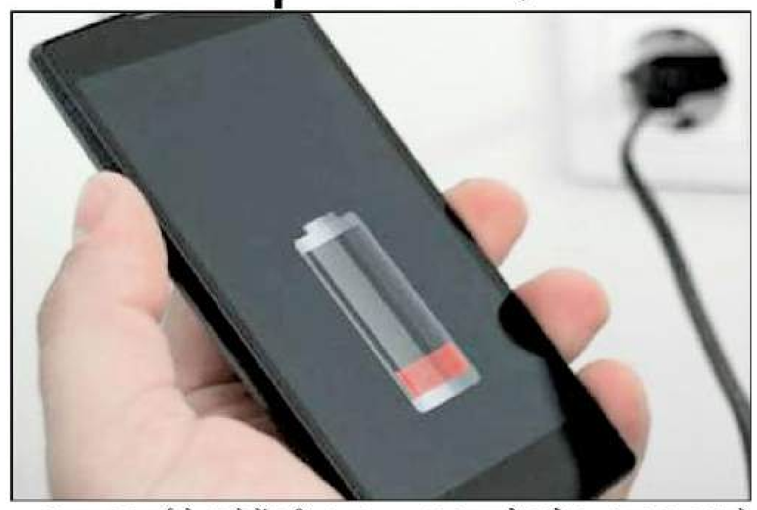

आजकल स्मार्टफोन लोगों की अहम जरूरतों में से एक हो गया है। स्मार्टफोन के बिना न लोगों की सुबह होती है, न रात। कुछ लोगों की ऐसी भी आदत होती है की वो अपने स्मार्टफोन को हमेशा कंप्यूटर से कनेक्ट कर के रखते हैं। ऐसा करने से आपके समर्टफोन में वायरस आने की आशंका और बढ़ जाती है। इसके साथ ही आपके स्मार्टफोन की बैटरी भी खराब होती है।

ऐसी ही कई बातें हैं जिनपर स्मार्टफोन की सुरक्षा और बेहतर परफॉरमेंस के लिए हमें ध्यान देना चाहिए। जैसे कि स्मार्टफोन को चार्ज होने के बाद चार्जिंग से तुरंत हटा लेना चाहिए। ऐसा न करने पर फोन में जल्द ही हीटिंग से सम्बंधित परेशानियां आने लगती हैं।

अगर आपका स्मार्टफोन भी चार्ज होते वक्त गर्म हो जाता है, तो इसका समाधना हम इस पोस्ट में देने वाले हैं। ऐसे कई तरीकें हैं जिससे स्मार्टफोन को तेजी से चार्ज किया जा सकता है। यह तरीके आपके स्मार्टफोन को किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और फोन को हीट भी नहीं होने देंगे।

1. ओरिजिनल चार्जर- अपने स्मार्टफोन को उसी चार्जर से चार्ज करें जो फोन के साथ आता है। अगर वो चार्जर खराब हो गया है, तो किसी डुप्लीकेट चार्जर का इस्तेमाल करने के बजाय ओरिजिनल चार्जर ही खरीदें। इसी के साथ यूनिवर्सल चार्जर से भी मोबाइल चार्ज ना करें। कई बार हम किसी भी चार्जर से अपना मोबाइल चार्ज करने लगते हैं, यह गलत है और ऐसा करने से बचें।

2. फोन का कवर हटा दें- फोन का कवर हटाने से भी हीटिंग की परेशानी से बचा जा सकता है। इसका मतलब की आपका स्मार्टफोन जल्दी भी चार्ज होगा और चार्जिंग के समय ज्यादा गर्म भी नहीं होगा।

3. एयरप्लेन मोड- अगर आप अपने स्मार्टफोन का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो कोशिश करें की उसे एयरप्लेन मोड पर रखें। एयरप्लेन मोड पर फोन जल्दी भी चार्ज होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एयरप्लेन मोड पर आपका डाटा और कॉल्स काम नहीं करती। इसी के साथ फोन को ऑफ कर के चार्ज करने से भी फोन बहुत जल्दी चार्ज हो जाता है।

4. पावर सेविंग मोड- अगर आप अपने मोबाइल को ऑफ नहीं करना चाहते तो उसे पावर सेविंग मोड पर डाल दें। पावर सेविंग मोड फीचर को इनेबल करने से ऑपरेटिंग सिस्टम की सभी प्रक्रियाएं काम करना बंद कर देंगी। पावर टर्न ऑन करने पर आपको कोई नोटिफिकेशन भी नहीं मिलेगी।

5. कुछ फीचर्स को करें बंद- जब भी आप अपना मोबाइल चार्ज करें, तो ऐसे सभी फीचर्स को बंद कर दें जो ज्यादा बैटरी खपत करती है। इससे भी हीटिंग की समस्या से निजात मिलेगा।

6. बैटरी सेविंग मोड को रखें ऑन- स्मार्टफोन को चार्ज करते समय हमेशा यह बात ध्यान रखें की बैटरी सेविंग मोड को ऑन रखें। इससे आपके फोन की बैटरी लाइफ बढ़ेगी।

7. SB पोर्ट चार्जिंग का ना करें प्रयोग- हम अपना स्मार्टफोन चार्ज करने के लिए कभी-कभी यूएसबी पोर्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं। इससे स्मार्टफोन की चार्जिंग स्पीड पर बुरा असर पड़ता है।

8. सही टेम्परेचर पर करें चार्ज- सही टेम्परेचर से फोन की बैटरी चार्जिंग कैपेसिटी में कमी आती है। ऐसी स्थिति में बैटरी कंजम्पशन ज्यादा होता है। अगर जरुरी ना हो तो फोन के गर्म होने पर बैटरी चार्ज ना करें, इससे फोन की बैटरी लाइफ बढ़ेगी।

बच्चे की शैतानियां करें हदें पार तो ऐसे करें डील

बच्चे शैतान नहीं होते हैं, दरअसल बचपन में उनका दिमाग व्यवस्थित नहीं होता है और वो अपने आस पास के तौर तरीकों से वाकिफ नहीं होते। परिणामस्वरुप वो ऐसी हरकते करते हैं जो उन्हें समझ नहीं आती और वो आपको गुस्सा दिला जाती हैं। बच्चों की शैतानी की हद से पार होने लगे तो ट्राय कीजिए ये टिप्स..

1) शैतानियों पर गुस्सा करते हुए भी गुस्से पर कंट्रोल करना मुश्किल होता है। ये जरूरी है क्योंकि आपकी एक ऊंची आवाज और आपकी डांट उन्हें अंदर से डरा कर रख देती है। इसके बदले बेहतर ये होगा कि आप एक गहरी सांस लें और कूल माइंड से इससे डील करने की कोशिश करें।

2) अक्सर पैरेंट्स उन्हें बिना कुछ सोचे समझे थप्पड़ लगा देते हैं जो तार्किक नहीं है। ऐसा करने से आप उस समय तो बच्चे को धमका कर अपने कंट्रोल में कर सकते हैं लेकिन इसका लॉन्गटर्म प्रभाव उल्टा पड़ता है, और आगे के लिए अच्छा नहीं होता।

3) बच्चे स्पॉन्ज की तरह कोमल होते हैं। वे सभी कुछ अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वैसे ही बिहेवियर उनके व्यवहार में भी रिफ्लैक्ट होने लगता है। वे आपका गुस्सा, आपका स्ट्रेस और टेम्पर सभी को एब्जॉर्ब करके वैसा ही रिएक्ट करना शुरु कर देते हैं। इसलिए उनके सामने सोच समझ कर अपनी फीलींग्स को जाहिर करें।

बच्चों को उनके सवाल पूछने के आदत से कभी रोकें नहीं। उन्हें घर पर होने वाले सेविंग और खर्च का पूरा नॉलेज होना चाहिए। उन्हे उनके अपने बजट को लेकर भी सजग और जागरुक होने को कहें। दस वर्ष पूरा कर लेने पर धीरे धीरे उनसे ये बातें शेयर करनी शुरु कर देनी चाहिए।

4) बच्चों पर कभी अपनी मर्जी थोपें नहीं। अगर आप हमेशा अपनी मर्जी के मुताबिक चीजें सोचते रहेंगें तो इसका उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

5) बहुत सारे पैरेंट्स की ये चिंता रहती है कि वे अपने बच्चों के साथ स्ट्रिक्ट रुप से पेश आते हैं तो वे उन्हें पसंद नहीं करते हैं। लेकिन इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। आपको कभी-कभी उनके साथ अनुशासन बना कर चलना ही पड़ेगा। ऐसे ही वे सही और गलत के बीच फर्क को समझ पायेंगे। याद रखें कि आप उनके पेरेंट्स हैं, उनके दोस्त नहीं। इस बात से आहत ना हों कि वे आप पर कमेंट करते हैं कि आप कूल नहीं हो या आप नाइस नहीं हो।

वाटर डिटॉक्स रेसिपी से दुरुस्त करें लिवर

अगर आपके लिवर में कोई समस्या हो गई है और आपका इम्युन सिस्टम खराब हो गया है तो रोज सुबह इन डिटॉक्स वाटर में से कोई एक ड्रिंक पिएं। आराम मिलेगा।

लिवर की समस्या

शरीर का सबसे जरूरी हिस्सा है - लिवर। यह पेट के दाईं ओर नीचे की तरफ होता है। शरीर की अधिकत्तर बीमारियां यही नियंत्रित करता है। इस के बीमार पड़ने पर शरीर पूरी तरह से क्षमतावीहिन हो जाता है। इसलिए लिवर डैमेज होने पर इलाज कराना जरूरी होता है। नहीं तो यह गंभीर समस्या बन जाती है। इसलिए धूमपान और नशा करने से दूर रहना चाहिए। लेकिन कई बार नशा ना करने के बावजूद भी लीवर खराब हो जाता है। ऐसा गलत खानपान की वजह से होता है। ऐसे में इन पेय पदार्थों में से किसी एक का सेवन करें और लीवर को साफ व हेल्दी रखें।

नैचुरल बैली स्लीमिंग डिटॉक्स वाटर

ये आपके शरीर में चर्बी इकट्ठा होने नहीं देगा और आपके बैली को छरहरा रखने में मदद करेगा। साथ ही इससे आपका शरीर पूरे दिन डिहाइड्रेट रहेगा। इसे बनाने के लिए एक ग्लास को पानी से भरे और उसमें खीरा, नींबू, संतरा और पुदीने के पत्ते को डालकर फ्रिज में रख दें। एक घंटे बाद इस इस पानी को पिएं। खीरे में सिट्रोलाइन एमिनो एसिड होता है जो आपके लीवर में से अमोनिया को बाहर निकालता है।

एप्पल सिनेमन डिटॉक्स वाटर

एक रोज सेब खाओ और डॉक्टर को दूर भगाओ!! ये वाक्य शत-प्रतिशत सत्य है और आपके लिवर को भी सेब पसंद है। सेब में मेलिक एसिड होता है जो लिवर में से गंदगी को साफ करने में कारगर होता है। मेलिक एसिड लिवर के फंक्शन और स्मूथ बनाने में भी मदद करता है। एप्पल सिनेमन डिटॉक्स वाटर लिवर के साथ शरीर को भी साफ और हाइड्रेट रखने में मदद करता है। एक कंटेनर में एप्पल का जूस निकाल लें और उसमें दालचीनी के टुकड़े डालें। अब इसे फ्रिज या ठंडी जगह में पंद्रह से तीस मिनट के लिए रख दें।

ग्रेपफ्रूट वाटर

ग्रेपफ्रूट में प्रचूर मात्रा में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो लिवर को साफ कर उसे बूस्ट करने में मदद करता है और इसकी सबसे अच्छी बात है कि इसे बनाना भी बहुत आसान है। इसे बनाने के लिए आपको केवल एक बड़ा सा ग्रेपफ्रूट लीजिए और उसके छोटे-छोटे टुकड़े कर लीजिए और मिक्सी में पीस लीजिए। अब रोज सुबह आधा ग्लास ग्रेपफ्रूट जूस लें और उसमें आधा ग्लास पानी मिला दीजिए। अब इस ग्रेपफ्रूट वाटर को पी लीजिए।

जिंजर साइएन लेमन डिटॉक्स वाटर

अदरक की गिनती सबसे हेल्दी रेसिपी में होती है। ये पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है और शरीर में गैस बनने नहीं देता। आप अदरक को खा भी सकते हैं और अदरक को पानी में गर्म करके पी भी सकते हैं। खैर यहां हम जिंजर साइएन लेमन डिटॉक्स वाटर की बात कर रहे हैं जो लिवर को साफ करता है। ये बनाने के लिए एक बर्तन में पानी गर्म करें और उसमें चार नींबू के रस मिलाएं। अब इसमें अदरक को कद्दूकस करके डालें। फिर दो चुटकी लाल मिर्च मिलाएं। अब 15 मिनट इसे पकने दें। फिर हल्का ठंडा होने पर इसे पी लें। इससे आपका इम्युन सिस्टम भी बूस्ट होगा।

मुद्रक एवं प्रकाशक राकेश शर्मा द्वारा अजय त्यागी के लिए ईको प्रिंटिंग प्रेस, पोस्ट एवं पीएस : गड़चुक, कटाबाड़ी मस्जिद के पास, कामरूप (मेट्रो), गुवाहाटी-35 से मुद्रित एवं **गुड लक पब्लिकेशंस, हाउस नं. 30, डी. नेउग पथ, डोना प्लैनेट के नजदीक, एबीसी, जीएस रोड गुवाहाटी-5 से प्रकाशित।**
संपादक : राकेश शर्मा, मोबाइल : 94350-14771, 97070-14771 ● **कार्यकारी संपादक : प्रदीप शील ● सहयोगी संपादक : रवि शंकर चौधरी ● फोन : 0361-2960054 (संपादकीय)** e-mail : viksitbharatsamacharghy@gmail.com, **(सभी विवाद सिर्फ गुवाहाटी न्याय क्षेत्र के अधीन)**